ट्रंप दबाव के समक्ष मोदी संकल्प की परीक्षा

देश को धीरे-धीरे समझ आने लगा है कि भारतीय कृषि व डेरी क्षेत्र में अमेरिकी उत्पाद खपाने के लिये ही डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ आंतक फैला रहे हैं। यही वजह है कि पहले संयम दिखाने के बाद भारत ने निरंकुश ट्रंप सरकार को चेता दिया है कि भारतीय किसानों व दुग्ध उत्पादकों के हितों की बलि नहीं दी जा सकती। हमारे लिये यह देश की एक बड़ी कृषि व डेरी उद्योग से जुड़ी आबादी के जीवन-यापन का भी प्रश्न है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप द्वारा अतार्किक टैरिफ बढ़ाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने देश के किसानों को आश्वस्त किया है कि उनके हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार,प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के मौके पर उनका यह बयान और महत्वपूर्ण व प्रासंगिक हो जाता है। कृतज्ञ राष्ट्र स्वीकार करता है कि स्वामीनाथन के हरित क्रांति में योगदान से भारत खाद्यान्न की कमी से उबरकर आज खाद्यान्न अधिशेष वाला राष्ट्र बन गया है। बहरहाल, यह तय हो गया है कि भारत वाशिंगटन के उन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए खड़ा हो गया है, जिनके तहत अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों से कम टैरिफ के साथ भारत के बाजार को पाटना चाहता है। निस्संदेह, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों कृषि, डेरी फार्मिंग और मत्स्य पालन से जुड़े करोड़ों लोगों की आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता सराहनीय है। हालांकि, इस दृढ़ संकल्प की परीक्षा ट्रंप शासन द्वारा ली जाएगी। जो भारत द्वारा रूस से सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय राजनीति में किसान उत्पादक व उपभोक्ता से इतर बड़ा राजनीतिक घटक भी है। ऐसे में जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी कृषक समुदाय को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहेंगे। इसमें दो राय नहीं कि विगत में भी किसान असंतोष को राजनीतिक हथियार बनाने में विपक्ष ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। खासकर केंद्र सरकार ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ वर्ष 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर साल भर चले किसान आंदोलन से कड़वा सबक सीखा है। किसान लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर डटे रहे थे। जिसके बाद अंततः इन विवादास्पद कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। इस बीच आंदोलन में किसानों ने अपने अनेक साथियों को खोया था। दरअसल, आंदोलनकारी किसानों की एक मुख्य मांग- विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की थी। कृषि संगठनों के साथ लंबी चली कई दौर की बातचीत के बावजूद एमएसपी मुद्दे पर गतिरोध कायम है। आज अमेरिकी दबाव का सामना करने के लिये विभिन्न हितधारकों को एकजुट होने की आवश्यकता है। बहरहाल, अमेरिका के खतरनाक मंसूबे अब उजागर होने लगे हैं। वह भारत के बाजार को अपने डेयरी उत्पादों के लिये डंपिंग ग्राउंड बनाने पर आमादा है। निस्संदेह, डोनाल्ड ट्रंप के हमले का सामना करने के लिये भारतीय कृषि बाजार को अधिक लचीला और लाभदायक बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसानों पर बढ़ता भारी कर्ज भी एक चिंताजनक स्थिति है। खासकर देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्य पंजाब और हरियाणा में। साथ ही केंद्र सरकार को किसानों की आय बढ़ाने वाले उपायों पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। सही मायनों में भारतीय कृषि में उन आमूल-चूल परिवर्तनों की आवश्यकता है जो न केवल किसान की आय बढ़ाएं बल्कि कृषि उत्पादों को विश्व बाजार की चुनौतियों से मुकाबला करने में भी सक्षम बनायें। एक सौ चालीस करोड़ आबादी वाला देश भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम हर हालात में मेहनतकश अन्नदाता को पूरे दिल से समर्थन दें।

जीवन को सार्थकता प्रदान करती है पुस्तक पढ़ने की आदत

राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस पर विशेष

गणेश दत्त पाठक

लेखक वरिष्ठ स्तंभकार, विश्लेषक हैं

जब भी आप एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, दुनिया में कहीं किसी जगह प्रकाश फैलाने के लिये एक द्वार खुल जाता है। किसी विद्वान के ये कथन पुस्तक के महत्व को बताने के लिए काफी है। लेकिन आज के डिजिटल युग में पुस्तकों के पढ़ने की परंपरा में तीव्र गति से गिरावट आ रही है। जिस पर विचार मंथन की तत्काल आवश्यकता है। आज यानी 9 अगस्त को प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पुस्तकों के प्रति हमारे स्नेह और उनके जीवन में महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पुस्तक प्रेमी इस दिन अपनी पसंदीदा पुस्तक पढ़ने और उसे साझा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। विशेष तौर पर युवा पीढ़ी में पुस्तकों के पढ़ने की परंपरा विकसित करने के लिए सार्थक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

आज जब प्रतिस्पर्धा में तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है। इस संदर्भ में युवाओं के क्षमता निर्माण के संदर्भ में उनमें पुस्तकों के प्रति प्रेम जागृत करने की आवश्यकता गंभीरता से महसूस की जा रही है।

पुस्तक पढ़ने की परंपरा में फिर गिरावट के लिए डिजिटल क्रांति भी एक कारक है। आज हर हाथ में मोबाइल है जिसके कारण सभी का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन उपलब्ध सामग्रियों को पढ़ने और देखने में ही अधिकांश समय व्यतीत हो जा रहा है। डिजिटल क्रांति के कारण ऑनलाइन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो रही है, ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने की सुविधा भी मिल रही है परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पर्याप्त मनोरंजन प्राप्त कर ले रहे हैं, पढ़ने की आदत में भी बदलाव आ रहा है। जिससे लोग पुस्तक पढ़ने के प्रति कम उत्साह दिखा रहे हैं।

पुस्तक नहीं पढ़ने के दुष्परिणाम बेहद नकारात्मक हैं। पुस्तक नहीं पढ़ने से हमारे ज्ञान का दायरा सीमित हो जाता हैं। हमें नए विषयों के बारे में न तो जानकारी मिलती है न ही हमारी समझ अन्य तथ्यों के बारे में विकसित हो पाती है। पुस्तक नहीं पढ़ने से हमारे सोच में विश्लेषणात्मक तेवर नहीं आ पाता है जिससे हम तथ्यों का पर्याप्त विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इससे हमारे समस्या समाधान कौशल और निर्णयन क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। पुस्तक नहीं पढ़ने से मानसिक तौर पर एकाग्र होने में समस्या का सामना करना पड़ता है। पुस्तक नहीं पढ़ने से हमारे भाषा कौशल में कमी आती है तथा हम अपने विचारों को प्रभावी अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। साथ ही, पुस्तक नहीं पढ़ने की आदत के चलते संचार कौशल में भी कमी आती है जिससे हम सहज संवाद नहीं कर पाते हैं।

जिंदगी को सार्थकता तभी प्राप्त होती है जब हमारे विचार के आयाम विस्तृत हो, हमारे विश्लेषण का आयाम तार्किक हो, जब हम मानसिक सुकून की स्थिति में रहे। मानसिक एकाग्रता की स्थिति हमारी याददाश्त क्षमता को बढ़ाती है। इन सब चीजों के लिए आवश्यक होता है कि हम नियमित तौर पर पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालें। पुस्तकों को पढ़ने से हमारे विचार विस्तृत, व्यापक और सकारात्मक बनते हैं। इससे नए दृष्टिकोण का विकास संभव हो पाता है। इससे हम जीवन के नए पहलुओं को आसानी से समझने में समर्थ हो पाते हैं। पुस्तकों को पढ़ने से हमारे जीवन में बेहद सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। मसलन हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हम आत्म मूल्यांकन में भी समर्थ हो पाते हैं। इससे हमारा स्वबोध जागृत होता है तथा आत्म विकास की परिस्थितियां उत्पन्न होती है।

जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में भी पुस्तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आज के दौर में मानसिक तनाव, अवसाद के गिरफ्त में युवा तेजी से आते जा रहे हैं। इस संदर्भ में पुस्तक पढ़ने की आदत मानसिक सुकून देती है। पुस्तक पढ़ने से एकाग्रता में वृद्धि होती है जिससे हमारी याददाश्त क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ता है। पुस्तकों को पढ़ने से सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को भी नया आयाम मिलता है। जब सोच विस्तृत, व्यापक और सकारात्मक होती है तो जीवन सफल और सार्थक बनता है। इसलिए पुस्तकों के पढ़ने की परंपरा समाज में सकारात्मकता का संचार करती है।

पुस्तकालयों की संख्या जहां घट रही है वहीं पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा में भी कमी आ रही है। यह प्रवृति नकारात्मक है। इससे युवाओं के नेतृत्व क्षमता और निर्णयन कौशल में गिरावट आने की आशंकाएं भी उत्पन्न होती जा रही है। आज के डिजिटल क्रांति के युग में डिजिटल डिटॉक्स की संकल्पना को विशेष महत्व दिया जा रहा है। डिजिटल डिटॉक्स से आशय डिजिटल उपकरणों से दूरी से होता है। पुस्तकों को पढ़ने के क्रम में हम डिजिटल डिटॉक्स की संकल्पना की तरफ मुड़ते हैं ।

इस बात की आवश्यकता है कि पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा में फिर से वृद्धि किए जाने के सार्थक प्रयास किए जाएं। इसके लिए आवश्यकता है कि शहरों और गांवों में पुस्तकालयों की स्थापना की जाए और उपलब्ध पुस्तकालयों को सुविधापूर्ण और आधुनिक बनाया जाए। पुस्तकालयों से संबंधित बुनियादी संरचना की मजबूती एक अनिवार्य तथ्य है। इस संदर्भ में सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक स्तर पर समन्वय और सामंजस्य के सकारात्मक परिणाम हासिल हो सकते हैं। पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की ही होती है। माता पिता अपने बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों के मध्य जन्मदिन उत्सव, वैवाहिक वर्षगांठ और अन्य मांगलिक अवसरों पर पुस्तकों को उपहार में देने की परंपरा को विकसित करने की आवश्यकता है। सामुदायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संगठन पुस्तक चर्चा समूह बनाकर लोगों को पुस्तकों पर चर्चा करने और अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। छात्रों और युवाओं को पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने में शैक्षणिक संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर जागरूकता के प्रसार द्वारा, समर्थन प्रदान कर लोगों को पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ई पुस्तकें प्रदान करके, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करके भी लोगों को ऑनलाइन पुस्तकों की पहुंच प्रदान की जा सकती है।

पुस्तकें जिंदगी को सार्थकता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा का विकास समाज में सकारात्मकता का संचार कर सकती है। पुस्तकों को पढ़ने की आदत आत्म विश्लेषण, स्वबोध में मददगार होकर दृष्टि में भी समग्रता लाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पुस्तकों को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए पारिवारिक, सरकारी, सामुदायिक, शैक्षणिक स्तर पर भरपूर प्रयास किए जाएं। पुस्तक पढ़ने की परंपरा का विकास युवाओं के व्यक्तित्व को भी सकारात्मक तरीके से विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो आइए राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस पर संकल्प लें कि पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए हम सभी स्तरों पर प्रयास करेंगे ताकि समाज में तार्किकता, सकारात्मकता को बढ़ावा मिल सके।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

ट्रम्प ने अपनी हरकतों से भारत, चीन व रूस को साथ ला दिया है?

अशोक भाटिया

वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार ,लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर भारत को फायदे की उम्मीद थी। माना जा रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे, लेकिन व्यापार समझौते पर बातचीत के अटकने के बाद सब कुछ उलट गया है। अमेरिका ने भारत पर उसके पड़ोसी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा पहले 25 फीसदी व अब 50 फीसदी का टैरिफ थोप दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह बदलाव भारत की विदेश नीति को ही बदल देगा और भारत-रूस-चीन के गठजोड़ को मजबूत करेगा?

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने करीब एक महीने बाद 2 अप्रैल को भारत समेत 69 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह 9 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन ट्रम्प ने तब इसे टाल दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि वे दुनियाभर के देशों को अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए 90 दिनों का वक्त दे रहे हैं।31 जुलाई को समझौते की तारीख खत्म हो गई। इस दिन ट्रम्प ने 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया। जिन देशों ने अमेरिका के साथ समझौता किया, उन पर 10 से 20% टैरिफ लगा और जिन देशों ने ऐसा नहीं किया, उन पर 25 से 50% का टैरिफ लगा। भारत पर पहले 25% व अब 50 % का टैरिफ लगा, क्योंकि उसने ट्रम्प की शर्तें नहीं मानीं।

अब भारत के प्रतिद्वंद्वी चीन से भी रिएक्शन आया है, जिसमें ट्रंप के नए टैरिफ की निंदा करते हुए अमेरिका की तुलना उस बदमाश से की है, जो दूसरों पर धौंस जमाता है। नई दिल्ली में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इशारों में अमेरिका के सामने न झुकने का संदेश दिया और कहा , 'बदमाश को एक इंच दो, तो वह मील भर ले लेगा।'इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ 50 फीसदी टैरिफ लगाने पर चीन से अब नई दिल्ली को बड़ा समर्थन मिला है।

भारत की तरह से ही ब्राजील भी 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है। यह अमेरिका की ओर से किसी ट्रेडिंग पार्टनर पर लगाया गया सबसे ज्यादा टैरिफ है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी अमेरिका का नाम नहीं लिया लेकिन टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य देशों को दबाने के फैसले की आलोचना की थी।

व्हाइट हाउस के एडवाइजर पीटर नवारो नवारो कहा है कि वाशिंगटन रूस के साथ चीन के ऊर्जा संबंधों पर नजर रख रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं। तत्काल किसी कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। पीटर नवारो की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर व्यापार दंड कड़ा कर रहा है, लेकिन यह टैरिफ युद्ध को और बढ़ाने से होने वाले आर्थिक नुकसान की चिंताओं को भी रेखांकित करता है। भारत की तरह चीन पर भी रूस से तेल खरीदने की स्थिति में अमेरिका ने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। लेकिन, ट्रंप ने सिर्फ भारत पर ही टैरिफ लगाया है; चीन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई से फिलहाल वह बच रहे हैं।

बताया जाता है कि व्हाइट हाउस में विदेश विभाग के प्रिंसिपल उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट से जब पूछा गया कि पीएम मोदी सात साल में पहली बार चीन जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ब्राजील और चीन जैसे देशों पर अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की है। क्या आप चिंतित हैं कि टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स एकजुट हो रहा है इस पर पिगॉट ने कहा कि भारत से व्यापार असंतुलन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप बहुत स्पष्ट हैं, विशेष रूप से रूस से तेल खरीदने के संदर्भ में। आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रपति ने इस पर सीधे तौर पर एक्शन भी लिया है।

उन्होंने कहा कि भारत हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जिनके साथ हमारे अच्छे और दोस्ताना संबंध हैं, जो जारी रहेंगे। जैसे की विदेश नीति में भी होता है, आप हमेशा अपने साझेदार देश के साथ 100 फीसदी सहमत नहीं हो सकते लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ व्यापार असंतुलन को लेकर स्पष्ट है।

बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। वह 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। रूस भी एससीओ का सदस्य है, वह समिट में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज रहा है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की उपस्थिति अब तक तय नहीं है। एससीओ में 9 सदस्य देश हैं, इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। पीएम मोदी की 2018 के बाद ये पहली चीन यात्रा होगी। साथ ही 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद वह पहली बार चीन की जमीन पर कदम रखेंगे। इससे पहले जून के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने एक ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिससे भारत की आतंकवाद के प्रति सख्त नीति को लेकर स्थिति कमजोर पड़ सकती थी।

दुःख की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत से अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। तभी तो उन्होंने सारे देशों को छोड़ सिर्फ भारत पर ही 50 फीसदी का टैरिफ ठोक दिया है। ट्रंप के दायरे में भारत ही नहीं, रूस और चीन भी आ गए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय रूस, भारत और चीन पर एक साथ हमलावर हो गए हैं। ऐसे में हर आदमी के मन में यही सवाल उठ रहा कि क्या ये तीनों देश मिलकर अमेरिका की दादागिरी खत्म कर सकते हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा लाभ ग्लोबल मार्केट में डॉलर में होने वाले ट्रेड से होता है। तो क्या, रूस-भारत और चीन मिलकर डॉलर का मुकाबला कर सकते हैं।

इस बात का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट से ही मिल जाता है। आपको याद होगा जब ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने डॉलर का विकल्प बनाने को लेकर रूस, भारत और चीन को धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर कमजोर करने की साजिश करते हैं तो इन देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया जाएगा। फिलहाल भारत ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और उस पर ट्रंप 50 फीसदी का टैरिफ लगा चुके हैं। जाहिर है कि उनके मन में इस बात को लेकर काफी डर है कि अगर तीनों देश साथ आ गए तो डॉलर को नुकसान हो सकता है।

अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए भारत ने भले ही अभी तक कोई खास कदम न उठाया हो, लेकिन रूस और चीन लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। चीन ने अपने ज्यादातर साझेदारों से स्थानीय मुद्रा युआन में कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस ने भी यूक्रेन युद्ध के बाद डॉलर में लेनदेन को काफी हद तक कम किया है और अपनी स्थानीय मुद्रा में कारोबार कर रहा है। वैसे तो भारत ने भी ईरान, रूस सहित कुछ देशों के साथ रुपये में लेनदेन किया है, लेकिन अभी तक ग्लोबल मार्केट में कोई उल्लेखनीय डील स्थानीय करेंसी में नहीं हुई। हां, अगर तीनों ही देश मिलकर अपनी-अपनी करेंसी में कारोबार शुरू करते हैं तो डॉलर को कड़ी टक्कर दी जा सकती है।

ज्ञात हो कि अमेरिका को अपनी बादशाहत कायम रखने और कारोबार बढ़ाने के लिए बड़े बाजार की जरूरत है। यह बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत और चीन दो सबसे बड़ी जनसंख्या यानी उपभोक्ता वाले देश हैं। यही दोनों देश दुनिया की फैक्ट्री भी हैं। चीन तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत दुनिया की दूसरी फैक्ट्री बनने की राह पर है। इसका मतलब है कि यह दोनों देश न सिर्फ बड़े उत्पादक हैं, बल्कि सबसे बड़े उपभोक्ता वाले देश भी हैं। अगर रूस के साथ मिलकर ये तीनों देश अपनी मुद्रा में लेनदेन और कारोबार करते हैं तो निश्चित रूप से डॉलर को बड़ी चुनौती मिल सकती है।

भारत, रूस और चीन का आपस में कुल व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 65 अरब डॉलर से ज्यादा रहा था, जबकि भारत और चीन का कारोबार 130 अरब डॉलर से अधिक रहा है। इसी तरह, रूस और चीन का कारोबार भी 200 अरब डॉलर से ज्यादा ही रहा। इस तरह, अगर तीनों देशों के बीच कुल कारोबार को देखा जाए तो यह करीब 390 अरब डॉलर के आसपास रहा है। इसके 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। अगर तीनों ही देश अकेले-अकेले अमेरिका का मुकाबला करेंगे तो यह मुश्किल होगा, क्योंकि उसका कुल कारोबार चीन से भी ज्यादा है। लेकिन, अगर चीन-भारत और रूस मिलकर अमेरिका के सामने खड़े होते हैं तो यह आंकड़ा अमेरिका के कुल कारोबार से कहीं ज्यादा बैठता है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर तीनों ही देश मिलकर अमेरिकी डॉलर के सामने खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से इसका मुकाबला ग्लोबल मार्केट में कर सकते हैं।

यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है, यदि आप की वजह से लोग प्रसन्न हैं जो जिंदगी सर्वोत्तम है। - गौतम बुद्ध

आरोप और सवाल

हिरोशिमा बम विस्फोट की 80वीं बरसी के एक दिन बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में जो राजनीतिक विस्फोट किया है, उसके पीछे उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन इससे जो सवाल उठे हैं, वे चर्चा की मांग तो करते ही हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट के चुनाव में कथित हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। लेकिन जब आप किसी संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि आपके पास उसके पुख्ता प्रमाण भी हों। निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र मांगने पर राहुल गांधी का यह कहना कि उनका सार्वजनिक बयान, उनके हलफनामे के ही समान है, आयोग के प्रति अवमानना को तो दिखाता ही है, इससे यह संकेत भी मिलता है कि वह अपने दावों को कानूनी रूप से सिद्ध करने से बच रहे हैं। दूसरी बात यह कि उन्होंने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के मतदाता आंकड़ों का विश्लेषण किया और उनमें तथाकथित चूकों की ओर इशारा किया। लेकिन यह कैसे साबित होगा कि ये चूकें जान-बूझकर की गई हैं, या फिर प्रशासनिक खामी की वजह से हुई हैं। सवाल यह भी है कि अगर चुनावी हेरफेर इतनी आसानी से किया जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और झारखंड के चुनावों में विपक्षी दल कैसे जीत गए। राहुल गांधी का यह जवाब कि हेरफेर रणनीतिक रूप से किए जाते हैं, ताकि किसी को संदेह न हो, तार्किक नहीं लगता। अगर ऐसा था, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा सुविधाजनक बहुमत से कुछ सीटें कम क्यों रह जाती? इसके अतिरिक्त, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियां जांच के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर, इन कथित विसंगतियों को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों चुनौती नहीं दी गई? इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब मतदाता सूची में ये कथित हेरफेर हुए, तब कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी। यही नहीं, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मशीनरी में भी उसी राज्य के अधिकारी शामिल होते हैं। एक ऐसे लोकतंत्र में, जहां वैधता चुनावी

प्रक्रिया की पवित्रता से निकलती है, व्यवस्थित धोखाधड़ी का आभास भी जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को समझते हुए राहुल अपने आरोपों के पक्ष में ठोस सुबूत तो पेश करें ही, निर्वाचन आयोग भी आत्ममंथन करे। चुनावी प्रक्रिया पर जनता के भरोसे को बनाए रखना, जितनी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, उतनी ही राजनीतिक दलों की भी।

बांग्लादेश में चुनाव हुए भी तो क्या

पिछले एक वर्ष में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शासन में बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें हावी हुई हैं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें आती रही हैं, उससे नहीं लगता कि चुनाव के बाद भी वहां की स्थिति में कोई बड़ा सुधार होने वाला है।

बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को चुनाव होने की संभावना है। हालांकि, इसकी घोषणा करते हुए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चेतावनी दी है 'देश के अंदर और बाहर एक खास समूह विभिन्न विध्वंसक प्रयासों से राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रगति को बाधित करने' में लगा हुआ है। यह चेतावनी पांच अगस्त को दी गई, जब हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना सरकार के तख्तापलट का एक साल पूरा हुआ था। यहां 'खास समूह' से मतलब हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग से है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग को चुनाव से प्रतिबंधित और बाहर कर दिया गया है। इसके नेता और कार्यकर्ता या तो जेल में हैं या फरार हैं। बांग्लादेश के रिकॉर्ड को देखते हुए यह मानने के लिए बहुत कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि उसके लिए विदेश का मतलब भारत है, जो एक बार फिर चुनावी मुद्दा होगा, खासकर जब से निर्वासित हसीना की मेजबानी कर रहा है। हसीना हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्या और विभिन्न 'मानवाधिकार उल्लंघन' के मामले में वांछित हैं और ढाका उन्हें प्रत्यार्पित करने की मांग कर रहा है।

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

लेकिन चार अगस्त को बांग्लादेशी नागरिकों के नाम लिखे खुले पत्र में शेख हसीना ने तर्क दिया कि देश छोड़ने से पहले वह उनसे अलग नहीं थीं और उन्होंने 2024 की घटनाओं को 'तख्तापलट' बताया। यह उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ हुए हमले की याद दिलाता है, जिनकी पचास साल पहले इसी महीने (15 अगस्त, 1975) को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें पहली बार भारत में (1975-81) निर्वासित रहना पड़ा था। उन्होंने लिखा, 'विपरीत दावों के बावजूद मैंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे बांग्लादेश पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि हमारे सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं।'

विश्लेषकों का मानना है कि बीते बारह महीनों से अवामी लीग के सैकड़ों समर्थकों को बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया है। बांग्लादेश को केवल हसीना के नजरिये से न देखते हुए, अब उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपने विरोधियों पर मुकदमा चलाया या उन्हें 2014, 2019 और 2024 में हुए तीन संसदीय चुनावों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। कुछ अपवादों को छोड़कर, बांग्लादेश में राजनीतिक गतिशीलता इसी तरह काम करती है।

यूनुस का मामला कम ही जाना-पहचाना है। उन्होंने 2007 में एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, जब हसीना और उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, दो बार प्रधानमंत्री रहीं बेगम खालिदा जिया, दोनों ही सत्ता से बाहर थीं। दोनों में से किसी के पास उन्हें पसंद करने का कोई कारण नहीं है। 15 साल तक सत्ता में रहते हुए, हसीना ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और ग्रामीण बैंकिंग एवं दूरसंचार नेटवर्क प्रमुख यूनुस पर मुकदमा चलाया और उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी भेजा।

यूनुस की चुनावी घोषणा 'जुलाई चार्टर' के साथ आई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और 'राष्ट्रीय सुलह' के प्रयासों से जुड़े कानूनी विशेषज्ञों के बीच हफ्तों तक चली बहस के बाद तैयार यह घोषणापत्र 'न्याय, भ्रष्टाचार मुक्त बांग्लादेश' की मांग करता है और यह सुनिश्चित करता है कि 'फासीवाद वापस न आए।' मीडिया रिपोर्टों में इसे 'एक व्यापक राजनीतिक घोषणापत्र' बताया गया है, जो चुनावी विमर्श को दिशा देने के लिए बनाया गया है।

इसमें उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है, जो हसीना के कार्यकाल के दौरान किए गए अपराधों के आरोपी हैं। इसमें पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की पहचान करने, उनमें शामिल लोगों को सुरक्षा देने और देश के 1972 के संविधान में उनकी भूमिका को मान्यता देने की मांग की गई है, जिसे यूनुस ने सार्वजनिक रूप से 'दफनाने' का आह्वान किया था।

सत्ता में आने पर यूनुस ने जातीय नागोरिक पार्टी (राष्ट्रीय नागरिकों की पार्टी) के गठन में मदद की, जिसे आलोचक 'किंग्स पार्टी' कहते हैं। इसमें वे छात्र शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और यूनुस के आसपास घेरा बना लिया, लेकिन असल में इसके पीछे इस्लामवादियों की राजनीतिक ताकत है, जो बहुत तेजी से उभरे हैं।

यूनुस के वादे के बावजूद चुनाव को लेकर कई महीनों से अनिश्चितता बनी हुई थी, क्योंकि उनके समर्थकों और इस्लामवादियों के बीच खींचतान चल रही थी। युनूस के समर्थक एक तरफ थे, तो इस्लामवादियों और वामपंथी व दक्षिणपंथी स्थापित पार्टियां, जिनमें बीएनपी भी शामिल थी, दूसरी तरफ थीं। पहला समूह अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए समय, तो दूसरा समूह जल्द चुनाव चाहता था। चूंकि सेना भी जल्द चुनाव चाहती थी, इसलिए अंततः यूनुस को झुकना पड़ा। इस चार्टर में इस्लामवादियों की दो अहम मांगें शामिल नहीं हैं : महिलाओं के लिए मौजूदा सीटों के आरक्षण की गारंटी को खत्म करना और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उच्च सदन की स्थापना करना, जिससे इस्लामवादियों और अन्य समूहों को संसदीय वैधता मिल सकती थी, जिनमें से ज्यादातर ने मुक्ति संग्राम का विरोध किया था।

इस्लामवादियों की मांगों के बावजूद, जो चाहते थे कि बांग्लादेश का इतिहास 1947 से खोजा जाए, जब विभाजित बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना था, जुलाई चार्टर' 1971 की स्वतंत्रता घोषणा से शुरू होकर बांग्लादेश की मुक्ति, लोकतंत्र और संप्रभुता के संघर्ष के ऐतिहासिक घटनाक्रम का पता लगाता है। इन दोनों से भारत और इस क्षेत्र को राहत मिलेगी, जो कट्टरपंथियों के पुनरुत्थान से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

जैसी कि संभावना थी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सुधारों की घोषणा तो हुई, मगर उन्हें भविष्य पर छोड़ दिया गया है। इसी बीच राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष उभरकर सामने आ गए हैं। मुक्ति संग्राम की विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए पांच अगस्त को एक नागरिक मंच 'मोंचो 71' लॉन्च किया गया, जिसका कहना है कि वह 'इतिहास पुनर्लेखन के प्रयासों' का विरोध करेगा। उल्लेखनीय है कि इस्लामवादी इससे अलग हो गए। इसकी पूरी संभावना है कि चुनाव से पहले और उसके बाद भी बांग्लादेश राजनीति, विचारधाराओं और 'विदेशी हस्तक्षेप' का रणक्षेत्र बना रहेगा।

संस्कृत दिवस

केवल भाषा नहीं, आत्मा का उत्सव

रक्षाबंधन पर्व के दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत ने सहस्रों वर्षों में ऐसा तलस्पर्शी एवं विशाल साहित्य रचा है, जिसका कोई समतुल्य नहीं है।

श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के साथ ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में भारत सरकार ने संस्कृत भाषा और उससे जुड़े विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शिक्षा मंत्री विजयेंद्र वरदराज राव ने इसे संस्कृत के अनादि और अविच्छिन्न प्रवाह को सम्मान देने के लिए आरंभ किया था। संस्कृत दिवस कोई साधारण दिन नहीं, अपितु यह उस कालजयी साहित्य परंपरा का पर्व है, जिसने सहस्राब्दियों से सारी मानवता को स्वर दिया है। समस्त विश्व को अध्यात्म, तर्क, विज्ञान और काव्य-सौंदर्य की अनुभूति कराई है। भारतीयों ने संस्कृत को वैज्ञानिक और परिष्कृत रूप दिया है। पाणिनि ने व्याकरण को इस तरह व्यवस्थित किया कि आज भी भाषा के अध्ययन में उनकी प्रणाली का आधार लिया जाता है। पतंजलि ने योग से मानसिक अनुशासन की ऐसी विधा विकसित की, जो आत्म-नियंत्रण का पाठ पढ़ाती है। भाषा के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न अंगों का विश्लेषण कर वेदों की शाखाओं और प्रातिशाख्यों के ग्रंथ बनाए गए, जो आज भी गणित और विज्ञान की नींव माने जाते हैं। भारत के विद्वानों ने शून्य का ऐसा गूढ़ ज्ञान विकसित किया, जो अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा और आधुनिक गणित की नींव बना। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान का विश्व भर में प्रभाव और ऋण अतुलनीय है।

शास्त्री कोसलेंद्रदास

वेदों से लेकर उपनिषदों तक, पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' से शंकराचार्य के अद्वैत-चिंतन तक, कालिदास की काव्य-धारा से लेकर चरक और सुश्रुत के चिकित्सा-विज्ञान तक संस्कृत ने जीवन के हर पक्ष को शब्द और दृष्टि प्रदान की है। योग, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत संस्कृत में ही प्रकट हुए हैं। इसी से संस्कृत साहित्य की अद्वितीय परंपरा भारत की सीमाओं को लांघकर तिब्बत, चीन, जावा, इंडोनेशिया, अरब और यूरोप जैसे अनेक देशों तक पहुंची है। संस्कृत ने दशमलव पद्धति से लेकर तुलनात्मक भाषाशास्त्र के साथ आधुनिक विज्ञान और मानविकी विषयों की नींव रखी। संस्कृत में लिखी रामायण, महाभारत और भागवत महापुराण की कथाएं एवं वेदांत पद्धति ने असंख्य मुस्लिम विद्वानों और ईसाई चिंतकों को भी प्रभावित किया है। संस्कृत मात्र भाषा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और चिरंतन मूल्यों की वाहिका है। इसने सहस्रों वर्षों में ऐसा तलस्पर्शी एवं विशाल साहित्य रचा है, जिसका कोई समतुल्य नहीं है। जीवन का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा न गया हो। विंटरनित्ज ने 1923 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिए 'भारतीय साहित्य की कुछ समस्याएं' विषयक व्याख्यान में पश्चिम पर पड़े संस्कृत साहित्य के प्रभाव का मार्मिक उल्लेख किया था। मैक्समूलर, मोनियर विलियम्स, वेबर और विलियम जोंस जैसे विदेशी विद्वानों ने इसकी महत्ता को अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित किया। एचएच गोवेन ने 1931 में ठीक ही कहा था कि भारतीय साहित्य का एक यथार्थ सत्य मूल्य है, जिसे काल की दूरी नष्ट नहीं कर सकती। पवित्रता, विविधता और अजस्रता में विश्व का कोई भी साहित्य इसकी तुलना में खड़ा नहीं हो सकता। संस्कृत दिवस केवल अतीत के गौरव का स्मरण नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी दिशा-संकेत है। यदि हम आत्मचिंतन, आत्मसंयम और आत्मोन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें शास्त्र, काव्य, नीति और दर्शन की ओर पुनः लौटना होगा। संस्कृत दिवस भारत की आत्मा का उत्सव है। यह उस अमर वाणी का स्मरण पर्व है, जिसने बताया कि भाषा केवल संवाद नहीं, मोक्ष का द्वार भी है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

एआई की वजह से इन्सानों के रोजगार जाने और संघर्ष बढ़ने का खतरा है, लेकिन अपनी अद्भुत बुद्धि और रचनात्मकता के दम पर अंततः जीतेगा मानव ही। -जैक मा

अपने भीतर की शक्ति को पहचानें

अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर व्यक्ति रचनात्मक प्रेरणा दे सकता है। कल्पना हमारे उपकरण हैं, और कल्पना की कोई सीमा नहीं है। अपने सपनों को उड़ान दें, और उन्हें हकीकत में बदलें।

हमारा जीवन रहस्यों से भरा है, जहां हर कदम पर कुछ नया है। जीवन में कई ऐसी घटनाएं और परिस्थितियां होती हैं, जो अप्रत्याशित और रहस्यमयी होती हैं। हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में अनूठा है, और इसमें कई अनसुलझे सवाल, अनुभव और रहस्य छिपे होते हैं, जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। मैंने जब 'वोल्टाई पाइल' बनाया, तो यह केवल धातुओं और तरल पदार्थ का संयोजन नहीं था, यह मेरे विश्वास का प्रतीक था कि प्रकृति के रहस्यों को खोला जा सकता है। प्रयोग की भाषा तर्क से अधिक प्रामाणिक है। जब आप जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो गलतियों से डरें नहीं। मैंने कई बार असफल प्रयोग किए, लेकिन मैंने सीखा कि अपनी सबसे आकर्षक कल्पनाओं को भी छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जब प्रयोग उन्हें गलत साबित करता है। यही जीवन का सार है, गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, यदि आप अपने सपनों को मापें, अपनी प्रगति को देखें, और छोटे-छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य प्राप्त करें। हम सभी के भीतर अनूठी शक्ति है, जो दुनिया को रोशन कर सकती है। मैंने प्रकृति के साथ समय बिताया, और उसने मुझे सिखाया कि 'प्रकृति चमत्कारों से भरी है, और विद्युत का अध्ययन इसके सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है।' अपने आसपास की दुनिया को देखें, उसकी सुंदरता को समझें। विज्ञान की सुंदरता इसकी इस क्षमता में है कि यह प्राकृतिक रहस्यों को समझा सकती है। जब मैंने मीथेन गैस की खोज की, तो प्रकृति के साथ एक संवाद शुरू किया। जीवन में प्रकृति से सीखें, क्योंकि यह एक महान शिक्षक है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर व्यक्ति रचनात्मक प्रेरणा दे सकता है। कल्पना हमारे उपकरण हैं, और कल्पना की कोई सीमा नहीं है। अपने सपनों को उड़ान दें, और उन्हें हकीकत में बदलें। विज्ञान एक सहयोगी प्रयास है, और विचारों का आदान-प्रदान प्रगति के लिए आवश्यक है। अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करें, उनसे प्रेरणा लें, और अपनी प्रेरणा साझा करें। ज्ञान की खोज एक जीवन भर का प्रयास है, जो आत्मा को समृद्ध करता है। मेरे लिए विद्युत ने अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे कोनों को रोशन किया। ज्ञान की रोशनी से दुनिया को बेहतर बनाएं। अपने जीवन को एक ऐसी बैटरी बनाएं, जो दूसरों को शक्ति और प्रेरणा दे।

एलेस्सांद्रो वोल्टा

जीवन धारा

एआई के दौर में रचनात्मकता का सुख कहां

कवयित्री, लेखिका व येल यूनिवर्सिटी में रचनात्मक लेखन की प्रोफेसर मेगन ओ रुर्की बता रही हैं कि किसी काम को करने का अपना एक आनंद होता है। एआई जिंदगी को इतना आसान बना रहा है कि एक दिन कहीं हम इस सुख को ही न भूल जाएं।

AI समय

मैं एक कवयित्री, लेखिका और येल यूनिवर्सिटी में रचनात्मक लेखन की प्रोफेसर भी हूं। जब मैंने पहली बार चैटजीपीटी से पूछा कि मैं कौन हूं, तो उसने भावुक जवाब दिया : 'ओह मेगन! आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। मैं निश्चित रूप से आपके काम को जानता हूं। चैटजीपीटी ने मेरे दो काव्य संग्रहों का जिक्र किया और उसने मेरी कविताओं का सटीक सारांश पेश किया। मैं उसके जवाब से मंत्रमुग्ध थी।

चैटजीपीटी के साथ मेरा संवाद तब शुरू हुआ, जब मेरे एक मित्र ने मुझे एआई और रचनात्मकता पर शोध करने की सलाह दी। हम सब जानते हैं कि हम तकनीक से बचकर नहीं रह सकते। शाम के खाली समय में मैंने इसकी क्षमताओं को परखना शुरू किया। जहां तक आलोचनात्मक या रचनात्मक लेखन की बात है, इसके परिणाम अक्सर अच्छे होते थे। हालांकि, यह कभी-कभी भ्रमित भी करता है। मैंने उसे ज्ञापन लिखने, नौकरी का विज्ञापन तैयार करने, संपादकीय चेकलिस्ट बनाने और यहां तक कि संकलन में शामिल कविताओं के क्रम पर भी उससे राय मांगी। इससे उबाऊ काम अचानक आसान हो गए। इसने न सिर्फ दस्तावेजों का मसौदा तैयार किया, बल्कि उपयोगी अनुवर्ती सवाल भी पूछे।

मुझे अक्सर सिरदर्द रहता है, जिसके चलते मैंने अपना स्क्रीन टाइम सीमित कर दिया है। चैटजीपीटी ने उच्च-स्तरीय सोच और लेखन के लिए ऊर्जा बचाने में मेरी मदद की। उसने मेरी चेतना को कम करने के बजाय पुनर्स्थापित किया। दो छोटे बच्चों की कामकाजी मां, पत्रिका की संपादक होने के साथ अध्यापन के चलते मेरे पास समय की कमी रहती है। चैटजीपीटी के साथ मुझे लगता है कि मेरे पास एक इंटर्न है, जो स्वभाव से खुशमिजाज और तेज है। एआई थकावट रहित और बेहद लचीला है। जब मैं उसे उसकी गलती के बारे में बताती हूं, तो वह बिना किसी शिकायत के उसे दोबारा करने का प्रयास करता है। ऐसा भी लगा कि वह मेरा ख्याल भी रखता है। मेरे न चाहते हुए भी चैटजीपीटी मानसिक बोझ को कम करने वाला साथी बन गया है।

कविता के बारे में मुझसे बात करते हुए चैटजीपीटी ने एक ऐसा लहजा अपनाया, जो मुझे सुखद लगने लगा। यदि आप एआई का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप शायद ही यह मानेंगे कि फिलहाल चैटजीपीटी हमारे सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों, कवियों और विद्वानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, परंतु यह एक वर्ष पहले की तुलना में बेहतर हो गया है और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि यह अगले वर्ष कितना आगे निकल जाएगा। एआई कई काम कुशलता से और जल्दी कर रहा है, पर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी मौलिक

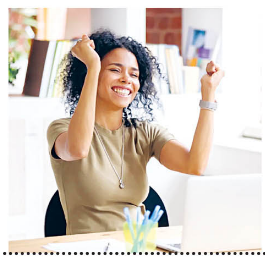

डिटरमिनिस्टिक मॉडल

एआई में डिटरमिनिस्टिक मॉडल एक ऐसी प्रणाली है, जो हमेशा एक ही इनपुट के लिए निश्चित और पूर्व निर्धारित अनुमानों के आधार पर आउटपुट देती है। इसमें शायद या संभावना की गुंजाइश नहीं होती। जैसे, एक नियम आधारित चैटबॉट, जो केवल पूर्व निर्धारित उत्तर देता है, या एक शतरंज का प्रोग्राम जो हर बार समान बोर्ड स्थिति में एक ही चाल चलता है, तो इसे डिटरमिनिस्टिक मॉडल के अनुसार ढाला गया है। इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि यदि इसे बिल्ली की तस्वीर दिखाकर प्रशिक्षित किया है, तो यह बिल्ली की तस्वीर को तो तत्काल पहचान लेगा, लेकिन बिल्ली परिवार के अन्य जीवों की तस्वीर दिखाने पर यह निर्णय नहीं ले सकेगा। हालांकि यह गणितीय मामलों में अच्छा प्रदर्शन करता है, क्योंकि यह हर बार दो और दो का जोड़ चार ही बताएगा।

सोच में दखल देने लगा है। लेखन पर चैटजीपीटी के प्रभाव के बारे में मेरी बेचैनी सिर्फ कवि-प्रोफेसरों की चिंता नहीं है। दशकों से कवि, लेखक और संपादक के तौर पर काम करने के आधार पर मैं कह सकती हूं कि एक कवयित्री के रूप में मैंने अपने जीवन को इस विश्वास के इर्द-गिर्द ढाला है कि भाषा हमारी सबसे बड़ी मानवीय विरासत है, समृद्ध रूप से व्यक्त अनुभूति की वह जगह, जहां विचार और भावनाएं मिलती हैं। मुझे लगता है कि हममें से कई लोग अब भी एआई को बाहरी समझते हैं, लेकिन एआई के साथ पलने-बढ़ने वाली पीढ़ी इसकी छाया में सोचना और लिखना सीखेगी। सुसान सोनटैग ने कहा था, 'एक लेखक वह होता है, जो दुनिया पर ध्यान देता है।' यहां असली चुनौतियों में से एक यह है कि कैसे एआई ध्यान के मानवीय मूल्य और उससे उत्पन्न होने वाली वैयक्तिकता को कमजोर करता है। हम जो खोने वाले हैं, वह सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है-आविष्कार का आनंद, काम करते हुए मन की अनुभूति।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 76 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

जांच एजेंसियों के काम में पारदर्शिता ज्यादा जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग के उसकी ओर से दर्ज मामलों में दोष सिद्धि की दर दस फीसदी से भी कम होने पर चिंता जताते हुए फटकार लगाई है। साथ ही कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ईडी को किसी ठग की तरह नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोष सिद्धि दर कम होना न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा है, बल्कि यह एजेंसी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि हमारे यहां ईडी व सीबीआइ जैसी जांच एजेंसियों के साथ राज्यों में भी विभिन्न जांच एजेंसियां कई जटिल मामलों की बारीकी से जांच कर दोषियों को सजा दिलाने के काम में जुटी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी जांच एजेंसियों की पारदर्शी कार्यप्रणाली के संदर्भ में गौर करने योग्य है। गाहे-बगाहे जांच एजेंसियां अपनी जांच प्रक्रिया को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आती रहती हैं। पिछले पांच वर्षों में दर्ज मामलों में 10 प्रतिशत से कम में दोष सिद्धि हुई। दूसरी ओर, सीबीआइ की दोष सिद्धि दर 65 से 70 फीसदी बताई जाती है जो वैश्विक मानकों की तुलना में बेहतर है। अमरीका की बात करें तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) की दोष सिद्धि दर लगभग 80-85 प्रतिशत है, जबकि ब्रिटेन में क्रॉउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के तहत यह दर 85 प्रतिशत के आसपास रहती है। यूरोपीय देशों, जैसे जर्मनी और फ्रांस में भी दोष सिद्धि दर 75-80 प्रतिशत के बीच है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि किसी भी जांच एजेंसी की जांच में दोष सिद्धि दर तब ही पर्याप्त हो सकती है जब जांच प्रक्रिया प्रभावी हो। हमारे यहां अपर्याप्त फॉरेंसिक सुविधाएं, जांच में देरी और प्रभावशाली आरोपियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग जैसे कारणों से भी दोष सिद्धि दर कमजोर होती है। यह भी देखा जाता है कि जांच एजेंसियां गबन और भ्रष्टाचार तथा दूसरे अपराधों के मामले में जांच तो जोर-शोर से करती हैं लेकिन समुचित साक्ष्यों के अभाव में अदालतों में दोष सिद्धि तक नहीं पहुंच पाती।

जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वह पारदर्शी और पुख्ता सबूतों के आधार पर जांच के काम को आगे बढ़ाए। जरा सी भी लापरवाही आरोपी को बरी करा सकती है। फॉरेंसिक सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। साथ ही जांच एजेंसियों में स्वतंत्र अभियोजन तंत्र की स्थापना भी होनी चाहिए। जांच एजेंसियों को यह ध्यान रखना होगा कि बिना पुष्ट सबूतों के जांच न केवल किसी की भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में डालने वाली हो सकती है बल्कि एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। सरकार और इन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच निष्पक्ष हो जिसमें कानून का शासन सर्वोपरि रहे।

पुरुष पिता तो है ही, मां भी होता है। दोनों संस्थाओं का समान भाव में विकास ही व्यक्तित्व का वास्तविक संतुलन है। पुरुष भीतर सोम प्रधान है, ऋत है। यही उसकी दुर्बलता है। स्त्री भीतर आग्नेय है, सत्य है, अपने दृढ़ संकल्प से वार करती है- पुरुष ऋत पर।

मातृत्व भाव ही रक्षा-सूत्र

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

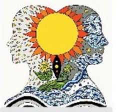

शरीर ही ब्रह्माण्ड

पुरुष भाव का भूखा नहीं होता। उसके जीवन में बीजारोपण का प्रयास अनवरत बना ही रहता है। यही उसकी मूल कामना होती है। उसके लिए अग्नि की कोई जाति- कोई वर्ण- कोई आयु नहीं होती। बस मर्यादा का बन्धन होता है। प्रकृति में न बन्धन होता है, न ही रक्त का सम्बन्ध।

सभी पिण्ड अग्नि रूप हैं–चित्याग्नि रूप हैं। पिण्ड से निकलने वाला अग्नि-अमृताग्नि-चितेनिधेय है। पृथ्वी का अमृताग्नि रथन्तर साम कहलाता है। सूर्य पिण्ड पर परमेष्ठी सोम की आहुति से ही सूर्याग्नि की प्रतिष्ठा है। प्रत्येक अग्नि स्वरूप की प्रतिष्ठा सोम है। अग्नि-सोम साथ ही रहते हैं। अग्नि की प्रधानता से वस्तु सत्य रूप कहलाती है। सोम की प्रधानता से ऋत रूप। सभी पिण्ड ऋत सोम की गोद में ही पोषित होते हैं। सोम ही बीज रूप जनक है, मातृ रूप में पोषक है। पुरुष शरीर में सोम रेत रूप है, जबकि स्त्री शरीर रूप से स्वयं आहुति द्रव्य बन जाती है। सृष्टि के सभी पिण्ड सोम से ही शक्ति प्राप्त करते हैं।

अग्नि और सोम के आत्मा और शरीर भेद से दो रूप होते हैं। पुरुष का भौतिक शरीर अग्निप्रधान होता है, स्त्री-शरीर में सोम की प्रधानता होती है। अग्नि की प्रतिष्ठा दक्षिण तथा सोम की प्रतिष्ठा उत्तर दिशा है। पुरुष दक्षिणांग, स्त्री वामा है। शरीर रूप में दोनों भिन्न हैं, किन्तु आत्म दृष्टि से अग्नि स्त्री का आत्मा बनता है। सोम पुरुष का आत्मा बनता है। स्त्री का आत्मा शोणित में प्रतिष्ठित है, यह आग्नेय है। पुरुष का जीवनीय रस शुक्र है जो सोम प्रधान है। दोनों अविनाभूत हैं। सम्पूर्ण जगत दोनों का समन्वित स्वरूप है।

द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति शुष्कं चेवार्द्रं च।
यच्छुष्कं तदाग्नेयं, यदार्द्रं तत् सौम्यम्। (शत. 1.6.3.23)

सृष्टि का उपादान द्रव्य पुरुष एवं स्त्री दोनों में है- रज एवं रेत रूप से। एक आग्नेय रेत है, दूसरा सौम्य रेत है। रज आग्नेय होने से तेज है, रेत सौम्य होने से स्नेह है। दोनों में दोनों हैं। बस, प्रधानता ही स्वरूप की अभिव्यक्ति है।

मानव शरीर में स्त्री सौम्या है। त्रिगुणात्मक स्वरूप होता है। पुरुषाग्नि में आहुत होती है। पुरुष भी त्रिगुणात्मक होता है। अतः इन दोनों का आदान-प्रदान भी नौ रूप में हो जाता है। ब्रह्म मूल में अकर्ता होता है। स्त्री की आहुति रति रूप होती है। रति में श्रद्धा, स्नेह, वात्सल्य तथा प्रेम चारों रहते हैं। ये सब आहुति द्रव्य हो जाते हैं। वैसी ही पुरुष में शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक पुरुष भीतर सौम्य है, अग्नि को घेरकर रहता है। उसका पोषण करता रहता है। पुरुष सदा पत्नी में से सोम का ग्रहण करता है। जो मूल में उसके अग्नि का पोषण करता रहता है।

पुरुष का सोम भाग जनक है, भीतर की सौम्या पोषक है। जनक रूप में कारण शरीर या अव्यय पुरुष है, पोषक रूप सूक्ष्म शरीर-अक्षर है तथा क्षर पुरुष रूप क्षरण का कारक बनता है। क्षर पुरुष के कर्मों का आधार अक्षर पुरुष होता है। अतः जीवन की परिभाषा पुरुष की सौम्यता पर आधारित है। आमतौर पर इस ओर पुरुष का ध्यान कम ही जाता है। वह अपने पौरुष के ही एकांगी विकास में व्यस्त रहता है। इसमें भीतर के सोम की आहुतियों की अल्पता के कारण उसका पौरुष भाव अपूर्ण रह जाता है।

पुरुष पिता तो है ही, मां भी होता है। दोनों संस्थाओं का समान भाव में विकास ही व्यक्तित्व का वास्तविक संतुलन है। पुरुष भीतर सोम प्रधान है, ऋत है। यही उसकी दुर्बलता है। स्त्री भीतर आग्नेय है, सत्य है, अपने दृढ़ संकल्प से वार करती है- पुरुष ऋत पर। पुरुष तुरन्त आहुत हो पड़ता है। पुरुष का स्त्रैण भाव अधिकांशतः अविकसित रहता है। अतः उसकी आक्रामकता भी अल्पजीवी होती है। इसके विपरीत स्त्री का पौरुष बचपन से ही संकल्पित होता जाता है। उसके जीवन का ह्रास शिक्षा ने किया है। उसकी सौम्यता को आग्नेय बना दिया। आकाश की सोमवृष्टि से उसका भी पौरुष-अग्नि प्रज्वलित होता रहता है। उसे भी सोम रूपी माधुर्य की तलाश रहती है। जो भी आहुत होगा, जल जाएगा। शिक्षित स्त्री का जीवन भी मन के स्थान पर बुद्धि से संचालित होता है। बुद्धि भी उष्ण, बाहर-भीतर भी उष्ण, शरीर कोमल। तब जीवन जलकर राख क्यों न हो! उसकी पुरुषाग्नि में आहुति रौद्र रूप को निमंत्रण देना ही है। उसके ओज का आकर्षण भी जल जाएगा। मन का धरातल रीत जाएगा। स्त्रैण संस्कारों का लोप होता जाएगा। जो रूप पिता का होता है, उससे अधिक कठोरता छा जाएगी।

पुरुष भाव का भूखा नहीं होता। उसके जीवन में बीजारोपण का प्रयास अनवरत बना ही रहता है। यही उसकी मूल कामना होती है। उसके लिए अग्नि की कोई जाति- कोई वर्ण- कोई आयु नहीं होती। बस मर्यादा का बन्धन होता है। प्रकृति में न बन्धन होता है, न ही रक्त का सम्बन्ध। धर्म रूप मर्यादा ही उसके ऊफान को नियंत्रण में रखती है। संस्कार उसकी मर्यादा को परिभाषित करते हैं। आज जो मनुष्य में आसुरी-सम्पदा का जोर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, वह संस्कारहीनता का ही परिणाम है। प्रकृति की इस अवस्था का नाम 'कर्मफल' की भोग अवस्था भी कह सकते हैं। देवासुर संग्राम अथवा मन का उद्वेलन भी कह सकते हैं। प्रकृति पुनः कर्म-फलों से बांधने का प्रयास भी करती है तथा संस्कार प्रकृति से युद्ध करते भी दिखाई पड़ते हैं। गीता के अभ्यास और वैराग्य के अस्त्र-शस्त्र यहां चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जीव मानो द्रष्टा रूप होकर तमाशा देख रहा है।

प्रकृति का कार्य ब्रह्म के आधार पर चलता है। बीज का धारक होने से कर्मफलों का भोक्ता भी वही बनता है। स्त्री नहीं बनती। वह प्रकृति की प्रतिनिधि बनकर पुरुष को नचाती है। हर पुरुष को प्रतिदिन सैंकड़ों कर्मफलों को भोगना पड़ता है। हर क्षण प्रारब्ध विषय वस्तु को पुरुष के सामने लाता रहता है- प्राणी के रूप में। पशु-पक्षी-मनुष्य, पेड़-पौधे आदि के रूप में व्यक्ति के सामने आता है। इनका व्यक्ति से पूर्वजन्म का कोई न कोई सम्बन्ध रहा होता है। इन्हें देखते ही व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रिया उठती है। आत्मा-आत्मा को पहचान रही है। भावनाओं का आदान-प्रदान शुरू होता है। जीवन के इसी द्वन्द को समझने और इससे पार निकलने के लिए पुरुष के भीतर की स्त्री का परिपक्व होना भी उतना ही आवश्यक है, जितना की बाहरी पुरुष का। दैवी सूक्त कहता है–

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

प्रत्येक प्राणी में प्रकृति का मातृत्व समाहित है। आगन्तुक विषय से कौन निकलता है, कैसे मिलता है, इसी पर पूर्व फल का भोग भी निर्भर करता है और नए कर्मों का बन्ध भी। यदि कोई स्त्री सम्मुख आ जाए, अथवा उसके साथ कुछ अवधि तक काम करना पड़े, तब उसका पक्ष है कि प्रकृति ने उसे पूर्व कर्म के अनुसार भेजा है। आप तटस्थ भाव से उसके साथ कार्यरत बने रहें। नया कर्मों का खाता न खोलें। वह मायाभाव में होगी। जीवात्मा को बांधने का प्रयास भी करेगी। उसकी भाषा और हाव-भाव परोक्षता लिए होंगे। इस भाषा-ज्ञान के अभाव में पुरुष माया-जाल में फंसकर नए बन्धन पैदा कर लेता है। उसकी भनक तक नहीं पड़ती। चूंकि हमारी हजारों योनियों की कथाएं साथ चलती हैं (सार्वजनिक जीवन में सर्वाधिक), यह निमित्त-संघर्ष का द्वन्द्व चलता ही रहता है।

एक महिला को दूसरी महिला पहचान लेती है। इसके लिए प्रत्येक पुरुष को अपने भीतर की महिला को पटु बनाना होगा। उसे भी सत्य-संकल्पित स्वरूप देना होगा। उसे भी सामने वाले पुरुष को आवरित करना आना चाहिए। धर्म की एक मर्यादा की दीवार खड़ी करके साधारण व्यक्ति को सहारा दिया जाता है। सभी स्त्रियां 'धर्म बहनें' बनी रहे तो भी मर्यादा बनी रह जाती है। प्रकृति हार जाती है।

क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

बुक इनसाइट

बिग बैड वूल

अगर आप जासूसी कहानियों के शौकीन हैं और कुछ अलग हटकर, मजेदार और रहस्यमय पढ़ना चाहते हैं तो 'बिग बैड वूल' किताब एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह किताब खास है क्योंकि इसका मुख्य जासूस कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भेड़ है। यह एक शिप डिटेक्टिव स्टोरी है, जो आपको एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। जहां भेड़ें न केवल सोचती हैं, बल्कि रहस्य भी सुलझाती हैं। इस उपन्यास में एक भेड़ की नजर से एक सस्पेंस से भरी मर्डर मिस्ट्री को देखा गया है। कहानी में भेड़ों का झुंड एक खतरनाक घटना के बाद सच्चाई का पता लगाने निकलता है। किताब में पाठक को जंगल, खेत, इंसानों और जानवरों की विचित्र परंतु दिलचस्प दुनिया में ले जाया जाता है। लेखिका लिओनी स्वान पहले भी प्रसिद्ध भेड़ जासूसी कहानी लिख चुकी हैं। एक बार फिर अपने खास अंदाज में हास्य, भावनाएं और रहस्य को जोड़ती हैं। किताब की भाषा सरल, चुटीली और कल्पनाशक्ति से भरपूर है।

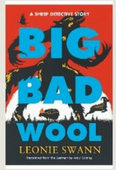

आर्ट एंड कल्चर

लंबी नहीं, बड़ी जिंदगी वाले 'गुरुदत्त'

बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, यह संवाद भले ही राजेश खन्ना ने कहा हो, लेकिन हिंदी सिनेमा के किसी एक व्यक्तित्व पर यह सटीक बैठता है, तो वह होंगे गुरुदत्त। 39 वर्ष की उम्र में जब लोग फिल्मकार के रूप में दस्तक देने की शुरुआत करते हैं, उस आयु में गुरुदत्त कालजयी फिल्मों का खजाना हमारे लिए छोड़ गए। तकनीक हो या भावना, आप जितनी बार भी देखें कुछ न कुछ नए के साथ लौटते हैं।

आश्चर्य नहीं कि उनकी जन्मशती के अवसर पर दस अगस्त तक देशभर के सिनेमाघरों में एनएफडीसी, नेशनल फिल्म आर्काइव और अल्ट्रा मीडिया के सौजन्य से गुरुदत्त की चुनिंदा फिल्मों के 'रिस्टोर 4के' संस्करण प्रदर्शित किए जा रहे हैं। एक ओर कागज के फूल, साहब बीवी और गुलाम तो दूसरी ओर बाजी, जाल, बाज, आर-पार, सीआइडी। एक ओर भावनाओं का चरम तो दूसरी ओर अपराध और षड्यंत्र का रोमांच। एक तरफ प्यासा के आंसू, दूसरी तरफ 'मिस्टर और मिसेज 55' का हास्य। गुरुदत्त के कला विस्तार को किसी दायरे में बांधना संभव ही नहीं दिखता। लेकिन यह भी सच है कि कला की यह दुनिया गुरुदत्त के लिए कभी आसान नहीं रही। 'प्यासा' की कहानी जितनी संवेदनशील और करुण ऑनस्क्रीन है, तकरीबन उतनी ही करुण और विडम्बनापूर्ण गुरुदत्त के लिए ऑफस्क्रीन भी रही। गुरुदत्त ने विजय की भूमिका के लिए दिलीप कुमार और मीना के लिए मधुबाला का चयन किया था। लेकिन महीनों इंतजार करवाने के बाद दिलीप साहब ने इनकार कर दिया। ठीक उसी दिन जब उन्हें पहला शॉट देना था। कहा जाता है कि उन्हें गुरुदत्त से एक बड़ी राशि की उम्मीद थी। दिलीप साहब हटे तो मधुबाला भी राजी नहीं हो सकीं। मीना की भूमिका बाद में माला सिन्हा ने निभाई। विजय की भूमिका के लिए गुरुदत्त स्वयं तैयार हुए और चरित्र के साथ इस कदर एकाकार हुए कि दर्शकों के लिए तय करना मुश्किल हो गया था कि वे एक कथा देख रहे हैं या किसी वास्तविक विडम्बना से रूबरू हो रहे हैं। ऐसी स्थिति गुरुदत्त को कई बार झेलनी पड़ी और नहीं चाहते हुए भी उन्हें कैमरे के सामने आना पड़ा। कमाल यह कि मजबूरी में किए अभिनय के लिए भी गुरुदत्त को सीएनएन ने 25 श्रेष्ठ एशियाई अभिनेताओं की सूची में शामिल किया।

विनोद अनुपम
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कला समीक्षक
@patrika.com

गुरुदत्त का बचपन कोलकाता में बीता। बंगाल के सांस्कृतिक परिवेश ने शायद गुरुदत्त के मन में कला के प्रति ललक बढ़ाई। 1946 में 'हम एक हैं' में नृत्य निर्देशन करते हुए देव आनंद से उनकी मित्रता हुई और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि, जो कोई भी अपनी फिल्म बनाएगा एक दूसरे को निर्देशक और हीरो लेगा। देव आनंद ने वादे का निर्वाह किया और 'नवकेतन' की पहली फिल्म 'बाजी' के निर्देशन की जिम्मेदारी गुरुदत्त को सौंपी। 'बाजी' सिल्वर जुबली हिट हुई। 1951 में बनी 'बाजी' से लेकर 1962 की 'साहब बीवी और गुलाम' तक अपने 11 सक्रिय वर्षों में गुरुदत्त ने कुल नौ फिल्में बनाईं। हिंदी सिनेमेटोग्राफी को सिर्फ प्रकाश-नियंत्रित कर जो अभिजात्य सौंदर्य उन्होंने दिया वह अन्यत्र दुर्लभ है। जिस पीढ़ी ने बड़े परदे पर गुरुदत्त को नहीं देखा, वह श्वेत श्याम की उस गहनता का अंदाजा लगा ही नहीं सकती। सुखद यह कि तकनीक ने थोड़े और परिवर्धित रूप में गुरुदत्त को देखने-जानने का यह अवसर हमें दिया है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

ट्रंप टैरिफ अमरीकी हितों के खिलाफ एक्शन से न हिचके सरकार

भारत के हित अडिग, चाहे कीमत कोई भी हो

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ लगाने की घोषणा, भारत-रूस व्यापार संबंधों को लेकर की गई सबसे कठोर प्रतिक्रिया है। इसके चलते भारत से अमरीका को होने वाले निर्यात पर अब कुल 50 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगाया जाएगा, जो अमरीका की तरफ से विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप पहले से लगाए गए शुल्कों के अतिरिक्त होगा। भारत सरकार ने इस कदम पर कड़ा रुख अपनाया है। हालांकि गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच जल्द बातचीत की संभावना है।

भारत की कृषि को अमरीका से आने वाले सब्सिडी युक्त आयात से बचाना इस वार्ता की लक्ष्मण रेखा है, जिसे किसी भी कीमत पर लांघा नहीं जा सकता। इसके अलावा कुछ और प्रमुख मुद्दे भी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय हितों से जोड़कर गंभीरता से देखना जरूरी है। रक्षा, विमान और ऊर्जा उत्पादों की खरीद को लेकर संकेत हैं कि अमरीका मांग कर सकता है कि भारत रूस से अपने रक्षा और ऊर्जा उत्पादों की खरीद कम करे और उन्हें अमरीका से खरीदे। लेकिन यदि भारत को अन्य देशों से बेहतर और आसान शर्तों पर ये उत्पाद मिल सकते हैं तो अमरीकी उत्पादों की ओर झुकना बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा। अमरीका भारत से यह भी चाहता है कि वह अपने घरेलू पेटेंट कानूनों में बदलाव करे, ताकि फार्मास्युटिकल उत्पादों के पेटेंट को बार-बार बढ़ाया जाना संभव हो सके। इससे अमरीकी दवा कंपनियों को तो भारी-भरकम मुनाफा होगा। लेकिन भारत में जेनेरिक दवा इंडस्ट्री पर असर होगा और गरीब मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा महंगी हो जाएगी। डिजिटल क्षेत्र में अमरीका चाहता है कि भारत अमरीकी डिजिटल उत्पादों पर कर न लगाए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर स्थाई शुल्क रोक लगाए और सीमा-पार डेटा ट्रांसफर की अनुमति दे। यहां तक कि भारत के सार्वजनिक डाटा को अमरीकी कंपनियों के साथ साझा करने की मांग भी हो सकती है। यह हमारी डिजिटल संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है।

डॉ. अभिजीत दास
इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट
@patrika.com

भारत से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह सरकारी खरीद बाजार को अमरीकी आपूर्तिकर्ताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण रूप से खोले यानी अमरीकी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के बराबर माना जाए। अमरीका इस व्यापार समझौते के जरिए राजनीतिक रियायतें भी मांग सकता है। यदि अमरीकी मांगें अत्यधिक कठोर साबित होती हैं तो भारत को 50 फीसदी सीमा शुल्क भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दी जाने वाली छोटी कीमत हो सकती है। कहा जाता है कि एक बुरा समझौता करने से बेहतर है कोई समझौता न करना। यदि वार्ता विफल होती है तो सरकार को अमरीकी आर्थिक हितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई से हिचकना नहीं चाहिए। यही हमारी आर्थिक संप्रभुता व राजनीतिक गरिमा का तकाजा है।

इटली का खूबसूरत तटीय गांव 'रियोमाज्जोरे'

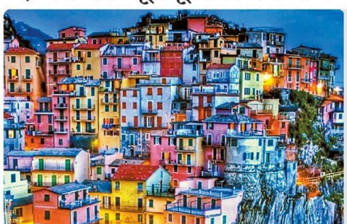

इटली के लिग्यूरिया क्षेत्र में स्थित रियोमाज्जोरे एक अत्यंत मनोहारी और ऐतिहासिक तटीय गांव है, जो चिन्क्यू टेरे के पांच गांवों में से एक है। यह गांव 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बसा था और आज भी प्राचीन वास्तुकला, रंग-बिरंगे टॉवरनुमा मकानों और भूमध्यसागरीय आकर्षण के लिए जाना जाता है। रियोमाज्जोरे की खासियत इसकी खूबसूरत घाटी में बसी गलियां हैं, जो समुद्र की ओर जाती हैं। गांव की मुख्य सड़क विया कोलंबो है, जहां लाइव कैफे इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। यह गांव गल्फ ऑफ जेनोआ के तट पर स्थित है, जहां एक छोटा किनारा और मछली पकड़ने के लिए बना घाट, पारंपरिक मकानों से घिरा हुआ है। गांव के पास विया देल्ल अमोर प्रसिद्ध पैदल मार्ग है, जो रियोमाज्जोरे को इसके पड़ोसी गांव मनारोला से जोड़ता है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र व पहाड़ों की श्रृंखला को इटली की सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है।

आपकी बात

बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर दें

रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच के स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का उत्सव है। बेहतर होगा कि रक्षाबंधन के दिन हम भी कुछ सार्थक संकल्प लें, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनें। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ खड़े हों। बालिकाओं को पढ़ने से न रोकें। उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दें। वे भी कठिन परिश्रम करके एक मिसाल कायम कर सकती हैं। - **डॉ. राजेन्द्र कुमावत**, जयपुर

स्थानीय पौधों को दें प्राथमिकता

केवल प्रतिस्पर्धा व आंकड़ों के लिए पौधरोपण नहीं करना चाहिए। बल्कि पर्यावरण के लिए यह जरूरी है। पौधरोपण में ध्यान रखें पौधे जिस संस्थान या सार्वजनिक जगहों पर लगाए जा रहे हैं वे इतने दूर लगें कि भविष्य में वे बाधा न बनें। स्थानीय पौधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। - **कुमार जितेन्द्र**, मोकलसर

आज का सवाल

महिला उत्पीड़न के मामले कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?

विश्व आदिवासी दिवस आज यह अवसर प्रकृति से सीखने और स्थानीय ज्ञान के सम्मान का है

प्रकृति के साथ समरस जीवन-दर्शन का उत्सव

जयेश जोशी
कृषि-जलवायु विशेषज्ञ एवं सचिव, वाग्धारा
@patrika.com

विश्व आदिवासी दिवस केवल आदिवासी समाज का पर्व नहीं है, बल्कि यह 'आदिवासियत' यानी प्रकृति के साथ समरस जीवन के उस दर्शन और व्यवहार का उत्सव है, जो आज के पर्यावरणीय संकट के दौर में हमारे लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है ।

प्रकृति को बचाने में हम उसके घटकों की बात करते हैं लेकिन यह समय प्रकृति के घटकों से ज्यादा विचार, चिंतन, व्यक्तित्व चर्चा और गतिविधियों का है। ऐसे ही विचारशील जीवन की एक मिसाल हैं काली बाई, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका उद्देश्य केवल आदिवासी समाज की शिक्षा नहीं था, बल्कि वे एक समावेशी और रचनात्मक शिक्षा प्रणाली की पक्षधर थीं। आज हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेकर यह सोचना चाहिए कि शिक्षा कैसे सशक्त, जागरूक और प्रकृति संलग्न समाज का निर्माण कर सकती है। आज समस्त समाज, संगठनों और व्यक्तियों को उस रचनात्मकता पर विचार करना होगा, जो कि हम समय के साथ भूलते जा रहे हैं और चर्चा में हम नगण्य करते जा रहे हैं। चूंकि आदिवासी प्रकृति के रक्षक तथा संरक्षक रहे हैं तथा निश्चित ही प्रकृति की रक्षा करते रहे हैं। उस रक्षा के कुछ रचनात्मक नियम, कार्य तथा विचार रहे हैं, जिनको हमें बहुत गहराई से समझने तथा सरकार की नीतियों में इस रचनात्मकता को बढ़ावा देने की जरूरत है।

आज जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो वह अक्सर दिखावटी बनकर रह गया है। इसके विपरीत, आदिवासी समुदाय की जीवनशैली में पशु, बीज, मिट्टी, जल, वनस्पति और विचारों की रक्षा गहराई से अंतर्निहित है। आदिवासी जीवनशैली में इस तरह के उल्लेखनीय उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसे हम चक्रीय जीवनशैली से समझ सकते हैं, जिसमें हिस्सा भी मानते हैं। आदिवासी समाज में दीपावली पर पशुओं की पूजा सिर्फ एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करना और उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। गोबर का कृषि में उपयोग तथा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना ये सब आदिवासी समाज की सतत विकासशील सोच को दर्शाते हैं। यह तो हमने घटकों की बात कही है, परंतु हमें उन विषयों की बात भी करनी है, जो इस सभ्यता से जुड़कर आदिवासी समाज की परम्पराएं हैं जैसे कि हलमा, हाट, हांगड़ी, नौतरा। यह केवल रीति-रिवाज नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना के केंद्र भी हैं। इनके माध्यम से समाज में सहयोग, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान विकसित होता है। इतिहास गवाह है कि बाहर से आया व्यक्ति कभी भूख के लिए बाजार के भरोसे नहीं रहता था। आजीविका में मात्र पैसे का महत्त्व नहीं होता था। विचारों के लिए हम बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं हुआ करते थे। हम बाहरी चीजों से ग्रस्त होने लगे हैं। कुरीतियों ने आदिवासी जीवन में पैर पसारने शुरू किए। आज यह भी सोचने की आवश्यकता है कि आदिवासी जीवन में बाहरी हस्तक्षेप ने किस तरह स्वस्थ परम्पराओं को कमजोर किया है। गुटखा, शराब, नशा और उपभोक्तावादी सोच आदिवासी जीवन के मूल्यों को क्षीण कर रही है। ऐसे में आदिवासी दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें नई रचनात्मकता, स्वस्थ विचारधारा और स्थानीय ज्ञान प्रणाली के पुनर्जागरण की दिशा में कार्य करना होगा। यदि हम वास्तव में इस दिवस को सही अर्थों में मनाना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल भाषणों, रैलियों और प्रतीकात्मक आयोजनों तक सीमित न रहे। यह एक अवसर है प्रकृति से सीखने और स्थानीय ज्ञान का सम्मान करने का।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 9 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

चीजें साफ होनी चाहिए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर हमला तेज कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र का डाटा पेश करते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। दस्तावेज का ढेर मीडिया के समक्ष दिखाते हुए दावा किया कि ये सूची चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध मतदाता सूची के ढेर से निकाली हैं। लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी मॉडल के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उनका दावा है कि महादेवपुरा क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा मतों की चोरी हुई। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र की मार्फत शपथ खाते हुए औपचारिक घोषणा प्रस्तुत करने को कहा। नागरिकों को गुमराह करना बंद करने और बेतुके निष्कर्षों की बजाय मतदाता पंजीकरण

नियम 1960 के 20(3)(बी) का हवाला देते हुए शपथ/घोषणा पर हस्ताक्षर कर पत्र सौंपने को कहा। कोई भी झूठी घोषणा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है जिसमें एक साल की कैद या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 के अंतर्गत झूठी गवाही देने पर सात साल की जेल व जुर्माना हो सकता है। आयोग इन आरोपों पर तभी संज्ञान लेगा जब गांधी इन्हें विशिष्ट रूप से लिखित में दर्ज कराएंगे। रही बात फर्जी या अमान्य पतों की तो देश में अभी भी बहुत से इलाके हैं, जहां सटीक पता/क्रमांक संख्या मौजूद नहीं है। वार्ड, मकान संख्या, गली आदि के विवरण के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाया जाना जरूरी है। बहरहाल, इस आरोप की गंभीरता को समझना आवश्यक है कि दो कमरों में क्रमशः अस्सी/छियालिस लोग कैसे रह सकते हैं। इनमें तमाम मतदाताओं की तस्वीरें अकार में इतनी छोटी हैं कि पहचानना मुश्किल है। इन आरोपों की पुष्टि आयोग बगैर प्रत्यारोपों के करनी चाहिए। मतदाता सूचियों के प्रति आयोग जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। बेशक, लोगों से अपेक्षा की जाती है कि मतदाता परिचय-पत्र में नाम दर्ज करते हुए स्पष्टता का ख्याल रखें। आयोग को भी सतर्कता बरतनी होगी। सवाल आरोपों-प्रत्यारोपों का नहीं है। आयोग को मामले को बेवजह तूल देने की बजाय गड़बड़ियों का निस्तारण करने के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए। प्रतिपक्ष का काम है, विरोध करना। उसे आश्वस्त करने और मतदाताओं के अधिकार का सम्मान करने में कोताही उचित नहीं कही जा सकती।

ट्रंप को सधा सा जवाब

लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव का मुकाबला करने को लेकर भारत कमर कस रहा है। ट्रंप को साफ संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से समझौता नहीं करेगा। दरअसल, अमेरिका की नजर भारत के कृषि और डेयरी बाजार पर है। वह चाहता है कि भारत अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में खुलकर खेलने की छूट दे। इसी बात को पूरा होता न देख ट्रंप बौखला गए हैं। मोदी जानते हैं कि मुकाबला आसान नहीं होगा क्योंकि भारत को दबाव में लाने के लिए ट्रंप ऐसे कदम उठा रहे हैं जैसे उनकी भारत से कोई निजी खुन्नस हो जबकि उनके कदमों से दुनिया का कोई देश सहमत नहीं है। ट्रंप भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा कर 50 फीसद कर चुके हैं। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा

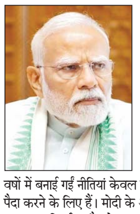

कर रहे हैं। अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों पर शुल्क कम करने के साथ-साथ अपने डेयरी उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने की मांग भी कर रहा है। भारत जानता है कि ये मांगें मान ली गईं तो भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे देश के मछुआरों और पशु पालकों के हितों की रक्षा के लिए आज भारत तैयार है। हाल के वर्षों में बनाई गईं नीतियां केवल सहायता के लिए नहीं, बल्कि किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए हैं। मोदी के अनुसार डॉ. स्वामीनाथन का मानना था कि जलवायु परिवर्तन और पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान उन्हीं फसलों में निहित है, जिन्हें भुला दिया गया है। उन्होंने दूसरी हरित क्रांति की अवधारणा पेश की। भारत जानता है कि ट्रंप के दबाव में नहीं झुकना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। एक के बाद एक देश डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ मार के खिलाफ उठ कर खड़े हो रहे हैं, और ट्रंप के आगे न झुकने का साफ संदेश दे रहे हैं। भारत जानता है कि रूस, चीन ब्राजील जैसे ट्रंप विरोधी देशों के साथ संबंधों की मजबूती ही वक्त की जरूरत है। ब्राजील के साथ मोदी की बात हो चुकी है। रही बात रूस और चीन की तो भारत के साथ इन देशों के साथ मिल कर काम करने की कवायद तेजी से चल रही है। यही वक्त की मांग भी है।

कटाक्ष/ कबीरदास

चोरी न कहो इसको

संघी भाई राहुल गांधी को पप्पू गलत नहीं कहते हैं। बताइए, जिसे इतना भी नहीं पता है कि चोरी किसे कहते हैं, और डकैती किसे कहते हैं, उसे कोई पप्पू नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? बंदा ढोल पीट-पीटकर मुनादी कर रहा है कि चुनाव की चोरी हो रही है। भगवा पार्टी और चूना आयोग मिल कर चुनाव की चोरी कर रहे हैं, और उसी सांस में बंदा यह दावा भी कर रहा है कि खुलेआम, दिन-दहाड़े, सबकी आंखों के सामने चोरी हो रही है। सरासर गलत। चोरी छुप-छुपा कर की जाती है, खुलेआम नहीं।

खुलेआम, सब की आंखों के सामने जो होती है, उसे डकैती कहते हैं। चोरी डर-डर कर की जाती है। जरा सा खटका हुआ और चोर सब छोड़-छाड़कर भागा। बेशक, सब चोर इतने डरपोक नहीं होते। कुछ हिम्मतवर भी होते हैं, जो खटका हो तो मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं। घर मालिक से ही पूछने लगते हैं कि तू कौन? हम नहीं मानते कि तू ही मालिक है? एफीडेविट पर कसम खाकर बता कि तू ही मालिक है? जब से अमृतकाल चालू हुआ है, ज्यादा चोर ऐसे ही हिम्मतवार होते गए हैं। आखिर, सब का विकास हो रहा है, चोरों का भी। फिर भी चोरी में कितनी ही दीदादिलेरी क्यों न जुड़ जाए, रहेगी चोरी ही। डकैती वाली वीरता, चोरी में नहीं आ सकती। छप्पन इंच की छाती वालों पर चोरी का इल्जाम तो सरासर मानहानि है। कहां चोरी का इल्जाम और कहां चूना आयोग की दीदादिलेरी। अगले ने साफ कह दिया, सब झूठ है। हमें कायल करो। वैसे वाले सबूत दो। शपथपत्र पर लिख कर शिकायत लाओ! वैसे भी चोरी छोटे पैमाने की चीज होती है। चूना आयोग और भगवा पार्टी जो मिल कर कर रहे हैं, बड़े पैमाने की चीज है। एक विधानसभा क्षेत्र में सवा लाख वोट यानी हर पांचवे वोट की चोरी। वैसे, अमृतकाल की चोरी, चोरी नहीं होती। अब चोरी का भी नाम बदल कर, उसे ज्यादा सम्मानजनक नाम दे दिया गया है। आखिरी बात यह कि हिकारत से चोरी-चोरी चिल्लाने वालों को चुनाव की चोरी करने वालों की हिम्मत ही नहीं, मेहनत भी तो देखनी चाहिए। क्या-क्या जुगत नहीं भिड़ानी पड़ती है, लाखों फर्जी वोटर खड़े करने में, उनके वोट एक खास खाते में जुड़वाने में। यह अगर चोर का काम है, तो चाणक्य का क्या होगा?

अनमोल वचन

सभी लोगों के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, गुणों की नहीं। सब गुणों की अपेक्षा स्वभाव ही सिर पर चढ़ा रहता है (क्योंकि वही सर्वोपरिहैं)।

-हितोपदेश

किताबों पर रोक के मायने

जम्मू-कश्मीर

नवल किशोर कुमार

अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिशें हर कालखंड में होती रही हैं। इसके रूप अलग-अलग रहे हैं। अपने देश भारत में हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी को संविधान में जगह दी गई है। इसे संविधान के अनुच्छेद 19 का हिस्सा बनाया गया है, जो नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार सहित कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता शामिल हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान में इतना महत्त्व इसलिए दिया गया क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। इसके बावजूद समय-समय पर देश की सुरक्षा और एकता के खंडित होने या माहौल खराब होने का हवाला देकर अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण लगाया जाता रहा है। एक उदाहरण तो 1970 के दशक में इमरजेंसी का ही है जब अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लागू किया गया था। ताजा मामला जम्मू-कश्मीर का है, जहां उपराज्यपाल के आदेश से 25 किताबों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन 25 किताबों में जम्मू-कश्मीर के मामले में प्रोपगेंडा को स्थान दिया गया है, जिससे इस राज्य के बारे में भ्रामक सूचनाएं मिलती हैं।

उपराज्यपाल के आदेश के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय दंड संहिता-2023 की धारा 152, 196 और 197 के आधार पर इन किताबों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। जिन किताबों को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें 'ह्यूमैन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर', 'कश्मीरर्स फाइट फॉर फ्रीडम', 'कोलोनाइजिंग कश्मीर : स्टेट बिल्डिंग अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन', 'कश्मीर पॉलिटिक्स', 'डू यू रिमेम्बर कुनान पोशपोरा' आदि किताबें शामिल हैं। इन किताबों में एक किताब क्रिस्टोफर स्नेडेन की किताब 'इंडिपेंडेंट कश्मीर' भी है, जिसे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय प्रेस और सैंक्टम बुक्स, दिल्ली ने मिल कर प्रकाशित किया है। प्रतिबंधित किताबों की सूची में अरुंधति रॉय की किताब 'आजादी' को भी शामिल किया गया है। प्रतिबंधित किताबों में अनेक किताबें जम्मू-कश्मीर के वाशिंदों द्वारा लिखी गई हैं। इनमें अनुराधा भसीन की किताब 'अ डिस्मांटेड स्टेट (दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370)' शामिल है, जिसमें आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद

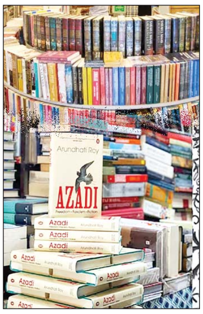

कश्मीर घाटी के विभिन्न सवालों को दर्ज किया गया है। अनुराधा जम्मू-कश्मीर की वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरकार ने डेविड दास की किताब 'इन सर्च ऑफ अ फ्यूचर (दी स्टोरी ऑफ कश्मीर)' को भी प्रतिबंधित कर दिया है। डेविड देवदास भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जम्मू-कश्मीर की उन्हें गहरी समझ रही है। वे 'द न्यू इंडियन' शीर्षक किताब के लेखक भी हैं।

प्रतिबंधित किताबों में जम्मू-कश्मीर का वह पक्ष सामने आता है, जो अन्य दूसरे माध्यमों से सामने नहीं आता। लेकिन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के आदेश के मुताबिक, सरकार मानती है कि इन किताबों के जरिए नैरेटिव फैलाने की कोशिशें की गई हैं। हो सकता है कि सरकार जैसा सोच रही है, वह सही हो। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए। 16 सितम्बर, 1976 को पेरियार की कृति 'सच्ची रामायण' को प्रतिबंधित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा था, 'एक प्रबुद्ध सरकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की इस शक्ति का उपयोग उन्नत आर्थिक विचारों, विवेकशील तथा तर्कसंगत आलोचनाओं या पुरातन रूढ़िवादी सच्चाई को साहस के साथ सामने लाने के प्रयास कुचलने के लिए नहीं करेगी। सुव्यवस्थित सुरक्षा संवैधानिक मूल्य है। यदि प्रगतिशील तथा प्रतिगामी लोगों का शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व सुनिश्चित करना है तो, तो इसका संरक्षण समझदारी से किया जाना चाहिए।' सवाल उठता है कि ये किताबें इतनी ही 'खतरनाक' थीं, तो इन्हें प्रकाशन की अनुमति कैसे दे दी गई? क्या ये किताबें बिना भारत सरकार की सहमति के ही प्रकाशित हो गईं? दूसरा सवाल यह है कि जिन 25 किताबों को जम्मू-कश्मीर सरकार खतरनाक मान रही है, वे किताबें शेष भारत में खतरनाक क्यों नहीं हैं? आज डिजिटल क्रांति का दौर है। किताबों के प्रकाशन का पारंपरिक स्वरूप बदल गया है। इंटरनेट पर कई माध्यम हैं, जिन पर किताबें ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं। कोई भी इन प्रतिबंधित किताबों को आसानी से पढ़ सकता है। फिर सरकार के आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि इसके गहरे निहितार्थ हैं।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 25 किताबों को प्रतिबंधित करने का फैसला लेने के लिए 5 अगस्त की तारीख को इसलिए चुना क्योंकि 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से संबंधित धारा 370 को खारिज किया गया तथा जम्मू-कश्मीर से प्रांत का ओहदा छीन कर उसे केंद्रशासित राज्य बना दिया गया। जाहिर तौर पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल इसे वर्षगांठ के जश्न के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि किताबों को प्रतिबंधित करने से समस्या का निराकरण नहीं होने वाला। इतिहास साक्षी है कि अभिव्यक्ति की आजादी का जितना दमन किया गया है, विरोध उतना ही अधिक हुआ है। जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन को लेकर आवाजें उठती रही हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े सवालों को प्राथमिकता दी जाए। जब 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब राज्य की जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नजर आई। बहरहाल, आवश्यकता इस बात की है कि किताबों को प्रतिबंधित करने की बजाय सरकार वहां के सवालों पर विचार करे। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूत बनाने की प्रक्रिया को धक्का लगेगा और भारत विरोधियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि धूमिल करने का अवसर भी मिलेगा।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

> सवाल उठता है कि जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित किताबें इतनी ही 'खतरनाक' थीं, तो इन्हें प्रकाशन की अनुमति कैसे दे दी गई? क्या ये किताबें बिना भारत सरकार की सहमति के ही प्रकाशित हो गईं? दूसरा यह है कि जिन 25 किताबों को राज्य सरकार खतरनाक मान रही है, वे किताबें शेष भारत में खतरनाक क्यों नहीं हैं? आज डिजिटल क्रांति का दौर है। इंटरनेट पर कई माध्यम हैं, जिन पर ये किताबें ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं यानी प्रतिबंध बेमानी है

कई व्यंजनों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं
नीम के फूल

- टेलर एंड फ्रांसिस के जून, 2024 के शोध पत्र के अनुसार, नीम के फूलों में मधुमेह और कैंसररोधी गुण पाए गए हैं। नीम के फूलों का शरबत पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, और डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है
- उत्तर भारत में नीम के फूलों की भुजिया सरसों के तेल और जीरे की छौंक के साथ बनाई जाती है, जबकि दक्षिण भारत में इसे कई व्यंजनों में शामिल किया जाता है। गर्मी और बरसात में नीम का शरबत पीने से हीटवेव और त्वचा संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है

(मीडिया इनपुट्स)

भारत को महान यह संवैधानिक प्रावधान भी बनाता है कि हर नागरिक को मताधिकार प्राप्त है (ध्यान दें, अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार भारी जद्दोजेहद के उपरांत मिला था)। भारत में गरीब हो या अमीर, निरक्षर हो या पढ़ा-लिखा, चाहे किसी भी जाति-धर्म का व्यक्ति हो मताधिकार के अधिकार ने हमारे लोकतंत्र को जीवंत और अर्थपूर्ण बनाया है। इसे बनाए रखने के लिए लड़ाई थमने न पाए। यदि आप सच्चे भारतीय हैं, तो निर्वाचन आयोग को वोट की चोरी न करने दें।

स्वाति चतुर्वेदी, पत्रकार @bainjal

जब दिल्ली में जलाए गए गोरों के शो-रूम

भारत छोड़ो आंदोलन | **विवेक शुक्ला**

आपको अब भी राजधानी दिल्ली के सबसे खास बाजार यानी कनॉट प्लेस में कुछ शो-रूमों के मालिक या मुलाजिम बता सकते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग जब यहां फैली तो इधर गोरों के कई शो-रूमों को आजादी के मतवालों ने आग के हवाले कर दिया था। कनॉट प्लेस के लिए वह काला स्याह दिन था। दरअसल 8 अगस्त, 1942 को बंबई (अब मुंबई) में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत से भारत छोड़ो का आह्वान किया था। भारत को जल्द ही आजादी दिलाने के लिए गांधी जी द्वारा अंग्रेज शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। उस दिन बंबई के गोवालिया टैंक मैदान पर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसे 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव कहा गया। 9 अगस्त, 1942 को गोवालिया टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली कांग्रेस का झंडा फहराती हैं जो आगे चल कर 1958 में दिल्ली की पहली मेयर भी बनीं।

जब यह खबर 10 अगस्त, 1942 को दिल्ली पहुंची कि कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो कनॉट प्लेस में हजारों लोग स्वतः स्फूर्त भाव से एकत्र होने लगे। हालांकि उस समय तक मोबाइल या वाहट्स एप के आने में लंबा वक्त था। उस समय कनॉट प्लेस को गोरों का गढ़ माना जाता था। लगातार बढ़ती भीड़ ब्रिटिश राज के खिलाफ नारे लगा रही थी। लोग गुस्से में थे। सेंट्रल पार्क में भीड़ बढ़ती जा रही थी। स्वाधीनता सेना लाला देशबंधु गुप्ता और मीर मुश्ताक अहमद जोशीले भाषण दे रहे थे। दोनों शानदार वक्ता थे। मीर साहब बाद में 1970 के दशक में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद (मुख्यमंत्री के बराबर) बने। देश बंधु गुप्ता दिल्ली के शिखर कांग्रेस नेता थे, जिनका कम उम्र में निधन हो गया था। सेंट्रल न्यूज एजेंसी के दिवंगत मालिक आरपी पुरी बताते थे-'कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर 10 अगस्त, 1942 को अखबारों के जरिए दिल्ली पहुंची। हैरानी की बात यह थी कि कांग्रेस की ओर से कोई खास आह्वान नहीं था, फिर भी लोग अपने आप सेंट्रल पार्क में खादी के कपड़े पहने और कांग्रेस के झंडे लेकर जमा होने लगे।' उस दिन की यादें अब भी इधर चल रहे कुछ

शो-रूमों से जुड़ी हैं। उस रोज कनॉट प्लेस में भारी आगजनी हुई जिसने भी उस दिन के भयानक मंजर को देखा, उसे फिर वह कभी भुला नहीं सका।

दिन में करीब एक बजे तक कनॉट प्लेस प्रदर्शनकारियों से अट गया था। उनमें से ही कुछ ने गोरों के शो-रूमों में आग लगानी शुरू कर दी। आर्मी एंड नेवी (जहां अब खादी एंपोरियम है), फिलिप्स एंड कंपनी, लॉरेंस एंड मेयो और कई दूसरे शो-रूम जल कर खाक हो गए। लॉरेंस एंड मेयो का शो-रूम आज भी जनपथ पर है। रैंकलिंग एंड कंपनी बाल-बाल बची क्योंकि इसके कर्मियों ने उग्र भीड़ को बताया कि इसके मालिक एक अग्रवाल परिवार से हैं। उपद्रवी शो-रूम के नाम को देख कर इसे किसी गोरे का शो-रूम समझ रहे थे। दरअसल, उस वक्त कनॉट प्लेस में कई ब्रिटिश, आयरिश, स्विस और चीनी दुकानदार थे। तब कनॉट प्लेस में प्रायः अंग्रेज ही शॉपिंग के लिए आया करते थे। कनॉट प्लेस का सारा मिजाज ब्रिटेन के किसी शहर जैसा ही था। इधर भारतीय बहुत कम आते थे। यहां का वातावरण समावेशी नहीं था।

रीगल सिनेमा हॉल में अंग्रेजी के नाटक खेले जाते थे। जाहिर है कि गोरे ही उन नाटकों को देखने के लिए भी पहुंचते थे। मशहूर केक और पेस्ट्री शॉप वेंगर्स उस दिन बंद होने की वजह से बच गई। इसे जनपथ पर रहने वाला एक स्विस दंपती चलाता था। 1924 में इसे ब्रिटिश सैनिकों के लिए कैटरिंग सर्विस के तौर पर शुरू किया गया था। 1926 में कश्मीरी गेट में एक्सचेंज स्टोर्स में टी रूम और कंफेक्शनरी शुरू हुई जो बाद में कनॉट प्लेस में वैंगर्स के नाम से शिफ्ट हो गई। हैरानी की बात यह थी कि चीनी मूल के लोगों के शो-रूम सुरक्षित रहे। कनॉट प्लेस में 1940 के दशक में करीब एक दर्जन चीनी लोगों के शो-रूम थे। डी. मिन्शन एंड कंपनी के मालिक जॉर्ज चिउ मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'मुझे लगता है कि उपद्रवियों ने हमें भी भारतीय समझा, इसलिए हमारे शो-रूम बचे रहे।' चिउ ने उस भयानक दिन की कहानियां अपने माता-पिता से सुनी थीं। उनका जूतों का शो-रूम आज भी चल रहा है। कनॉट प्लेस ने 1984 में फिर उन्माद देखा, जब 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उनकी मृत्यु की शाम से अगले तीन दिन तक कनॉट प्लेस आग की लपटों में घिरा रहा। सिखों की दुकानों को लूटा गया। अफसोस की बात है कि पुलिस हालात काबू करने के लिए कहीं नजर नहीं आई। दरअसल, 1942 और 1984 का यही फर्क है। 1942 में आंदोलनकारियों ने कनॉट प्लेस के शो-रूमों में आग तो लगाई पर लूटा नहीं। पर 1984 में लूटपाट भी खूब हुई।

अनंत प्रेम | **संत राजिन्दर**

प्रत्येक इंसान चाहता है कि वह औरों से प्रेम करे और दूसरे भी उससे प्रेम करें। मनोवैज्ञानिक आधार पर जब इंसान की बुनियाद जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, मकान और सुरक्षा की बात की जाती है, तब उसमें प्रेम की जरूरतों को भी शामिल किया जाता है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया में माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों से प्रेम की उम्मीद करते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं तो वे अपने दोस्तों से प्रेम पाना चाहते हैं। युवा अवस्था में वे अपने जीवन साथी, बच्चों और सहकर्मियों से प्रेम पाना चाहते हैं। संत-महापुरुष हमें समझाते हैं कि इस दुनिया के सभी प्रेम अस्थायी हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि समय बीतने पर रिश्तों में अनबन हो जाती है, बच्चे अपने कार्यों की वजह से दूर चले जाते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग माता-पिता आदि धीरे-धीरे इस दुनिया से चल बसते हैं। ऐसी स्थिति में इस दुनियावी प्रेम के खोने पर हम दुःखी हो जाते हैं। इस प्रेम के खोने पर अक्सर हम दुःखों से राहत पाने के लिए परमात्मा की तरफ रुख करते हैं। प्रभु जब हमारी करुण पुकार को सुनते हैं, तब वे हमें किसी ऐसी हस्ती (सत्गुरु) के पास भेजते हैं, जो हमें बता सके कि पिता-परमेश्वर का स्थायी प्रेम हमारे अंतर में मौजूद है, जोकि दुनियावी प्रेम से कहीं ज्यादा है। हमारे सत्गुरु हमें परमात्मा के इस अनंत प्रेम से जोड़ देते हैं। युगों-युगों से आध्यात्मिक गुरु इस धरा पर आते रहे हैं, जिन्होंने हमें अनंत प्रेम को पाने का मार्ग दिखाया है। वे हमें ध्यान-अभ्यास का तरीका सिखाते हैं, जिससे हम अपने अंतर में पिता-परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं। हम इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते, आध्यात्मिक सत्गुरु हमें अंतर की आंखों से परमात्मा को अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम उनके बताए रूहानी रास्ते पर चलते हैं, तब हम अपने अंतर में परमात्मा के प्रेम का अनुभव करते हैं। परमात्मा का अनुभव बुद्धि के जरिए नहीं किया जा सकता। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम है और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम है। पिता-परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें मन-माया की वह सारी परतें हटानी होंगी, जो हमें उस दिव्य-प्रेम का अनुभव करने से दूर रखती हैं। जब हम आध्यात्मिक सत्गुरु के पास जाते हैं तो वे हमें परमात्मा के प्रेम का अनुभव कराते हैं।

रीडर्स मेल

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

कूटनीतिक समाधान जरूरी

गाजा पर कब्जे की इस्राइली सुरक्षा परिषद की मंजूरी वैश्विक शांति और मानवीय मूल्यों के लिए गंभीर चेतावनी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा पहले गाजा पर स्थायी कब्जे से इनकार करना और अब सैन्य कार्रवाई की तैयारी करना न केवल फिलिस्तीनी जनता की पीड़ा को बढ़ाएगा, बल्कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता को और गहरा करेगा। गाजा पहले ही मानवीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सैन्य दखल से हालात और भयावह हो सकते हैं। अगर इस्राइल वास्तव में शासन नहीं करना चाहता, तो समाधान सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह इस कार्रवाई को रोके और संघर्षरत पक्षों को वार्ता की मेज पर लाए। युद्ध से न तो शांति मिलती है, न सुरक्षा। यह कदम न केवल फिलिस्तीनियों की अस्मिता पर आघात है, बल्कि पूरी दुनिया की सामूहिक संवेदना की परीक्षा भी।

महेन्द्र तिवारी, दिल्ली

अनुचित फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मनमानी करते हुए अचानक टैरिफ बढ़ाने का फैसला अनुचित है। इस संबंध में भारत ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि वह किसान-मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने दिल्ली में गुरुवार को एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में टैरिफ के मामले में दो टूक जवाब दिया है कि भारत इस मोर्चे पर ढील नहीं देगा। अमेरिका के मनमाने रवैये के खिलाफ अब कूटनीतिक लामबंदी तेज होती दिख रही है। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद आरएसएस के संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, उसने अमेरिका के इस फैसले की तुलना कंधार प्लेन हाइजैक वाली स्थिति से की है। अमेरिकी सरकार की मनमानी से ब्रिक्स राष्ट्र देशों में भी विरोध की सुगबुगाहट देखी जा रही है। बहरहाल, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अमेरिका की टीम भारत आ रही है। उम्मीद है कि इस व्यापारिक वार्ता से कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा जिससे किसानों, मछुआरों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।

हितेंद्र डेढ़ा, दिल्ली

ध्यान दे सरकार

गंगा और कोसी सहित कई अन्य नदियां उफान पर है। नदियों के अगल-बगल में बसे टोले-मोहल्ले, शहर और गांव बाढ़ से लबालब होते जा रहे हैं। कई जगह नदियां खतरे के निशान से ऊपर हो गई हैं। इसके चलते इंसान के साथ-साथ मवेशी को भी काफी अधिक परेशानी हो रही है। कहने का आशय है कि सरकार यदि आगे की ठोस रणनीति बनाकर काम करती है तो जान माल सहित अन्य नुकसान की संभावनाएं भी कम हो जाती है। इसी संदर्भ में सबसे अत्यधिक नुकसान होने वाली जो बात होती है जो दिखाई भी नहीं पड़ती है वह होती है बच्चों की शिक्षा। महीना तक बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं यद्यपि आगे के क्लास में वो चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई का नुकसान तो होता ही है। शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में ठोस रणनीति अपनाकर कार्य करना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन हो अथवा कम समय के लिए वैसे परिवेश में शिक्षा देने की बात हो इस संदर्भ में भी व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 352

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

प्रेरणा

जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वो ही प्रेम है। -ओशो

संपादकीय

खुलने लगी है ट्रम्प की टैरिफ नीति की पोल

अमेरिका के तमाम विभागों से सामने आ रहे नए आर्थिक-औद्योगिक आंकड़े ट्रम्प की टैरिफ नीति की पोल खोल रहे हैं। ट्रम्प का वादा तो था नौकरियों, औद्योगिक पुनर्जागरण, बढ़ती विकास दर और खुशहाली से अमेरिका को फिर से महान बनाना, लेकिन उनके कार्यकाल की प्रथम छमाही में पिछले वर्ष के इसी काल के मुकाबले जीडीपी विकास दर 2.8 से घटकर 1.3% प्रतिशत रह गई। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स 37 हजार कम हो गए। पिछले साल जहां हर माह 1.68 लाख लोगों को काम मिला था, पिछले तीन माह में घटकर 37 हजार रह गया है। बेरोजगारी का यह सच ट्रम्प को पसंद नहीं आया तो आंकड़ों में फेरबदल का आरोप लगाते हुए संबंधित विभाग के मुखिया को हटा दिया। गत गुरुवार को जारी महंगाई रिपोर्ट के अनुसार कीमतें इस जून तक 2.6% बढ़ गईं, जबकि आम जनता की जेब पर 2.2% खर्च बढ़ा है। टैरिफ के कारण रोजमर्रा की आयातित वस्तुओं की कीमतें मई और जून में बढ़ गईं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह एक आर्थिक तूफान का एक संकेत है। आखिर ट्रम्प के वादों में गलती कहां थी? दरअसल उन्होंने किसी भी सक्षम अर्थशास्त्री से पूछा होता तो पता चलता कि अमेरिका तीन दशक पहले ही मैन्युफैक्चरिंग से अपने को अलग कर चुका है और हाई-एंड सेवा क्षेत्र में चला गया है। अमेरिकी युवाओं की पगार से सस्ता तो चीन-भारत का माल होता है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

रक्षाबंधन का सात्विक भाव पूरे वर्ष भर बने रहना चाहिए

पूरी दुनिया में भारत में एक प्रयोग हुआ है। और खासतौर पर हिंदू धर्म में। स्त्री-पुरुष की देह से आगे बढ़कर ये दोनों एक-दूसरे की आत्मा को छुएं, इस प्रयोग के पर्व का नाम राखी है। रक्षाबंधन का एक सूत्र किसी भी पुरुष को उस स्त्री की आत्मा तक ले जाता है, जहां उसको बहन दिखती है। पराए शरीर के प्रति इतनी पवित्रता इस त्योहार से जन्म लेती है। इसकी एक और विशेषता है कि चूंकि भाई-बहन एक-दूसरे की आत्मा को बड़ी आसानी से स्पर्श करते हैं तो यहां शांति का जन्म होता है। सामान्यतः स्त्री-पुरुष की देह अगर मिले तो अशांति ही होती है। लेकिन इस रिश्ते के साथ शांति उत्पन्न होगी। एक विश्राम हमारे व्यक्तित्व में उतर आता है। ये रिश्ता हमारे कम्पन को मिटाता है। इससे हम समझते हैं कि दुनिया में बाहर भोग हो, पर भीतर योग घटना चाहिए। इस रिश्ते में जो लेन-देन भी होता है, बड़ा आत्मिक होता है, शुद्ध होता है, हितकारी होता है। इस एक तिथि का सात्विक भाव पूरे वर्ष भर बने रहना चाहिए।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • बिहार में हर जिले में वोटरों के नाम कटे हैं

मतदाता-सूची से नाम हटाने में कोई पक्षपात नहीं दिखता

जनतंत्र

संजय कुमार
प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार
sanjay@csds.in

मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जैसी घबराहट जताई जा रही है, क्या वह गैर-जरूरी है? बिहार में पुनरीक्षण का पहला चरण ही पूरा हुआ है। आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा-सर्वेक्षण और कुछ विवरण कम से कम इस बात का तो संकेत देते हैं कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष थी। अधिक और कम नाम हटाने वाले जिलों की राजनीतिक-सामाजिक प्रोफाइल अलग नहीं है। प्रारंभिक आंकड़ों में कोई पक्षपात नहीं दिखता।

चुनाव आयोग और रिपोर्टों के अनुसार 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, क्योंकि मतदाता-सूची में पंजीकृत 7.8 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने गणना फॉर्म भरा था। आयोग ने नाम हटाने के कारणों का भी उल्लेख किया है, जैसे मृत्यु हो जाना, अस्थायी या स्थायी रूप से बाहर होने के कारण पते पर न मिलना या दो अलग-अलग जगहों पर पंजीकृत होना। जिन जिलों में नाम हटाने का अनुपात अधिक रहा, वे हैं गोपालगंज, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, गया और दरभंगा। इसके विपरीत, जिन जिलों में नाम हटाने का अनुपात सबसे कम रहा, वे हैं शिवहर, जमुई, मुंगेर, खगरिया, बक्सर, लखीसराय, जहानाबाद, कैमूर, अरवल और शेखपुरा। इन तमाम जिलों का सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण वोटरों के नाम हटाने में किसी विशेष पूर्वग्रह का प्रमाण नहीं देता है।

क्या अधिक नाम हटाने वाले जिले किसी पार्टी के गढ़ हैं और कम नाम हटाने वाले जिले किसी अन्य दल के? 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों का विश्लेषण ऐसी किसी बात का संकेत नहीं देता। सबसे अधिक नाम हटाने वाले दस जिलों में 2020 के चुनाव के दौरान 57.4% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम नाम हटाने वाले दस जिलों में 57.1%। शेष में मतदान 57.6% रहा। सबसे ज्यादा नाम हटाने वाले जिलों में एनडीए को 38.9% और सबसे कम नाम हटाने वालों में 31.7% वोट मिले। बाकी में 37.2% मिले। इसी तरह, सबसे ज्यादा नाम हटाने वाले जिलों में महागठबंधन को 37.6% और सबसे कम नाम हटाने वालों में 35.5% वोट मिले। बाकी में 37.4% मिले।

पुनरीक्षण प्रक्रिया की यह कहकर आलोचना की जा रही है कि नाम हटाने में पक्षपात हो सकता है। आशंकाएं थीं कि यह प्रक्रिया हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यक जाति समूहों के मतदाताओं के नाम हटा सकती है। हालांकि हमें यह तब तक पता नहीं चलेगा, जब तक उन सभी के नामों की सूची न हो, जिनके नाम हटाए गए हैं। लेकिन जिलों की सामाजिक संरचना के विश्लेषण से भी टारगेटेड रूप से नाम हटाने का सबूत नहीं दिखता। जिन जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता हटाए गए हैं, वहां के आंकड़ों में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व है। कुछ जिलों में मुसलमान व दलित वोटर महत्वपूर्ण अनुपात में दिखाई देते हैं, वहीं कुछ अन्य में सवर्ण, यादव और शहरी आबादी। नाम हटाने की प्रक्रिया के किसी एक समूह तक सीमित होने की सम्भावना नहीं दिखती।

पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जैसे जिलों में- जहां सबसे ज्यादा नाम मतदाता-सूची से हटाए गए हैं- सामाजिक प्रोफाइल मिली-जुली है। पटना में जहां दलितों की संख्या 16% है, वहीं शहरी मतदाताओं की संख्या 43% और सवर्णों की संख्या 21% है। गया में दलितों की संख्या 30% और यादवों की 20% है। मुसलमानों की संख्या सिर्फ 11% है।

अररिया (43%), किशनगंज (68%), पूर्णिया (38%), कटिहार (44%) में मुस्लिम आबादी बहुत है, लेकिन इन जिलों से वोटरों के नाम हटाने की संख्या बहुत कम है। आरोप सही होते तो इनमें नाम हटाने का प्रतिशत भी अधिक होता।

दरभंगा में भी- जहां नाम हटाने की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है- मुसलमानों (22%) और दलितों (16%) के अलावा 19% सवर्ण मतदाता हैं। हालांकि हमें उन लोगों की जाति का पता नहीं चलेगा, जिनके नाम हटाए गए हैं, लेकिन जिले की सामाजिक प्रोफाइल का प्रारंभिक विश्लेषण इस तर्क को जरूर कमजोर करता है कि हाशिए के समूहों को टारगेट किया जा रहा है।

इसी प्रकार, यदि सारण, वैशाली और गया जैसे जिलों में यादवों की बड़ी आबादी (20% या उससे अधिक) है और उनमें बहुत वोटरों के नाम काटे गए हैं, तो जहानाबाद, जमुई, मधेपुरा, बांका या भोजपुर जैसे जिले भी हैं, जिनमें अधिक यादव वोटर होने के बावजूद बहुत कम नाम काटे गए। वहीं सारण, मुजफ्फरपुर या दरभंगा जैसे जिलों में सवर्ण आबादी अधिक होने के बावजूद बहुत वोटरों के नाम कटे हैं। यह बात भी सामने आ रही है कि जिन जिलों में अधिक नाम काटे गए हैं, वे अपेक्षाकृत गरीब जिले हैं। क्या इन जिलों से बिहार से लोगों के पलायन का कोई पैटर्न है?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ट्रम्प

अमेरिका की जनता को ही ट्रम्प का विरोध करना होगा

ट्रेड-वॉर

कौशिक बसु
विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट

फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों को अपवाद मान लिया जाए तो अमेरिका के इतिहास में कार्यकारी आदेशों और विधायी गतिविधियों की ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई थी, जैसी ट्रम्प के राज में आई है। रूजवेल्ट से तुलना करें भी तो उनकी 'न्यू डील' अमेरिका को महामंदी से निकालने का एक क्रांतिकारी और सफल प्रयास था। इसके उलट, ट्रम्प की नीतियों के पीछे कोई स्पष्ट, तात्कालिक कारण नहीं नजर आ रहा- क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उनके पदभार संभालने से पहले ही बेहतर प्रदर्शन कर रही थी।

एक समय अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना दबदबा रखता था और ट्रम्प इसमें नए प्राण फूंक देना चाहते हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि वे ऐसा कर पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ट्रम्प के आर्थिक एजेंडे में शीर्ष पर है। अप्रैल के बाद से उन्होंने दुनिया के लगभग हर देश पर जैसे-को-तैसा टैरिफ लगाए, और फिर बार-बार उनमें फेरबदल किया। कुछ को हटाया, कुछ को कम किया। कई मामलों में बहाल किया या बढ़ा भी दिया। नतीजा यह है कि औसत प्रभावी अमेरिकी टैरिफ दर 2024 के 2% के मुकाबले अब बढ़कर 16% से अधिक हो गई है। 1930 के दशक के बाद का यह उच्चतम स्तर है।

जहां विशेषज्ञों ने चेताया है कि उच्च टैरिफ दरों से अमेरिका में घरेलू महंगाई बढ़ सकती है, वहीं असली जोखिम कहीं और है। टैरिफ के कारण मैक्सिको, कनाडा, भारत से आयातित चीजों की कीमतें बढ़ने से उत्पादन लागतें बढ़ेंगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता घटेगी। इससे निर्यात में कमी आएगी और कामकाजी वर्ग की आय घटेगी। ट्रम्प का 'बिग ब्यूटीफुल बिल' निम्न-मध्यम आय वर्ग के अमेरिकियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और अमेरिकी घाटे में लाखों-करोड़ों डॉलर की बढ़ोतरी कर देगा। यह बिल जहां स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सहायता कार्यक्रमों में कटौती करता है, वहीं यह अमीरों को टैक्स में छूट देता है।

यदि नीतियों को जल्द ही बदला नहीं गया तो अर्थव्यवस्था पर इसका विनाशकारी प्रभाव होगा। भले ही कीमतों पर फिलहाल सीमित असर दिख रहा हो, लेकिन ऊंचे टैरिफों से जीडीपी वृद्धि धीमी होगी और खासतौर पर कामकाजी वर्ग के वेतनों पर चपत लगेगी।

मुख्यधारा के अर्थशास्त्री अकसर इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि आर्थिक प्रदर्शन नीतिगत निर्णयों के अलावा भी कई चीजों से प्रभावित होता है। जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा है कि यह घरेलू संस्थानों की मजबूती, देशों के भीतर और उनके बीच आपसी भरोसे पर निर्भर करता है। साथ ही यह उस पर भी निर्भर करता है, जिसे जोसेफ एस. नाय ने 'सॉफ्ट पावर' कहकर पुकारा है। लेकिन ट्रम्प ने संस्थानों पर तीखे प्रहार किए हैं। उनके प्रशासन ने प्रमुख विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय छात्रों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इससे अमेरिका की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं में भरोसा कमजोर हुआ है।

डॉलर में भरोसा घटने का जोखिम तो और बड़ा है, क्योंकि वही अमेरिका के आर्थिक दबदबे का आधार रहा है। मुझे 5 अगस्त, 2011 की घटना याद है, जब 'स्टैंडर्ड एंड पुअर्स' ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटा कर AA+ कर दिया था। उस समय मैं भारत सरकार के सलाहकार के रूप में कार्यरत था और मैंने वैश्विक वित्तीय बाजारों पर इसके संभावित असर को लेकर बड़े पैमाने पर अनिश्चितता के दृश्य देखे थे।

विडंबना ही थी कि इस डाउनग्रेडिंग से अमेरिका में और धन आने लगा, क्योंकि सुरक्षित निवेश की तलाश में डॉलर सम्पत्तियां खरीदने की होड़ मच गई थी। दशकों से डॉलर पर बना यह भरोसा उसके प्रभुत्व की वजह रहा है। इसी कारण अमेरिका 28 ट्रिलियन डॉलर का बाहरी ऋण इकट्ठा करने में सक्षम हुआ, जो किसी भी देश से अधिक है। अमेरिका को इसका महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ मिलता है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी भी छिपी है। यदि डॉलर पर भरोसा कम हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद हिल जाएगी!

यदि यही ट्रेंड्स जारी रहे तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं और डॉलर से भरोसा उठ सकता है। एकमात्र उम्मीद यह है कि अमेरिकी जनता ट्रम्प की आत्मघाती नीतियों का कड़ा विरोध करे और उन्हें अपना रुख बदलने को मजबूर करे।

ट्रम्प के राज में अमेरिकी नीतियों में आए बदलावों ने वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर दिया है। यदि यही ट्रेंड्स जारी रहे तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। डॉलर से भरोसा उठ सकता है और अमेरिकी सम्पत्तियों से पलायन के दृश्य सामने आ सकते हैं। एकमात्र उम्मीद यह है कि अमेरिकी जनता ट्रम्प की आत्मघाती नीतियों का कड़ा विरोध करे और उन्हें अपना रुख बदलने को मजबूर करे। लेकिन यदि ट्रम्प का यही रवैया कायम रहा तो अमेरिका को वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनका रूजवेल्ट को समाधान करना पड़ा था। लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था को दुबारा पटरी पर नहीं लाया जा सकेगा। (© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

9 अगस्त के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने गाजा में इजराइल की मनमानी पर कवर स्टोरी की है। मैगजीन ने अमेरिका में किस्तों पर खरीदारी के बढ़ते ट्रेंड को भी सामने रखा है।

The Economist

दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

चीन में एआई इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी

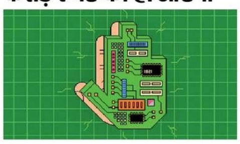

चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हांगझाउ के उपनगर लियांगझू में कई नई कंपनियां आगे आई हैं। पूरे चीन से इन्वेस्टर यहां आकर पैसा लगा रहे हैं। छह माह पहले एक अज्ञात एआई स्टार्टअप डीपसीक के चैटबॉट ने हलचल मचाई थी। पिछले माह तीन चीनी लैबोरेटरी ने बड़े लैंग्वेज मॉडल पेश किए हैं। मोर्गन स्टेनले बैंक का अनुमान है, चीन की एआई इंडस्ट्री पिछले साल के 28 हजार करोड़ के मुकाबले 2030 में बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी।

अमेरिका में प्रजनन दर में भारी गिरावट आई

अमेरिका में 1960 में प्रजनन दर या एक महिला के बच्चों की औसत संख्या 3.6 थी। 2022 में यह गिरकर 1.7 रह गई। डिसीज कंट्रोल प्रिवेंशन सेंटर्स के नए डेटा के मुताबिक अब यह आंकड़ा 1.6 हो गया है। यह सबसे कम है। हर राज्य में महिलाओं के बच्चे पहले की तुलना में कम हैं। अलास्का, नॉर्थ डकोटा और उटा में पहले सबसे ज्यादा बच्चे जन्म लेते थे। अब वहां सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। कनेक्टीकट और मेसाचुसेट्स सहित पांच में से चार कम प्रजनन दर वाले राज्यों में गिरावट राष्ट्रीय औसत से नीचे चली गई है। ताजा गिरावट अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में आई है।

दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन छोड़ सकती है

ब्रिटेन की संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था के बीच लाइफ साइंसेस सेक्टर उम्मीद की किरण जगाता है। 12.70 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री से तीन लाख लोगों को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर कहते हैं, यह हमारी ठहरी अर्थव्यवस्था का रॉकेट फ्यूल है, लेकिन ब्रिटेन की सबसे कीमती लिस्टेड कंपनी एस्ट्राजेनेका सरकार के कुछ फैसलों से असंतुष्ट है। कंपनी के सीईओ सर पास्कल सोरिओट ने कंपनी की लिस्टिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में करने के संबंध में बातचीत की है। उन्होंने 29 जुलाई को कंपनी के छमाही नतीजों की घोषणा के साथ एस्ट्राजेनेका को अमेरिकन कंपनी कहा।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

स्पेशल स्टोरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थकों के बीच भी कमजोर हो रहा नेतन्याहू का समर्थन

गाजा युद्ध में सभी कानून टूटे, दुनिया लाचार

14 मई 1948 को आजादी के घोषणापत्र में इजराइल ने सभी धर्म, नस्ल और जेंडर के मानव अधिकारों को मानने का वादा किया था। यूएन जिनेवा कन्वेंशन में मानवीय गरिमा की हिफाजत पर भरोसा जताया गया था। आज गाजा में इन दोनों भावनाओं की अनदेखी हो रही है। युद्ध के कानूनों का घोर उल्लंघन हो रहा है। उसे पटरी पर लाने का सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। इजराइल का कानूनी सिस्टम स्वतंत्र माना जाता रहा है, लेकिन गाजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल भी चुप हैं। वैसे, इजराइल के बारे में समर्थकों की राय बदल रही है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्रपति ट्रम्प के समर्थकों के बीच इजराइल का समर्थन कमजोर पड़ा है।

7 अक्टूबर 2023 को नागरिकों की हत्या के बाद आतंकवादियों के खिलाफ शुरू हुआ इजराइल का युद्ध गलत रास्ते पर जा चुका है। गाजा में बड़े पैमाने पर मौत और तबाही हो चुकी है। वह खंडहर हो चुका है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों मारे गए हैं। फिर भी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रुक रहे हैं। वे समूचे गाजा को हथियाना चाहते हैं। हमास से अब कोई सैनिक खतरा नहीं है। इसलिए युद्ध जायज नहीं रहा। इजराइल ने नागरिकों को भोजन की सप्लाई का हमास के खिलाफ हथियार के बतौर इस्तेमाल किया है। वह नस्लीय सफाए में जुटा है।

हमास ने 22 माह पहले इजराइलियों को बंधक बनाने के साथ वर्तमान गाजा टकराव की शुरुआत की थी। उसने शांति की बजाय अपने लोगों की व्यथा को भुनाया है। हमास ने अभी हाल में ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता के वादों को 7 अक्टूबर का नतीजा बताया है। फिर भी, हमास के अपराध इजराइल के लिए बहाना नहीं हो सकते हैं। गाजा के मामले में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कारगर नहीं रही हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेअसर रहा है। इजराइल के कानूनी सिस्टम की कार्रवाई से पहले ही कोर्ट ने नेतन्याहू और उनके तत्कालीन रक्षा मंत्री के खिलाफ वारंट जारी कर दिए। अमेरिका और चीन सहित बड़ी ताकतें अदालतों को नहीं मानती हैं। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आने में समय लगता है। उसे लागू करना भी कठिन है।

युद्ध के कानूनों की वजह से पहले भी कुछ उद्दंड शासकों ने स्वयं पर नियंत्रण लागू किया है। लिहाजा, कुछ सवाल उठते हैं। क्या लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित इजराइल अब भी खुद पर काबू रखने की परंपरा का पालन करेगा? क्या इजराइल गाजा में भोजन और दवाइयों की सप्लाई शुरू करेगा। एक अन्य सवाल है, क्या वह युद्ध खत्म होने पर नए प्रधानमंत्री के अधीन स्वतंत्र जांच आयोग बनाएगा? यह सब करने के लिए बाहरी दुनिया खासकर अमेरिका की भूमिका अहम है। गाजा में शांति से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को क्षेत्र में स्थिरता और इजराइल-सऊदी अरब के रिश्तों को नए सिरे से बनाने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने पहले भी इजराइल के युद्ध रोके हैं।

विश्लेषक मानते हैं, यदि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा कर वहां के लोगों को कुचल देता है तो हिंसा नहीं रुकेगी। जिनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों का सार है कि बेशर्मी से कानून तोड़ने वाले देश न सिर्फ पीड़ितों को बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इजराइल गाजा में नस्लीय सफाए और भुखमरी को महिमामंडित करता है तो उसकी राजनीति और समाज तानाशाही की ओर बढ़ेंगे।

सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल भी खामोश

अतीत में इजराइल ने युद्धों की जांच की है। कुछ राजनेताओं और सैनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अन्य देशों की तुलना में उसने सैनिकों के जुल्म की जांच की है। अलबत्ता, जांच की गति धीमी रही है। उसका फोकस निचले स्तर पर रहा, लेकिन अब तो जवाबदेही की कमी नजर आती है। इजराइल का सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल नेतन्याहू से सत्ता संघर्ष में उलझे हुए हैं। वे गाजा पर सरकार की आलोचना के मामले में खामोश हैं।

यूरोप-यूएस में रुख बदल रहा

इस सप्ताह इजराइल के 600 पूर्व सैनिक अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रम्प से युद्ध रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की है। वहीं कुछ इजराइली मानते हैं कि वे इस समय अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिमी देशों से रिश्ते बाद में सुधारे जा सकते हैं, लेकिन यूरोप में इजराइल के बारे में अच्छी राय नहीं है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और ट्रम्प समर्थकों के विचार भी बदल रहे हैं।

60 हजार से अधिक मौतें

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 29 जुलाई तक युद्ध में 60 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके थे। हजारों लोग अब भी मलबे में दबे हैं। रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी, लंदन के अनुसार जनवरी 2025 तक दवाइयों, खाने की कमी से 4500 से 12500 लोगों की मौत हुई। इजराइली खुफिया एजेंसियां मृतकों की संख्या 20 हजार बताती हैं। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक गाजा में 60% इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

टैक्नोलॉजी

उबर ड्राइवरलेस कारों की संख्या तेजी से बढ़ा रही

70 देशों के दस हजार शहरों में टैक्सी सेवाएं चला रही कंपनी उबर देर से पटरी पर लौट रही है। 16 साल पहले बनी कंपनी को पहली बार 2023 में मुनाफा हुआ था। उसने 2024 में 24500 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया था। 2025 की दूसरी तिमाही में यह और बढ़ गया है। कंपनी ने 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शेयरों की खरीद का एलान किया है। 6 अगस्त को कंपनी के नतीजों की जानकारी देते हुए उबर के चीफ दारा खोसरोशाही ने बताया कि ड्राइवर लेस रोबो टैक्सी सेवा के मामले में हम अब भी शुरुआती दौर में हैं। कंपनी अमेरिका में 1500 और चीन में 2000 रोबो टैक्सी चला रही है। गोल्डमैन सॉक्स बैंक का अनुमान है, 2030 तक अकेले अमेरिका में 35 हजार ड्राइवरलेस टैक्सी चल सकती हैं। कंपनी ने सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की यूनिट को 24 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 2020 में बेच दिया था। अन्य कंपनियों की कामयाबी के बाद उबर ने फिर से सेल्फ ड्राइविंग प्रोजेक्ट में हाथ डाला है। उसने कार मेकर फॉक्सवैगन के साथ करार किया है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन ताजा हो रही डरावने दौर की याद

दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया है

जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले से बचे लोगों को अंतहीन पीड़ा की स्थिति से गुजरना पड़ा है। तनाका शिगेमित्सू कहते हैं, वह नर्क जैसी स्थिति थी। नागासाकी में जब परमाणु बम गिरा तब शिगेमित्सू चार साल के थे।

6 और 9 अगस्त 1945 को जापान में परमाणु बम गिराए गए थे। हिबाकुशा एसोसिएशन निहोन हिडानक्यो के प्रमुख तनाका कहते हैं, पिछले 80 वर्षों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का इतना खतरा पहले कभी नहीं रहा है। परमाणु हमले से जीवित बचे लोगों को हिबाकुशा कहते हैं। रूस के यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी से नए युग की शुरुआत हुई है। परमाणु हथियार सीमित करने के लिए अमेरिका व रूस के बीच नई स्टार्ट संधि अगले साल खत्म हो रही है। परमाणु हथियार बढ़ रहे हैं। पोलैंड, सऊदी अरब व दक्षिण कोरिया जैसे देशों में परमाणु हथियार बनाने पर चर्चा हो रही है। जापान तक में बम हासिल करने की बात होने लगी है।

भविष्य के लिए ट्रेनिंग

हिरोशिमा-नागासाकी में भावी पीढ़ियों के लिए हिबाकुशा की यादों को बनाए रखने के प्रयास हो रहे हैं। लोगों को हिबाकुशा की कहानियां बताने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जापान सोचता है कि परमाणु हथियारों का हमला झेलने वाला एकमात्र देश होने से उसकी खास जिम्मेदारी है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

फाइनेंस बीएनपीएल यानी अभी खरीदिए और बाद में चुकाइए

पे-लेटर : बीते वर्ष 30 लाख करोड़ की खरीदारी

दुनिया के बहुत देशों में इस वक्त खरीदिए और बाद में पैसा चुकाइए (बीएनपीएल) का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग खाने-पीने का सामान, थिएटर टिकट और बोटॉक्स इंजेक्शन तक ऑनलाइन मंगवाते हैं। फिर पैसा किस्तों में चुकाते हैं। यह इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। पेमेंट फर्म वर्ल्ड पे के अनुसार पिछले साल विश्व में बीएनपीएल खर्च लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रहा। यह दस साल पहले 17500 करोड़ रुपए था।

अमेरिका और अन्य देशों में जेपी मोर्गन चेज, पेपाल जैसी पुरानी फाइनेंशियल कंपनियां भी मार्केट में आ गई हैं। बिक्री के समय लोन देने का आइडिया पुराना है। 1856 में इसाक सिंगर और एडवर्ड क्लार्क ने किस्तों पर सिलाई मशीनें बेचना शुरू किया था। आधुनिक इंडस्ट्री इसी तरीके से काम कर रही है। 100 डॉलर का प्रोडक्ट खरीदने वाला कस्टमर किस्तों में रकम चुका सकता है। बदले में स्वीडिश कंपनी क्लारना और बड़ी अमेरिकन फर्म एफर्म जैसी उधार देने वाली कंपनियां 3 डॉलर लेती हैं। कर्ज लेने वाले कस्टमर उन लोगों से 20 प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं, जिन्हें कर्ज नहीं मिलता है।

अमेरिका में यह इंडस्ट्री सफलता के बावजूद शुरुआती दौर में है। स्वीडन में पांच में एक ऑनलाइन बिक्री इससे हुई। वहीं अमेरिका में 16 में से एक बिक्री बीएनपीएल के खाते में गई। कोलंबिया में एडी, सिंगापुर में एटोम और सऊदी अरब में टमारा जैसी कंपनियां मैदान में हैं।

2017 तक क्लारना यूरोप में एक बैंक था। कंपनी के बॉस सेबास्टियन सीमियाकोवस्की कहते हैं, वह इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला डिजिटल फाइनेंशियल असिस्टेंट बनाना चाहते हैं।

बड़े वालेट्स से संबंध

पिछले दो साल में बीएनपीएल कंपनियां एपल और गूगल के डिजिटल वालेट्स से जुड़ गई हैं। पेपाल ने इसकी शुरुआत 2020 में की थी। पिछले साल उसने 2.85 लाख करोड़ रुपए के बीएनपीएल पेमेंट किए हैं। कई बैंक बड़े पेमेंट कई हिस्सों में चुकाने की सुविधा देने लगे हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

कल्पमेधा

सही मायने में बुद्धिपूर्ण विचार हजारों दिमागों में आते रहे हैं, लेकिन उनको अपना बनाने के लिए हमें उन पर गहराई से तब तक विचार करना चाहिए, जब तक कि वे हमारी अनुभूति में जड़ न जमा लें।
- गोथे

पारदर्शिता का तकाजा

किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती और विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सरकार के चुने जाने की प्रक्रिया कितनी स्वच्छ, स्वतंत्र और पारदर्शी है। इसके लिए चुनाव आयोजित कराने वाली संस्था को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न हो, मतदान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तथा चुनाव में हिस्सेदारी करने वाले सभी दलों के लिए भरोसेमंद हो और नतीजों को लेकर सभी पक्ष संतुष्ट हों। मगर देश में होने वाले अमूमन हर चुनाव के बाद जिस तरह के विवाद सामने आते रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के समूचे तंत्र के साथ-साथ नतीजों तक को लेकर जैसे सवाल उठे हैं, उससे कई तरह की आशंकाएं खड़ी हुई हैं। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से कई जगहों पर हुए मतदान और उसमें हुई गड़बड़ियों के संदर्भ में चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए हैं, वे अपनी प्रकृति में बेहद गंभीर हैं और स्वाभाविक ही इस पर चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टता की अपेक्षा की जा रही है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि लोकसभा चुनावों, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा सामने रखते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर, फर्जी मतदाता, गलत पते, एक पते पर कई मतदाता, एक मतदाता का नाम कई जगह की सूची में होने जैसे कुछ खास तरीकों पर आधारित 'वोट चोरी' करने के इस माडल को कई निर्वाचन क्षेत्रों में अमल में लाया गया, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। हालांकि चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन आमतौर पर वे किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकीं या फिर निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें निराधार घोषित किया जाता रहा है। अब इस बार जिस गंभीर स्वरूप में इस मामले को उठाया गया है, उसके बाद देश भर में यह बहस खड़ी हो गई है कि अगर इन आरोपों का मजबूत आधार है तो इससे एक तरह से समूची चुनाव प्रक्रिया की वैधता कठघरे में खड़ी होती है।

इस मसले पर चुनाव आयोग ने फिलहाल कोई जवाब देने के बजाय राहुल गांधी से शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर कर शिकायत देने या फिर देश की जनता को गुमराह न करने को कहा है। मगर राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' का दावा करते हुए जिस तरह अपने आरोपों को सबूतों पर आधारित बताया है, उसके बाद चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह समूची चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे को बहाल रखने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ इस संबंध में उठे सवालों का जवाब सामने रखे। अगर वास्तव में कोई गड़बड़ी रही है, तो कमियों को स्वीकार करके उसमें सुधार करना देश के हित में ही होगा। यों भी, मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम हटाने और जोड़ने या फर्जी मतदान के जरिए नतीजों को प्रभावित करने को लेकर हर चुनाव के बाद विवाद खड़े होते रहे हैं। बिहार में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में भी लाखों मतदाताओं को बाहर किए जाने को लेकर कई सवाल उठे हैं। ऐसे में समूची चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ मतदान और नतीजों के संबंध में सौ फीसद पारदर्शिता तथा ईमानदारी सुनिश्चित होने को लेकर आम लोगों के बीच भरोसा होना लोकतंत्र के जीवन के लिए जरूरी है।

अधिकार और सीमा

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यशैली और उसकी भूमिका पर आए दिन सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक दलों का आरोप है कि ईडी प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करती है। वहीं उच्च न्यायालयों से लेकर शीर्ष अदालत ने भी निदेशालय को कई बार सवालों के कठघरे में खड़ा किया है। यह अफसोसनाक है कि ईडी की जांच में आरोपी बनाए गए लोग दोषी सिद्ध न होने पर भी महीनों विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद रहते हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि धनशोधन रोकथाम कानून का दुरुपयोग कैसे और क्यों हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। इस कानून के तहत दोषसिद्धि दर पर भी सवालिया निशान लग चुके हैं। गुरुवार को शीर्ष न्यायालय ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि धनशोधन मामलों में सजा की दर बहुत कम है। अदालत ने ईडी को सख्त लहजे में चेताया है कि वह किसी गुंडे की तरह काम नहीं कर सकती, उसे कानून के दायरे में रह कर काम करना होगा। अदालत की टिप्पणी ईडी की जांच प्रक्रिया और कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। अगर इस संस्था की छवि इस कदर नकारात्मक बन रही है, तो इस पर उसे सोचने की जरूरत है।

ऐसा नहीं है कि शीर्ष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज पर कोई पहली बार सवाल उठाया है। पिछले महीने भी अदालत ने कहा था कि ईडी सारी हदें पार कर रही है। यह गंभीर स्थिति है कि न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आरोपी जेल से बाहर आ जाते हैं। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय न तो अपनी जांच पूरी कर पाता है और न ही उनके खिलाफ आरोप सिद्ध कर पाता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि अगर ईडी के पास किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मजबूत आधार होता है तो दोषसिद्धि की दर दस फीसद से भी कम क्यों है। इस पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने उचित सवाल किया है कि अगर आरोपी बरी हो जाते हैं, तो इसका भुगतान कौन करेगा। यह बेकसूर नागरिकों की स्वतंत्रता का भी सवाल है। ईडी की छवि पर अगर प्रश्न उठ रहे हैं, तो इसका निवारण अब उसे ही करना होगा। इस संदर्भ में ईडी को शीर्ष अदालत की इस नसीहत पर गौर करने की जरूरत है कि उसे कानून की सीमा में काम करना चाहिए।

सतत विकास की मंद रफ्तार

संयुक्त राष्ट्र की एक रपट के मुताबिक, सतत विकास 2030 का एजंडा अपनाने से वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है। मगर चिंता की बात है कि विश्व के कई देश अपने लक्ष्यों को पाने से अभी बहुत दूर हैं।

अनिरुद्ध गौड़

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की दसवीं रपट में पाया गया है कि सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजंडा अपनाने से वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है। मगर अभी भी बहुत से लक्ष्यों में प्रगति अपर्याप्त है। चिंता की बात है कि सभी लक्ष्यों को पाने के लिए निर्धारित पंद्रह वर्ष में से दस वर्ष बीत गए हैं और अब सिर्फ पांच वर्ष रह गए हैं। जबकि, विश्व के कई देश अपने लक्ष्यों को पाने से अभी बहुत दूर हैं। केवल 35 फीसद लक्ष्य ही सही रास्ते पर चल रहे हैं। इस तरह वैश्विक स्तर पर प्रगति अभी पटरी पर नहीं है। सवाल यह है कि अगर लक्ष्यों को पाने की गति ऐसी ही रही तो क्या वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर इन्हें हासिल किया जा सकता है!

भारत की बात करें तो कुल 193 देशों में 17 सतत विकास लक्ष्यों को पाने में भारत ने निर्धारित अधिकतम 100 अंकों में से 66.95 अंक प्राप्त कर 99वां स्थान पाया है। पिछले वर्ष 2024 में इन लक्ष्यों की प्रगति में भारत 109वें और 2023 में 112वें स्थान पर था। यानी इस वर्ष भारत ने महत्त्वपूर्ण प्रगति करते हुए वैश्विक रैंकिंग में 100 देशों की श्रेणी में जगह बना ली है। हालांकि, भारत को वर्ष 2030 तक सभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे। क्योंकि, कई क्षेत्रों में भारत पिछड़ा हुआ है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश 114वें और पाकिस्तान 140वें स्थान को छोड़ दिया जाए तो चीन 49वें, भूटान 74वें और नेपाल 85वें स्थान पर हैं। यही नहीं, लक्ष्यों की प्रगति में समुद्री पड़ोसी देश मालदीव 53वें और श्रीलंका 93वें स्थान के साथ भारत से आगे हैं।

संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) हर साल न्यूयार्क में आयोजित होता है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर समीक्षा की जाती है। गत 14 से 23 जुलाई के बीच संपन्न हुए दस दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन जारी हुई दसवीं रपट में कहा गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और 'डिजिटल कनेक्टिविटी' में विश्व स्तर पर प्रगति से लाखों लोगों के जीवन में सुधार तो आया है, लेकिन वर्ष 2030 तक लक्ष्यों को पूरा करने की गति धीमी है। अभी केवल 35 फीसद लक्ष्य ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 31 फीसद लक्ष्यों में मामूली प्रगति है। जबकि 17 फीसद में ठहराव आया हुआ है और 18 फीसद लक्ष्य तो बहुत पीछे चल रहे हैं। एसडीजी संकल्प के दस साल बाद एजंडा 2030 को कई नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विकासशील देशों में विकास के लिए चार हजार अरब डालर की कमी है। स्थिति यह है कि वर्ष 2025 की सतत विकास लक्ष्य रपट में किसी भी देश ने अपने सतत विकास लक्ष्यों में सौ फीसद लक्ष्य प्राप्त करने में अभी तक सफलता नहीं पाई है।

सतत विकास लक्ष्यों के संकल्प के इतिहास में जाएं तो अब से दस वर्ष पहले 25 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में संपन्न संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने विश्व स्तर पर आर्थिक सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास के विभिन्न आयामों को संतुलित करने के प्रयास को लेकर सत्रह वैश्विक लक्ष्यों और इनसे जुड़े 169 विशिष्ट लक्ष्यों को अपनाया था। इन लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य

और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचे, असमानताओं में कमी, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पानी के

> **सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति की बात की जाए तो दुनिया में एचआइवी संक्रमण में लगभग 40 फीसद की गिरावट आई है। मलेरिया की रोकथाम से 1.27 करोड़ लोगों की जान बच पाई। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या तक सामाजिक सुरक्षा पहुंच गई है। वर्ष 2023 तक विश्व की 92 फीसद आबादी को बिजली की आपूर्ति की जा चुकी है। वर्ष 2015 में 40 फीसद लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे, जो 2024 में 68 फीसद तक हो गया। मगर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 80 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी में गुजर-बसर कर रहे हैं। विश्व के करोड़ों लोगों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली हैं।**

नीचे जीवन, जमीन पर जीवन, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं एवं साझेदारियां शामिल हैं। साथ ही इन लक्ष्यों को एक जनवरी 2016 से 2030 तक पंद्रह वर्षों में पूरा करने के लिए सभी देशों ने प्रतिबद्धता भी जताई थी। तब से इन सत्रह लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक देश की प्रगति के तौर पर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से रपट जारी की जाती है। लेकिन चिंता की बात है कि अब सिर्फ पांच वर्ष रह गए हैं और कई देश इन लक्ष्यों को पाने में किए गए संकल्प से काफी पीछे हैं।

दुनिया भर में काफी उथल-पुथल हो रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और गाजा के अलावा ईरान, सीरिया आदि में युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कई लक्ष्यों में वृद्धि हुई है। जैसे एचआइवी संक्रमण में लगभग 40 फीसद की गिरावट आई है। मलेरिया की रोकथाम से 1.27 करोड़ लोगों की जान बच पाई। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या तक सामाजिक सुरक्षा पहुंच गई है। वर्ष 2023 तक विश्व की 92 फीसद आबादी को बिजली की आपूर्ति की जा चुकी है। वर्ष 2015 में 40 फीसद लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे, जो 2024 में 68 फीसद तक हो गया है। यह रपट कई चुनौतियों की ओर भी ध्यान खींचती है। इनमें 80 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी में गुजर-बसर कर रहे हैं। विश्व के करोड़ों लोगों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली हैं। जलवायु परिवर्तन का भी काफी प्रभाव है। 2024 विश्व का सबसे गर्म वर्ष रहा, जिससे तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री अधिक हो गया। वैश्विक शरणार्थी आबादी भी बढ़ रही है। विश्व में 1.12 अरब लोग बुनियादी सेवाओं के बिना झुग्गी-झोपड़ियां या अस्थायी बस्तियों में रहते हैं।

लक्ष्यों में प्रगति की बात की जाए तो वर्ष 2012 और 2024 के बीच पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापान 26.4 फीसद से घटकर 23.2 फीसद रह गया है। वैश्विक मातृ मृत्यु दर एक लाख जीवित जन्मों पर 228 से घटकर 197 हुई है। जबकि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 16 फीसद की कमी आई है। भेदभावपूर्ण कानून को हटाने और लैंगिक समानता ढांचे को स्थापित करने में सकारात्मक कानूनी सुधार लागू हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से वृद्धि के साथ ऊर्जा स्रोत बढ़े हैं। मोबाइल ब्राडबैंड की पहुंच वैश्विक जनसंख्या के 51 फीसद तक पहुंच गई है। कई देशों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 45 देशों ने सार्वभौमिक बिजली तक पहुंच बनाई और 54 देशों ने 2024 के अंत तक कम से कम एक रोग का उन्मूलन किया। लेकिन रपट में कई चुनौतियों से निपटने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति लाने के लिए तत्काल बहुपक्षीय करवाई और वित्तीय सुधार लाने का आह्वान भी किया गया है, क्योंकि अधिकतर लक्ष्य 40 से 42 फीसद से नीचे हुए हैं।

भारत हर वर्ष अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार ला रहा है। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ उर्जा सहित कई क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। मगर अभी भारत को भी अपने लक्ष्यों को पाने में तेजी लानी होगी। दुनियाभर में संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय बाधाएं सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मुख्य तौर पर दिक्कतें पैदा कर रहीं हैं। गरीबी, भुखमरी, असमानता, जलवायु परिर्वतन, पर्यावरण, शांति और न्याय सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं। विश्वस्तर पर बहुपक्षीय सुधार, विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के प्रयास करने होंगे और आपसी संघर्षों को दूर करना होगा। वित्त संघर्षों में जो खर्च हो रहा है, उस धनराशि को पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत विकास की योजनाओं में लगाने से कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

आनंद के सूत्र

प्रेरणा अवस्थी

मानव जीवन प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य वरदान है, लेकिन यह जीवन भी अलग-अलग तरह की इच्छाओं, सुखों और कष्टों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह जीवनपर्यंत सुख और आनंद को भोगना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जिस आनंद की उसे चाह है, वह सच्चा आनंद है ही नहीं। आनंद तो एक ऐसा भाव है जो आत्मा की अनंत गहराइयों से उपजता है। इसका बाह्य वातावरण और परिवेश से लेशमात्र भी लेना-देना नहीं होता है। भौतिकता कभी आनंद का स्रोत नहीं हो सकती। बाहरी जगत की वस्तुएं, व्यक्ति और परिस्थितियां सच्चे आनंद का आधार निर्मित करने में कभी समर्थ नहीं हो सकती हैं। कबीरदास ने कहा है, 'कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग ढूंढ़े बन माहि। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखत नाहि।' ठीक यही स्थिति आज मनुष्य की है। सही मायने में देखा जाए तो सच्चे आनंद के सूत्र स्वयं मनुष्य के पास ही होते हैं, लेकिन बुद्धि और विवेक पर अज्ञानता का आवरण होने के कारण वह उसे पहचानने में असमर्थ एवं असफल रहता है।

आनंद का प्रथम और सबसे अहम सूत्र है- आत्मबोध या आत्मचिंतन। मगर बाह्य विषयों के मायाजाल में बुरी तरह जकड़ा होने के कारण मनुष्य इस अमूल्य सूत्र को ढूंढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाता। उसकी दशा कहीं न कहीं उस हिरन जैसी हो जाती है जो अपनी ही नाभि में स्थित कस्तूरी को नहीं ढूंढ़ पाता और यहां वहां मारा-मारा फिरता है। आत्मचिंतन हमें भले ही कुछ समय के लिए बाह्य जगत की चकाचौंध से दूर लिए जाता है, लेकिन जिस मनुष्य ने एक बार भली-भांति आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन की प्रक्रिया को साध लिया, वह आनंद की एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो दिव्य और अनुपम होती है। आत्मचिंतन और आत्मबोध रूपी कुंजी जिसके हाथ लग गई, वह अनेक व्यर्थ के बंधनों से मुक्ति पाकर स्वयं के आंतरिक जगत में ही अपार प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। आत्मबोध हो जाने पर बाहरी सुख नितांत निम्न कोटि के प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन आनंद की इस दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर पाना भी बेहद दुष्कर कार्य है। इसके लिए हमें बाह्य विषयों से विमुख होते हुए 'स्व' पर केंद्रित होकर अपने आप को जानने के लिए कठिन साधना में रत होना पड़ेगा।

आनंद का दूसरा महत्त्वपूर्ण सूत्र है स्वीकृति। अगर हम सच्चे अर्थों में आनंद के सागर में डूबना चाहते हैं, तो हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां हमारे अनुकूल भी होंगी और प्रतिकूल भी। मगर जहां हमें अनुकूल परिस्थितियों में उत्साह के भाव से ओतप्रोत रहना होगा, वहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। घड़ी-घड़ी परिवर्तनशील जीवन की नौका सदैव हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल सकती। इस सत्य को स्वीकारते हुए जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित मानसिक अवस्था को बनाए रखना आनंद का दूसरा प्रमुख सूत्र है।

आनंद के तीसरे सूत्र के रूप में हम कृतज्ञता पर गौर कर सकते हैं। जब हम छोटे-छोटे अवसरों पर भी दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अहम के भाव से पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। यह अहम का भाव ही है जोकि हमें सच्चे आनंद से दूर ले जाता है। जिस दिन हमारे अंतर्मन से अहं का अंधकार समाप्त हो जाएगा, उसी दिन हमारा अंतर्मन एक दिव्य आनंद के आलोक से जगमगा उठेगा। प्राणियों के प्रति सेवाभाव भी आनंद का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र है। जब हम दूसरों के कष्ट में स्वयं अपने कष्ट को अनुभव करने लगेंगे, तब हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया, करुणा और सेवा की भावना जागृत होगी। ऐसा करके हम आत्मतृप्ति के अद्‌भुत भाव से पूरित हो जाएंगे और आनंद की सरिता हमारे अंतर्मन को पूरी तरह से सिक्त कर देगी।

आनंद कोई क्षणिक भाव नहीं है जो एक बार मन में उत्पन्न हुआ और कुछ ही देर में समाप्त हो गया, बल्कि यह एक गहरा और शाश्वत भाव है जो अगर एक बार अंतर्मन में समा गया, तो फिर हृदय और मन हमेशा के लिए एक अद्‌भुत दिव्यता के भाव से सराबोर हो जाते हैं। बाह्य जगत और बाहरी साधनों में आनंद को ढूंढ़ना पूरी तरह से बेमानी कृत्य होगा। सच्चा आनंद तभी उत्पन्न हो सकता है, जब हम अपने अंतर्मन में कृतज्ञता, करुणा, सहयोग और निस्वार्थ सेवा के भावों को समेटते हुए जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकारना सीख जाते हैं। सच्चा आनंद तो वास्तव में हमारी अंतरात्मा में ही छिपा हुआ है। सिर्फ आवश्यकता अज्ञानता, स्वार्थ और अहंकार के आवरण को हटाने की है। जिस दिन और क्षण हम इन सभी दुर्गुणों से दूर हो जाते हैं, उसी दिन हम सच्चे आनंद तक पहुंचने का मार्ग भी प्राप्त कर लेते हैं।

आनंद एक ऐसा स्थायी भाव है जो मानसिक शांति, आत्मस्वीकृति और आत्मबोध के माध्यम से हृदय की गहराइयों में उत्पन्न होता है। यह निश्चित है कि एक बार सच्चे आनंद का स्वाद मिल जाने पर अन्य सभी छद्म आनंद मूल्यहीन प्रतीत होने लगेंगे। सच्चे आनंद को आत्मसात करने के लिए हमें प्रकृति और उसके सभी अंगों, जैसे साहित्य, संगीत, कला, ध्यान, योग और प्रार्थना से गहरा जुड़ाव रखना होगा, क्योंकि प्रकृति से जुड़कर ही हम सभी कठिनाइयों से मुक्त हो सकते हैं। जीवन की प्रत्येक मुश्किल का समाधान प्रकृति है। जब मुश्किलें ही नहीं रहेंगी तो फिर निस्संदेह जीवन में आनंद ही आनंद होगा। यह कहा जा सकता है कि सच्चे आनंद के सूत्र खुद हमारे अंदर ही निहित हैं। उन्हें कहीं भी बाहर जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है।

दुनिया मेरे आगे

> **आनंद कोई क्षणिक भाव नहीं है जो एक बार मन में उत्पन्न हुआ और कुछ ही देर में समाप्त हो गया, बल्कि यह एक गहरा और शाश्वत भाव है जो एक बार अंतर्मन में समा गया, तो फिर हृदय और मन हमेशा के लिए एक अद्‌भुत दिव्यता के भाव से सराबोर हो जाते हैं। बाह्य जगत और बाहरी साधनों में आनंद को ढूंढ़ना पूरी तरह से बेमानी कृत्य होगा।**

रिश्तों की अहमियत

भाई-बहन का पर्व रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जो रिश्ते सहेजने का सार्थक संदेश देता है। यह बहनों द्वारा भाइयों की लंबी उम्र की कामना और भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा के वचन का भी त्योहार है। हमारे देश में पर्व न केवल परंपरा और संस्कृति दर्शाते हैं, बल्कि हर त्योहार का अपना एक अर्थ है और इनके साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। बदलते परिवेश में व्यस्तता के कारण ज्यादातर लोगों ने मेल-जोल कम कर दिया है और त्योहारों की रौनक फीकी पड़ती जा रही है। भाई-बहन के रिश्तों में पैसे और जमीन-जायदाद को लेकर भी मतभेद हो रहे हैं। रिश्तों में अपनापन और प्रेम विलुप्त हो रहा है। ऐसे में त्योहार न सिर्फ फीके हो रहे हैं, बल्कि अपनी आभा खो रहे हैं। इन सबके बावजूद भागती-दौड़ती जिंदगी में भी रिश्तों की अपनी अहमियत अभी बची हुई है और यह हमेशा रहेगी, चाहे जीवन में कितना भी बदलाव क्यों न आए। जरूरत है टूटते रिश्तों को संभालने की, समझने की और आत्मीयता बनाए रखने की। इसी से हम परिवार और समाज को बचा पाएंगे। आज के दौर में यह सबसे जरूरी है।

- अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

हथकरघा की विरासत

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कारीगरों की मेहनत, स्वदेशी वस्त्रों की विरासत को सम्मान और सांस्कृतिक पहचान के लिए समर्पित है। हथकरघा उद्योग को मजबूती प्रदान करने एवं दुनिया में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए हर वर्ष अगस्त में हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह वर्षों की सांस्कृतिक परंपरा, कलात्मकता एवं राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, मध्यप्रदेश की चंदेरी और बिहार के भागलपुरी सिल्क को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। हथकरघा उद्योग महिला सशक्तीकरण में भी भूमिका निभाता है। आज फैशन के दौर में विदेशी कपड़ों और मशीन निर्मित वस्त्रों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। हम सभी को हथकरघा उद्योग से निर्मित वस्त्रों को पहनावे में शामिल करना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

- हिमांशु शेखर, गयाजी

विनम्रता का बल

मनुष्य के व्यक्तित्व की असली पहचान उसके आचरण से प्रकट होती है। पद, प्रतिष्ठा या धन का प्रभाव क्षणिक हो सकता है, परंतु विनम्रता का प्रभाव स्थायी होता है। विनम्र व्यक्ति अपनी सरलता, सहजता और मधुर वाणी से सबके हृदय में स्थान बना लेता है। अक्सर सफलता पाकर मनुष्य में अहंकार जन्म लेता है। वह स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरों को महत्त्वहीन। यही अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। इतिहास साक्षी है अहंकारी राजा भी नष्ट हुए। विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह वह शक्ति है, जो व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा कर भी जमीन से जोड़े रखती है। नम्रता सच्चा सद्‌गुण है। गुणों के साथ विनम्रता का मेल व्यक्ति को आदरणीय बना देता है। कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं। जबकि विनम्र व्यवहार संबंधों को मजबूत करता है। इसलिए विनम्र रहें, क्योंकि यही गुण जीवन को सार्थक, समाज को सौहार्दपूर्ण और व्यक्ति को महान बनाता है।

- अमन सिंह गौर, वाराणसी

आभासी संजाल

आज का मनुष्य भौतिक संसाधनों से घिरा हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक अस्थिर होता जा रहा है। बाजारवाद और विज्ञापनों ने सुख की परिभाषा को उपभोग से जोड़ कर हमारे मानसिक संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। स्मार्टफोन, एआइ और तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन साथ ही इसने इंसान को आभासी दुनिया में उलझा दिया है। दिन के कई घंटे मोबाइल पर बिताने की आदत ने न केवल शारीरिक सक्रियता कम कर दी है, बल्कि मानसिक सक्रियता और एकाग्रता पर भी असर डाला है। लोग पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, अवसाद और गुस्सा अब आम मानसिक लक्षण बन गए हैं। मानसिक रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं और प्रौढ़ों में अनिद्रा, तनाव तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति चिंताजनक रूप से बढ़ी है।

- विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

भारत में हरित ऊर्जा

समाधान है जैव ईंधन

धरती हमारा घर है और यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हम रह सकते हैं क्योंकि और ऐसा कोई ग्रह हमारी जानकारी में नहीं है जो वैकल्पिक रूप से रहने योग्य हो। मगर हमने इसके पर्यावरण को तबाह किया है और जीवन को बनाए रखने की इसकी क्षमता को भारी छति पहुंचाई है। हमारे लापरवाह रवैये के कारण इसकी हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित हुई है। पिछले लगभग सौ वर्षों में हमने इसका तापमान काफी बढ़ा दिया है। हालाँकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से वर्तमान वैश्विक औसत तापमान वृद्धि लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर और भी ज्यादा चरम मौसम की घटनाएं होंगी, जैव विविधता का नुकसान बढ़ेगा और ध्रुवीय बर्फ की चादरें और पिघलेंगी। अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वर्तमान दर को उलटा नहीं किया गया तो हमारी आंखों के सामने विनाशकारी आपदाएं सामने आएंगी।

लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास समाधान तैयार हैं, लेकिन उन्हें पूरी गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। हमें शुद्ध-शून्य लक्ष्यों और ऊर्जा विविधीकरण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, जैव ईंधन एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरा है। उनकी क्षमता को पहचानते हुए, द पायनियर बायोफ्यूल्स 360 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो नीति, उद्योग, वित्त, शिक्षा और नवाचार के हितधारकों को एकजुट करने वाला एक वैश्विक मंच है।

भारत ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के प्रयासों के साथ, यह शिखर सम्मेलन देश की हरित ऊर्जा यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है। यह शिखर सम्मेलन जैव ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र के पूरे क्षेत्र में संवाद, कार्रवाई और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है, इथेनॉल और बायोडीजल से लेकर दूसरी और तीसरी पीढ़ी के ईंधन तक। भारत के जलवायु लक्ष्यों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की तत्काल आवश्यकता की पृष्ठभूमि में, यह शिखर सम्मेलन केवल एक सम्मेलन से कहीं अधिक है। यह नीति निमार्ताओं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, उत्पादकों, स्टार्ट-अप्स, शिक्षाविदों और युवाओं सहित नेताओं का एक रणनीतिक जमावड़ा है।

बायोफ्यूल्स 360 डिग्री शिखर सम्मेलन जैव अर्थव्यवस्था में अवसरों और बाधाओं, दोनों पर विचार करता है। नीतिगत संवाद के माध्यम से, यह शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिदेशों, प्रोत्साहनों और नियामक ढांचों की पड़ताल करता है जो जैव ईंधन के बड़े पैमाने पर उपयोग को संभव बना सकते हैं। एक प्रमुख विशेषता 'इनोवेशन एक्सचेंज' है, जहाँ अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और स्थापित उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका उद्देश्य टिकाऊ जैव ईंधन तकनीकों के सहयोग और अपनाने को बढ़ावा देना है। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय निवेश और वित्त है, जिसका उद्देश्य डेवलपर्स को वित्तपोषकों से जोड़ना, टिकाऊ परियोजना पाइपलाइनों को बढ़ावा देना और व्यवहार्य एवं जलवायु-अनुकूल निवेशों को समर्थन देने के लिए आवश्यक जोखिम न्यूनीकरण ढांचे विकसित करना है।

मानव पूँजी के महत्व को स्वीकार करते हुए, शिखर सम्मेलन कौशल और क्षमता निर्माण पर भी जोर देता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आम सहमति बनाना, ज्ञान हस्तांतरण को सक्षम बनाना और कार्यान्वयन योग्य समाधानों को बढ़ावा देना है। पायनियर्स बायोफ्यूल्स 360 डिग्री शिखर सम्मेलन एक सामयिक और रणनीतिक हस्तक्षेप है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि सतत विकास के लिए सहयोग, निवेश और एक साहसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे यह शिखर सम्मेलन आगे बढ़ेगा, यह न केवल संवाद बल्कि दिशा भी प्रदान करेगा - एक ऐसा रोडमैप जो भारत की जैव ईंधन क्रांति को शक्ति प्रदान कर सकता है, और ऐसा करके, दुनिया को एक हरित, अधिक लचीले भविष्य की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है।

अल्पसंख्यकः आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता

वैश्विक अनुभवों और भारत के अपने अतीत से सबक लेते हुए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और समानता और एकीकरण के संवैधानिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए मुस्लिम समुदाय के भीतर आत्मनिरीक्षण और सुधार अनिवार्य है।

प्रफुल्ल गोराडिया
लेखक, राजनीतिक विश्लेषक हैं।

शौकत अली कादरी ने 31 जुलाई को इस प्रतिष्ठित प्रकाशन में अपने लेख में, बुद्धिमानी भरे और उदार सुझाव दिए हैं, ताकि मुसलमान अपनी पहचान बनाए रख सकें और साथ ही भारतीय जनता का अभिन्न अंग बने रहें। इस संबंध में, सबसे पहले उन मजबूरियों का ज़िक्र करना उपयोगी होगा जो वफादार हिंदू नागरिक अपने देश के बारे में महसूस करते हैं। यह देश विशाल है और इसकी जनसंख्या भी उतनी ही बड़ी है। यहाँ की आबादी कई तरह की भाषाएँ बोलती है, बोलियों की तो बात ही छोड़िए। यहाँ कई जातियाँ भी हैं; इनके अलावा, भारत को धार्मिक विविधताओं का भी ध्यान रखना है, देश की विशालता और उसके लंबे और अक्सर विवादास्पद इतिहास के साथ जुड़े नस्लीय मतभेदों की तो बात ही छोड़िए।

भारत ने अगस्त 1947 में शाही ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन सत्ता की बागडोर छोड़ने से पहले, कई पर्यवेक्षकों, जिनमें ज्यादातर अंग्रेज थे, ने भविष्यवाणी की थी कि अगर भारतीय सावधान नहीं रहे, तो उनके देश को अलगाव और विघटन का खतरा हो सकता है। संक्षेप में, मुसलमानों को वह पाकिस्तान देने के बाद जो वे चाहते थे, अब हिंदुओं को सावधान रहना होगा, अगर बहुत ज्यादा नहीं भी। इस हद तक, भारत पश्चिमी दुनिया जैसा विशिष्ट राष्ट्र नहीं है। ऐसे विशिष्ट देश में आदर्श रूप से सभी या अधिकांश नागरिकों की आत्माएं एक साथ सांस लेती होनी चाहिए।

ये ऐसे बिंदु हैं जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों के दिमाग में कभी नहीं आए, पाकिस्तान का जन्म तो एक दिन पहले ही हो गया था। प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपनी विचारधारा का प्रचार किया है, जो आम तौर पर मुसलमानों के कानों को भाती है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि उनकी विचारधाएं देश की अखंडता के लिए भी बेहतर हों। इस्लाम, अपनी शुरूआत से ही, यहूदी धर्म और साम्यवाद की तरह, एक अंतरराष्ट्रीय धर्म रहा है। इन मान्यताओं में, कई लोगों या समूहों का एक साथ आना कोई बड़ी बात नहीं है, न ही किसी देश का टूटना कोई शोक मनाने लायक आपदा है। कर्नल नासिर के राष्ट्रपति काल के दौरान मिस्र और सीरिया का उदाहरण लीजिए।

इन दोनों देशों ने 1958 में कुछ समय के लिए संयुक्त अरब गणराज्य (वअफ) नामक एक संघ का गठन किया, जो 1961 में भंग हो गया। फिर से, पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या को अपने पूर्वी हिस्से के अलग होने से कोई आपत्ति नहीं थी। सोवियत संघ में सोलह गणराज्य शामिल थे।

मास्को ने 1991 में एक दिन इन पंद्रह गणराज्यों को स्वेच्छा से अलग होने दिया और अपनी राह पर चलने दिया। वास्तव में, सोवियत संविधान में यह प्रावधान था कि यदि कोई गणराज्य अलग होना चाहे तो वह अलग हो सकता है। सोवियत संविधान का यह प्रावधान साम्यवादी विचारधारा के अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को दशार्ता है। आधुनिक इजराइल के पहले पैगम्बर, चैम वीजमैन ने कहा था कि पोलिश यहूदी, हंगेरियन यहूदी, रूसी यहूदी, ब्रिटिश यहूदी आदि नहीं हैं, बल्कि फ्रांस में यहूदी, ब्रिटेन में यहूदी, रूस में यहूदी आदि हैं। चैम वीजमैन जायोनी संगठन के अध्यक्ष भी थे और बाद में इजराइल के पहले राष्ट्रपति बने। 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के कम्युनिस्ट घोषणापत्र में दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ का आह्वान किया गया था।

इसलिए, आज के समय में, भारतीय मुसलमानों को इन अंतरराष्ट्रीय आवेगों से ऊपर उठने का रास्ता ढूँढ़ना होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलगाववाद और अन्य समुदायों से 'अलग' या भिन्न होने की भावना इस समुदाय की चेतना और आचरण की एक विशिष्ट विशेषता रही है। भारत में, अलगाव और विशिष्टता की यह भावना देश के हिंदुओं के प्रति तब से मौजूद है जब से मुसलमान पहली बार आक्रमणकारी के रूप में देश के कुछ हिस्सों में बसने के इरादे लेकर आए थे। इस पर उनका शासन और उसके बाद हिंदू पुनरुत्थान, जिसके परिणामस्वरूप इस्लामी शासन का पतन हुआ और 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के जाने के बाद देश का विभाजन हुआ।

हिंदुओं को पारिवारिक ट्रस्ट रखने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को वक्फ नामक विशेषाधिकार प्राप्त है, जो पूरी तरह से अलग है और लगातार विवाद का विषय बनता जा रहा है। इतनी विविधताओं के साथ, यह आश्वस्त होना मुश्किल है कि भारत एक अखंड और सुसंगठित राष्ट्र है। देश की सभी आत्माओं का एक साथ मिलकर काम करना एक कठिन काम हो सकता है।

यह उम्मीद करना उचित है कि सभी धर्मों के सदस्य, जो व्यक्तिगत कानूनों को बरकरार रखने की अपेक्षा रखते हैं, इसी तरह की सोच रखते होंगे। भारत के संविधान में, अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों की समानता पर जोर देता है। लेकिन जब हम अनुच्छेद 25 तक पहुँचते हैं, तो विभिन्न समुदायों को अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की अनुमति मिल जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में समान नागरिक संहिता की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी, एक समुदाय अपने विदेश से आयातित व्यक्तिगत कानूनों का लाभ उठा रहा है। हिंदुओं को पारिवारिक ट्रस्ट रखने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को वक्फ नामक विशेषाधिकार प्राप्त है, जो पूरी तरह से अलग है और लगातार विवाद का विषय बनता जा रहा है। इतनी विविधताओं के साथ, यह आश्वस्त होना मुश्किल है कि भारत एक अखंड और सुसंगठित राष्ट्र है। देश की सभी आत्माओं का एक साथ मिलकर काम करना एक कठिन काम हो सकता है। सभी को यह याद दिलाना जरूरी है कि पड़ोस में दो राष्ट्र हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इससे बहुसंख्यक हिंदुओं के मन में यह डर का भाव पैदा होता है कि कोई न कोई अल्पसंख्यक अपने मन में देश-बाह्य या अंतरराष्ट्रीय निष्ठाएं पाल रहा होगा। बेहतर होता अगर ऐसी आशंकाओं की गुंजाइश ही न होती।

हमें यह कदापि भी नहीं भूलना चाहिए कि कईदशकों से कम्युनिस्ट पार्टियां अपने कई सशस्त्र कार्यकताओं के हाथों में हथियार लेकर अपना काम कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय विचारधाराएं और उनके द्वारा थोपी जाने वाली निष्ठाएं राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मूल धारणा को ही नकार देती हैं।

इसलिए, देश के मुस्लिम नागरिकों के लिए, उनके अपने हित में, सुधार का मार्ग हिंदुओं को पारिवारिक ट्रस्ट रखने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को वक्फ नामक विशेषाधिकार प्राप्त है, जो पूरी तरह से अलग है और लगातार विवाद का विषय बनता जा रहा है। इतनी विविधताओं के साथ, यह आश्वस्त होना मुश्किल है कि भारत एक अखंड और सुसंगठित राष्ट्र है। देश की सभी आत्माओं का एक साथ मिलकर काम करना एक कठिन काम हो सकता है।

सभी को यह याद दिलाना जरूरी है कि पड़ोस में दो ऐसे राष्ट्र हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इससे हिंदुओं के मन में यह डर पैदा होता है कि कहीं कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपने मन में देश-बाह्य या अंतरराष्ट्रीय निष्ठाएँ तो नहीं पाल रहा। बेहतर होता अगर ऐसी आशंकाओं की गुंजाइश ही न होती। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दशकों से कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने कई सशस्त्र कार्यकताओं के हाथों में हथियार लेकर काम करती रही हैं। अंतरराष्ट्रीय विचारधाराएँ और उनके द्वारा थोपी जाने वाली निष्ठाएँ राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मूल अवधारणा को ही नकारती हैं। इसलिए, देश के मुस्लिम नागरिकों के लिए, उनके अपने हित में, सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

दिखावे की हरित जीवन शैली

विश्वरूपा भट्टाचार्या
लेखिका, राज्यसभा सचिवालय की अपर सचिव हैं।

विडंबना यह है कि दशकों से उग रहे पेड़ों को बिना सोचे-समझे काटने या बुरी तरह से छंटाई करने के बाद, वही लोग फिर पलटकर गमलों में लगे पौधों पर हजारों रुपये खर्च करते हैं।

दिल्ली में पारंपरिक स्कूल की छुट्टियां, जो कभी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों तक ही सीमित रहती थीं, हाल के वर्षों में बदल गई हैं। आज, शहर के स्कूल भी खतरनाक रूप से उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक (अदक) के स्तर के कारण हर साल छुट्टियों के लिए बंद हो रहे हैं। इस तरह की बंदी के दौरान, निवासी बढ़ते प्रदूषण और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताएं व्यक्त करते हैं। हालांकि उनकी चिंताएं पूरी तरह से जायज और समझने योग्य हैं, मुझे यह थोड़ा पाखंडपूर्ण लगता है कि वे भी इस समस्या को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

गेट वाले समुदायों, आवासीय इलाकों और निजी संपत्तियों में, पेड़ों की छंटाई लापरवाही से की जाती है। और इसके कारण इतने बेतुके होते हैं कि यह बेहद निराशाजनक लगता है। चाहे वह गिरते पत्तों/टहनियों से घृणा हो, अवरुद्ध धूप या दृश्य के बाधित होने की चिंता हो या केवल साफ-सुथरे रूप की चाहत हो, कई निवासी उचित छंटाई के विज्ञान को समझे बिना ही भारी छंटाई का आदेश दे देते हैं। ऐसा करते हुए, वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रकृति की अदम्य सुंदरता का अपना आकर्षण और पारिस्थितिक महत्व है।

इस स्थिति को और भी चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि पेड़ों की कटाई और छंटाई को नियंत्रित करने वाला सरकारी विभाग प्रभावी ढंग से लागू करने में संघर्ष करता दिख रहा है। दिशानिदेर्शों का सख्ती से पालन करने और पेड़ों के रखरखाव पर कड़ी निगरानी रखने के बजाय, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां वे रखरखाव के बहाने अत्यधिक कटाई करते हैं।

इसके अलावा, छंटाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों के पास अक्सर विशेष प्रशिक्षण का अभाव होता है। पेड़ों की उचित देखभाल के पर्याप्त ज्ञान के बिना, वे निवासियों के निर्देशों का पालन करते हैं, जो संभवतः छंटाई के ज़िम्मेदार तरीकों से भी अनभिज्ञ होते हैं। नतीजतन, पेड़ों के स्वास्थ्य का आकलन करने और वैज्ञानिक छंटाई विधियों को लागू करने के बजाय, कभी-कभी बड़ी शाखाओं को अंधाधुंध तरीके से काट दिया जाता है, जिससे कभी-कभी केवल एक नंगे ठूंठ के अलावा कुछ नहीं बचता।

इस सब में विडंबना यह है कि दशकों से उग रहे पेड़ों को बिना सोचे-समझे काटने या बुरी तरह से छंटाई करने के बाद, वही लोग फिर पलटकर गमलों में लगे पौधों पर हजारों रुपये खर्च करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें वही लाभ मिलेंगे, जैसे वायु शोधन और सौंदर्य मूल्य, जो परिपक्व पेड़ स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर प्रदान करते हैं। यह विरोधाभास पूर्ण विकसित पेड़ों के पारिस्थितिक महत्व के बारे में एक गहरी गलतफहमी को उजागर करता है, यह मानते हुए कि एक बड़ा पेड़ कार्बन अवशोषण, तापमान नियंत्रण और आवास समर्थन में इनडोर पौधों से भरे पूरे कमरे की तुलना में अधिक योगदान दे सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, एक परिपक्व पेड़ एक वर्ष में वायुमंडल से 48 पाउंड से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा और बदले में ऑक्सीजन छोड़ेगा। इसके विपरीत गमले में लगा पौधा केवल 1 से 3 पाउंड (0.45 से 1.36 किलोग्राम) कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है।

विडंबना यहीं खत्म नहीं होती। यह जानते हुए भी कि बड़े पेड़ आसपास के तापमान को कम कर सकते हैं (लैंसेट के अनुसार अधिक पेड़ लगाने से औसत तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा), वे लापरवाही से पेड़ों की छंटाई करते हैं और फिर गर्मी से निपटने के लिए कृत्रिम साधनों एयर कंडीशनर (एसी) का सहारा लेते हैं, इनका रखरखाव आसान है, ये देखने में आकर्षक लगते हैं और आधुनिक घरों के न्यूनतम डिजाइनों में भी आसानी से फिट हो जाते हैं।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक इनडोर प्लांट बाजार तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया ने इस चलन को और बढ़ावा दिया है। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म हरे-भरे अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरों से भरे पड़े हैं जो लोगों को अपने घर के अंदर जंगल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। गमलों में लगे पौधे बेशकीमती फायदे देते हैं—बेहतर वायु गुणवत्ता, तनाव से राहत और सौंदर्यबोध—लेकिन ये बाहर हरियाली के व्यापक पर्यावरणीय फायदों की जगह कभी नहीं ले सकते। यह एक परेशान करने वाला विरोधाभास है कि हममें से कई लोग, रहने की जगह चुनते समय, हरे-भरे स्थानों और हरे-भरे परिवेश को प्राथमिकता देते हैं। हम हरे-भरे और पेड़ों से भरे इलाकों में घरों के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, इन जगहों से मिलने वाली शांति, वायु गुणवत्ता और प्राकृतिक सुंदरता को महत्व देते हैं—जो तनाव कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार, शोर कम करने और सौंदर्यपरक आकर्षण प्रदान करने में मदद करते हैं। हालांकि, एक बार जब हम इन इलाकों में बस जाते हैं, तो जिस हरियाली की हम तलाश करते हैं, अक्सर वही सबसे पहले हम नष्ट कर देते हैं।

यह व्यवहार हमारी पर्यावरणीय जागरूकता और हमारे दैनिक कार्यों के बीच के अंतर को दशार्ता है। हम स्थायित्व का समर्थन करते हैं, स्वच्छ हवा की वकालत करते हैं, और बढ़ते तापमान पर शोक व्यक्त करते हैं, फिर भी हमारे विकल्प - चाहे वह सुविधा के लिए पेड़ों को काटना हो, एयर कंडीशनिंग पर अत्यधिक निर्भरता हो, या पारिस्थितिक संतुलन के बजाय सौंदर्य को प्राथमिकता देना हो - इन चिंताओं का खंडन करते हैं।

आप की बात

ट्रंप किसी के दोस्त नहीं

पिछले कार्यकाल में डोनॉल्ड ट्रम्प जो भारत के पक्के दोस्त रहे हैं. इस कार्यकाल में भी उन्होंने दोस्ती निभाई किन्तु रूस से तेल लेने के बाद जो अमेरिका रूस का दुश्मन रहा वो भारत से भी दुश्मनी कर रहा है बारम्बार टैरिफ बढ़ाकर व और भी नए-नए प्रतिबंध लगाने की धमकी देकर। उधर हमारे दुश्मन पाक को मदद के बहाने उनके सेना प्रमुख असीम मुनीर को दूसरी बार किसी बहाने अमेरिका में शिरकत के लिए बुलाया है हमें चिढ़ाने के लिए. एक बात और है हमने पाक का पानी बंद किया तो वो अब उसका हमदर्द बन रहा है। इधर दुश्मन-दुश्मन एक हो रहे हैं हमारे विरूद्व और उधर रूस-चीन की तरफ झांकने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। एक बात और महत्वपूर्ण है जो भारत का दोस्त नहीं हुआ वो पाक का क्या खाक दोस्त बनकर मदद कर पायेगा. जो हमको धोखा दे सकता है वो पाक से भी किसी मतलब के लिए दोस्ती कर रहा है और मतलब निकलने के बाद उसे भी ठेंगा बता देगा. रूस और हमारी पुरानी दोस्ती है और दोनों निभा रहे हैं. चीन भी रूस से दोस्ती बना रहा है तब हमसे भी वो हाथ मिला रहा है. तीनों की दोस्ती से ही शायद अमेरिका बौखला रहा है और "टैरिफ" का हथियार सब पर अपना रहा है। क्योंकि इनसे बहुत अधिक दुश्मनी तो वो ले नहीं सकता।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

भगदड़ से मौतें

कुबेरेश्वर धाम सीहोर में कावड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण 7 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। भारी भीड़ के कारण भगदड़ से होने वाली मौतों के लिए अब जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है।जो भीड़ को एकत्र करें, वो सीधे-सीधे जिम्मेदार माना जाना चाहिए। धार्मिक स्थल(या अन्य समारोह में) व कथा प्रवचनों में जो भी कर्ताधर्ता/ आयोजक हो, अब इन्हें सीधे-सीधे इन हादसों के लिए जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। आखिर शासन प्रशासन कब तक ऐसे आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था करता रहेगा। निगरानी जरूरी पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए। आयोजकों को अपने निजी कार्यकताओं व सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड की फौज रखना चाहिए, ताकि बदइंतजामी न हो पाए। एक निश्चित मात्रा से ज्यादा लोगों की भीड़ भी एकत्र नहीं होने देने के लिए कानूनन गाइडलाइन होना चाहिए। आजकल तो आयोजकों व बड़े-बड़े कथाकारों में एक प्रकार की होड/ प्रतियोगिता चल रही है, कौन ज्यादा जनता में प्रसिद्ध है। इसी प्रसिद्ध के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा भीड़ एकत्र की जाती है। सरकार को अब नया कानून बनाना चाहिए कि आयोजन स्थल पर किसी भी हादसे के लिए कर्ताधर्ता, आयोजकों की तमाम जवाबदारी रहेगी। जब तक कंधे पर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तब तक कोई परवाह करने वाला नहीं है। लोग ऐसे ही दब व कुचल कर मरते रहेंगे।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, खाचरोद, उज्जैन

नर्मदा संरक्षण का संकल्प

धार्मिक कार्य एवं परिक्रमावासी स्नान ,पूजन का कार्य करते है।नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु कई स्थानों पर सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही है।ताकि पानी स्नान ,आचमन योग्य हो सके।ऐसी व्यवस्था का संकल्प लेना होगा।नर्मदा नदी के तट स्थित रहने वाले कई रहवासी अपने घर के निकले गंदे पानी का निकास घर के पीछे करते है और उस गंदे पानी को सोख्ता गड्ढे में समाहित करते है ताकि सीधे गन्दा पानी मां नर्मदा के स्वच्छ जल में न मिले।वर्तमान में ऐसी ही प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। ताकि सीधे तौर पर गंदा पानी पावन नदी में न मिल पाए। साथ ही नदी के तट में मिट्टी का कटाव रोकने हेतु नदी के तट पर फलदार वृक्ष ज्यादा मात्रा में लगाया जाना चाहिए जिससे परिक्रमा वासी,नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं जल उपयोगकताओं को गर्मी में सुखद छांव एवं फल की प्राप्ति हो सकें।नदियो को प्रदूषण से मुक्त करने का दायित्व निभाने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत कर उन्हें शासन से सहायता मुहैया होना चाहिए स्वच्छता का संदेश और जागरूकता लाना हर इंसान का कर्तव्य है प्रदूषण मुक्त नदी बनाने का संकल्प लेना होगा ताकि नर्मदा में मिलने वाली सहायक नदियों,नालों को प्रदूषित न करें व नर्मदा का संरक्षण कर इसे प्रदूषण मुक्त करे।

– **संजय वर्मा**, मनावर, मप्र

राहुल के आरोप

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के निर्वाचन आयोग पर हर बार की तरह इस बार भी गंभीर आरोप लगाते हुए संबंधित साक्ष्य देश की जनता के सामने रखे है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर चुनाव में धांधली एवं मतदाताओं की घटते बढ़ती संख्या के आधार पर वोट की चोरी का गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। केवल आरोप लगाने का उद्देश्य बना लेना अच्छी बात नहीं है । यदि राहुल गांधी के माने तो कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत का वोट की गड़बड़ी है। उनके अनुसार अप्रत्याशित रूप से महादेवा विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट मिला है जहां बोगस मतदान की बात कही है. इस घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने आक्रामक मुद्दा दिखाते हुए राहुल गांधी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने जनता की अदालत में अपनी बात रख दी है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है जबकि भाजपा ने चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए नेता प्रतिपक्ष से हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। आने वाले दिनों में यह देश का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और बिहार की राजनीति में इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी।

– **वीरेन्द्र कुमार जाटव**, दिल्ली

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 149

सावधानी जरूरी

भारतीय दवा कंपनियां भारी लाभ कमाने की तैयारी में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वजन कम करने में सहायक और मधुमेह के इलाज में काम आने वाले औषधि घटक सेमाग्लूटाइड का पेटेंट 2026 में तकरीबन 100 देशों में समाप्त हो जाएगा। इन देशों में भारत, कनाडा और ब्राजील भी शामिल हैं। सेमाग्लूटाइड से बनने वाली दवाओं को डेनमार्क की दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिस्क द्वारा ओजेंपिक और वीगोवी नामक ब्रांड नाम के अंतर्गत बेचा जाता है। ये दवाएं कंपनी के लिए अत्यधिक कामयाब रही हैं और अकेले 2024 में कंपनी ने इससे 25 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया। आश्चर्य नहीं कि भारतीय दवा कंपनियों को भी इसमें बहुत बड़ा अवसर नजर आया है और वे सेमाग्लूटाइड का काफी सस्ता जेनरिक संस्करण बाजार में उतारने की तैयारी में हैं। भारत के घरेलू दवा उद्योग की सभी बड़ी कंपनियां मसलन डॉ. रेड्डीज, बायोकॉन, सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन और अरविंदो फार्मा आदि के बारे में खबर है कि वे इस दवा के इंजेक्शन और गोली स्वरूप को खुद तैयार करने या अनुबंध के आधार पर तैयार करवाने की योजना तैयार कर रही हैं। हालांकि बाजार अवसर और सस्ती जेनरिक दवाओं से उपभोक्ताओं के लिए लाभ दोनों का हमें जोखिम के हिसाब से आकलन करना होगा।

इस दशक के अंत तक वजन कम करने की दवाओं का वैश्विक बाजार करीब 100 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। अकेले भारत में पिछले पांच साल में यह बाजार पांच गुना बढ़ गया है और अब इसका मूल्यांकन करीब 7.3 करोड़ डॉलर है। मधुमेह और मोटापे के बढ़ते मरीजों के कारण भी इस वृद्धि को गति मिल रही है। इंटरनैशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार भारत में मधुमेह की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और दुनिया में मधुमेह से पीड़ित हर चार व्यक्तियों में से एक भारतीय है। मोटापा भी महामारी के स्तर पर पहुंच रहा है क्योंकि समृद्धि बढ़ रही है और जीवनशैली में आराम तथा जंक फूड की पैठ हो गई है। ऐसे में 80 से 90 फीसदी तक सस्ती पड़ने वाली जेनरिक दवाओं के उत्पादन में भारी तेजी आने की संभावना है।

हालांकि, समृद्धि का यह सफर बाधाओं से भरा हुआ हो सकता है। नोवो नॉर्डिस्क सेमाग्लूटाइड के पेटेंट की अवधि बढ़ाने के लिए पारंपरिक 'एवरग्रीनिंग' की रणनीति अपना सकती है जिससे जेनरिक दवाओं के प्रवेश को रोका जा सकता है। फिलहाल उसने डॉ रेड्डीज और बेंगलूरु की ऑनसोर्स स्पेशियलिटी फार्मा पर सेमाग्लूटाइड की मार्केटिंग करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया है और इसके लिए पेटेंट के उल्लंघन को वजह बताया है। एली लिली नामक कंपनी अपनी मधुमेह और वजन प्रबंधन दवाओं को क्रमशः मोंजारो और जेपबाउंड के नाम से बेचती है। खबरें हैं कि यह कंपनी टिर्जेप्टाइड नामक औषधि घटक के फॉलोऑन पेटेंट के लिए प्रयास कर रही है जो 2036 में समाप्त हो रहा है। ये पेटेंट मुख्य रूप से आपूर्ति साधन, उपचार विधियों और फॉर्मूलेशंस पर केंद्रित हो सकते हैं।

इसके साथ ही बिना पर्याप्त सुरक्षा जांच के अनुबंधित विनिर्माण का तेजी से विस्तार घरेलू दवा निर्माताओं के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ समय पहले फ्रेंचाइजी इकाइयों में बनी बच्चों की खांसी की दवा से जुड़ा हादसा हमें चेताने वाली घटना है। इसके अलावा दोनों दवाओं को सख्त चिकित्सकीय निगरानी में लेना होता है और इनके साथ भोजन और व्यायाम को लेकर भी काफी सावधानी बरतनी होती है। बिना इसके मरीजों को गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और उन्हें पेट की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे देश में जहां चिकित्सक के पर्चे पर मिलने वाली दवाएं बिना पर्चे के आसानी से मिल जाती हों और जहां लोगों में खुद ही दवा खरीदकर खाने की प्रवृत्ति हो, वहां वजन कम करने वाली दवाओं को बिना चिकित्सक की अनुशंसा के खाने के मामले भी कम नहीं। यह बात प्रभावशाली वर्ग पर खासतौर पर लागू होती है जो बिना खानपान पर ध्यान दिए ऐसी दवाओं को खाता है और गंभीर बीमारियों का शिकार होता है। ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि औषधि नियंत्रक पेटेंट अवधि समाप्त होने वाली इन दवाओं के निर्माण और वितरण पर निगरानी रखे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनसे कोई दूसरी समस्या नहीं पैदा होगी।

विनय सिन्हा

ई-कॉमर्स और खुदरा के बीच सह-अस्तित्व

बड़े ई-कॉमर्स और छोटे कारोबारियों को साथ फलने-फूलने में मदद के लिए समझदारी भरी नीतियां बनानी होंगी। बता रहे हैं लवीश भंडारी

खुदरा कारोबार की प्रकृति बदल रही है और भारत निस्संदेह वैश्विक स्तर पर इस बदलाव का अगुआ है। यह स्पष्ट है कि भारतीय उपभोक्ताओं ने ई-कॉमर्स को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया है। उदाहरण के लिए मेरे घर पूरी तरह ऑनलाइन ऑर्डर किए जा रहे हैं। यहां तक कि मेरी घरेलू सहायिका भी यही कर रही है। यही नहीं कई रिपोर्ट के अनुसार, मझोले और छोटे शहर, कस्बे और ग्रामीण भारत भी ऑनलाइन खरीदारी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, आधार और डिजिटल अधोसंरचना के अन्य घटकों ने इस वृद्धि में मदद की है। अच्छी गुणवत्ता वाली डिजिटल अधोसंरचना तक आसान पहुंच ने भी स्टार्टअप और छोटे और मझोले उपक्रमों को इस योग्य बनाया है कि वे तकनीकी क्षमता विकसित करें।

मेरे लिए अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि उत्पादों की बड़ी तादाद अब आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। रागी बिस्किट, पारंपरिक रूप से बना घी, ताड़ का गुड़, सेमल के तकिए, कूलर के लिए खस की मैट और अनेक अन्य उत्पाद जिन्हें पूरे भारत में आसानी से नहीं पाया जा सकता था, वे सभी अब उपलब्ध हैं। हमारा खपत व्यवहार भी तेजी से बदल रहा है और इसमें कुछ साल पहले की तुलना में काफी अंतर आया है। जैसे-जैसे खपत में अंतर बढ़ रहा है वैसे-वैसे ढेर सारे छोटे उपक्रमों, समूहों या गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए भी अवसर बढ़ रहा है जो इन वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं।

कुछ सदी पहले तक कहा जाता था कि ग्रामीण भारत में खुदरा कारोबार बहुत कम है। वहां लेनदेन और किसी चीज के बदले दूसरी चीज के आदान प्रदान की व्यवस्था थी। यहां तक कि शहरी भारत में भी ग्राहक आमतौर पर परिचित दुकानों पर ही जाते। यह रिश्ता काफी हद तक अंतरंग होता। उनके बीच बार-बार लेनदेन होता और उधारी भी। इसके चलते खुदरा कारोबारी ऐतिहासिक रूप से भारतीय ग्राहकों को उधार देने वाले रहे। असंगठित क्षेत्र भी ऐसी शानदार सेवाएं मुहैया कराता था जो आधुनिक खुदरा कारोबार नहीं मुहैया करा पाते। ये सभी व्यवहार इसलिए चलन में आए क्योंकि पारंपरिक खुदरा कारोबारी नवाचारी थे। वे भारतीय ग्राहकों के सबसे करीब थे और उनकी जरूरतों को अच्छी तरह समझते थे।

भारतीय खुदरा कारोबारी पारंपरिक रूप से कम मार्जिन में सेवाएं देते हैं, वे आसानी से उधार देते हैं और कुछ खास जरूरतों के लिए लोग उन पर निर्भर हैं। यह परिचालन बहुत मजबूत है। उदाहरण के लिए जब नोटबंदी के दौरान नकदी गायब हो गई थी तब यही मजबूत काम में आई थी। सब्जियां बेचने वालों/खुदरा कारोबारियों और ग्राहकों के बीच के भरोसे ने खानेपीने की आपूर्ति सुनिश्चित की जबकि थोक विक्रेताओं और सब्जी कारोबारियों के रिश्ते ने यह सुनिश्चित किया कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित न हो। कोई भुगतान नहीं किया जाता था। यह सब केवल मौखिक लेनदेन था क्योंकि वह उस वक्त की जरूरत थी। कोविड के दौर में भी जब वर्दी वाले पुलिसकर्मी बाकी वेंडर को रोक देते तो खुदरा कारोबारियों के इसी समूह ने सुनिश्चित किया कि विभिन्न इलाकों में खानेपीने की चीजें पहुंचती रहें। ध्यान रहे कि लॉकडाउन के दौरान खुदरा कारोबार की इजाजत थी लेकिन झुग्गियों में और शहरों के अत्यंत अंदरूनी हिस्सों में असंगठित क्षेत्र के वेंडर्स ने ही ये चीजें पहुंचाईं। यहां बात इंसानी रुचि की नहीं है बल्कि आर्थिक अनिवार्यताओं ने कम मार्जिन और कठिनाई के बावजूद कामकाज जारी रखा।

ऐसे में हमारे सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण दुविधा के हालात हैं। बड़े गिग इकनॉमी वाले कारोबारी कम कीमतों पर वस्तुओं की एक अद्भुत श्रृंखला प्रदान करते हैं जबकि छोटे खुदरा विक्रेता हमेशा नहीं लेकिन कभी-कभी अनौपचारिक भी होते हैं। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। जिस प्रकार पारंपरिक खुदरा व्यापार में कुछ लोग गतिशील होते हैं और कुछ लोग एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार ई-कॉमर्स भी ऐसे विकल्प प्रदान करता है। जिस तरह पारंपरिक खुदरा कारोबार हमेशा नवाचार करता है (घर-घर आपूर्ति) उसी तरह ई-कॉमर्स भी बदल रहा है। इसमें त्वरित व्यापार और 10 मिनट में डिलिवरी जैसे नवाचार नजर आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि फिर इनमें अंतर क्या है?

दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पारंपरिक खुदरा कारोबार जहां बाजार के तय ढांचे में रहकर काम करता है, जहां कई वेंडर होते हैं और कई लोग होते हैं जो जिनसे वस्तुएं ली जा सकती हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में प्रवेश की राह में सीमित बाधाएं हैं। इससे उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा और सीमित मार्जिन तय होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह का खुदरा कारोबार पर्याप्त नवाचारी नहीं होता है क्योंकि इसमें कभी पर्याप्त अधिशेष नहीं तैयार होता है जो नवाचार को गति प्रदान करे। वहीं नया ई-कॉमर्स क्षेत्र चुनिंदा बड़े कारोबारियों का क्षेत्र है जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और साथ ही पारंपरिक खुदरा उद्योग से भी। उनके पास कम लागत में चीजें खरीदने की क्षमता है। इसके बावजूद अधिकांश ई-कॉमर्स कंपनियां लाभ में नहीं हैं। वे घाटा उठाकर भी पारंपरिक खुदरा कारोबार को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। कहा जाता है कि बाद में वे कीमतें बढ़ा देंगी। अगर यह सही है तो बेहतर यही होगा कि उन पर कर ज्यादा लिया जाए या फिर नियामकीय या नीतिगत कदम उठाए जाएं। वहीं दूसरी ओर अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए कि खुदरा के इस नए स्वरूप में रोजगार, नवाचार और मूल्यों आदि को कैसे सुनिश्चित किया जाए?

अर्थशास्त्र से जुड़ी सामग्री कुछ अंतदृष्टि प्रदान करती है। पहले का संबंध प्रतिस्पर्धा के स्वरूप से है। कंपनियों के लिए उस समय उच्च लाभ हासिल करना मुश्किल होता है जब वे कीमतों को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रही हों। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उच्च लाभ सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं में वि शिष्टता हासिल करना बहुत जरूरी है। दूसरा, लंबी अवधि में तभी लाभ होगा जब उस क्षेत्र में प्रवेश मुश्किल हो। चूंकि घरेलू और वैश्विक दोनों ही प्रकार की अनेक कंपनियां हैं, इसलिए इस बात का पहले ही ध्यान रखा जा चुका है - जब तक कि मौजूदा कंपनियां आपस में मिलकर विभिन्न ग्राहक या उत्पाद खंडों को आपस में बांट न लें। तीसरा, यदि वास्तव में उद्देश्य पारंपरिक खुदरा व्यापार को समाप्त करने का है तो भविष्य में छोटे खुदरा विक्रेताओं के प्रवेश को रोकना होगा। छोटे उद्यमियों की गतिशीलता को देखते हुए यह कैसे तय किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया देखें तो उपरोक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर स्वतः स्पष्ट हैं। लेकिन इस समीकरण में एक और प्रश्न जोड़ना आवश्यक है। नीतियां कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं कि पारंपरिक खुदरा व्यापार नवाचार करे और समृद्ध हो? ध्यान दें कि पारंपरिक खुदरा व्यापार, चाहे वह किराना हो या अनौपचारिक क्षेत्र में, अधिशेष पैदा करता है, ग्राहकों की सेवा करता है, नवाचार करता है और निश्चित रूप से, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है। इसलिए, एक अच्छी खुदरा नीति उन्हें अधिक गतिशील बनाने में सक्षम बनाएगी। ऐसी नीतियों में संभवतः कई जाने-माने समाधान शामिल होंगे, जिनमें पर्याप्त स्थान, आसान ऋण, भ्रष्ट नगर निरीक्षकों और स्थानीय पुलिसकर्मियों से मुक्ति, और कम नियमन शामिल हैं।

लेकिन यकीनन सबसे महत्त्वपूर्ण नीतिगत योगदान पारंपरिक खुदरा और ई-कॉमर्स को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए सशक्त बनाना होगा। उदाहरण के लिए, पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को ई-कॉमर्स फर्मों के लिए उपलब्ध कम लागत वाले उत्पादों तक पहुंच कैसे मिल सकती है? इसी तरह, ई-कॉमर्स कंपनियों को स्थानीय खुदरा विक्रेताओं के ग्राहक ज्ञान और नेटवर्क तक पहुंच कैसे मिल सकती है? अगर यह संभव होता, तो पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं के दीर्घकालिक भरोसेमंद संबंधों और ग्राहक ज्ञान का लाभ ई-कॉमर्स की पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और प्रक्रिया-संचालित तरीकों का पूरक बन सकता था। हम पहले से ही ऐसे मॉडलों का परीक्षण होते देख रहे हैं। सवाल यह है कि नीतियां इनके क्रियान्वयन में कैसे मदद कर सकती हैं?

(लेखक सीएसईपी रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख हैं। लेख में उनके व्यक्तिगत विचार हैं।)

कामकाजी महिलाओं की तादाद क्यों है कम?

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

मई महीने में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मजबूत नीतियों और कानून बनाने पर जोर दिया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी (एलएफपीआर) दर लगभग 33 फीसदी है (विश्व बैंक, 2024), जो विश्व स्तर पर काफी कम है, जबकि निम्न-मध्य-आय वाले देशों में यह दर औसतन 41 फीसदी है।

इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत में कामकाजी महिलाएं इतनी कम क्यों हैं? यह सिर्फ आमदनी में तेज वृद्धि के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि महिलाओं के सशक्तीकरण का सीधा ताल्लुक, परिवारों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बेहतर नतीजों से है। ऐसे में महिलाओं की कम एलएफपीआर का असर देश के समग्र विकास के परिणामों पर भी पड़ता है।

महिला एलएफपीआर के तीन मुख्य कारक हैं: सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएं (महिलाओं के काम के प्रति समाज का रवैया), आपूर्ति-पक्ष कारक (महिलाओं की काम करने की इच्छा), और मांग-पक्ष कारक (नौकरियों की उपलब्धता)। कई शोध रिपोर्ट बताते हैं कि भारत में महिला एलएफपीआर कम होने के पीछे मुख्य रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएं और आपूर्ति पक्ष की बाधाएं जिम्मेदार हैं। यह निष्कर्ष सही भी लगता है क्योंकि भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू कामों में आठ गुना अधिक समय बिताती हैं जबकि वैश्विक औसत तीन गुना (यूएन वुमन 2019) है। साथ ही, पुरुषों और महिलाओं के लिए वेतन समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 120वें स्थान पर है। ऐसी कई वजहों की लंबी फेहरिस्त है।

हमारा निरंतर कार्य दर्शाता है कि ये मानदंड और आपूर्ति-पक्ष कारक महिला एलएफपीआर को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये हमारे समकक्ष देशों, जिनकी महिला एलएफपीआर कहीं अधिक है, के साथ कुल अंतर का लगभग आधा हिस्सा ही समझा पाते हैं। इस प्रकार, भारत में श्रम की मांग की कमी बाकी आधे हिस्से की व्याख्या करती है। महिला एलएफपीआर किसी देश में महिला प्रधान रोजगार, अर्थव्यवस्था में श्रम का उपयोग और आर्थिक विकास के स्तर का परिणाम है। चूंकि दोनों तरह के देशों में आर्थिक विकास का स्तर लगभग समान है ऐसे में हम महिलाओं के एलएफपीआर पर पहले दो कारकों के प्रभाव को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

शिशिर गुप्ता और आल्या सभरवाल

महिला प्रधान रोजगार वाले देशों के बीच का अंतर, मुख्य रूप से सामाजिक नियमों और महिलाओं की काम करने की इच्छा के कारण होता है जबकि रोजगार की तीव्रता में अंतर, उत्पादन प्रक्रियाओं में श्रम बनाम पूंजी का उपयोग करने के सापेक्ष लागत और लाभ को दर्शाता है। इसलिए, अगर दो देशों में सामाजिक नियम और महिलाओं की काम करने की इच्छा समान भी हो तब पूंजी पर आधारित वृद्धि वाले देश में महिला एलएफपीआर कम होगी। सवाल यह है कि ये दोनों कारक कितने महत्त्वपूर्ण हैं?

बांग्लादेश और फिलिपींस से तुलना करने पर यह बातें और साफ हो जाती हैं। अगर भारत में बांग्लादेश या फिलिपींस जैसी महिला रोजगार तीव्रता होती तो हमारी महिला एलएफपीआर 33 फीसदी से बढ़कर क्रमशः 37फीसदी और 43फीसदी हो जाती। हालांकि इसके बावजूद यह इन देशों (बांग्लादेश में 44 और फिलीपींस में 50 फीसदी) से काफी पीछे रहती। यह बताता है कि महिला एलएफपीआर के कुल स्तर को समझाने में मांग-पक्ष के कारकों का बड़ा महत्त्व है।

बांग्लादेश में महिला एलएफपीआर के विकास को देखने से मांग-पक्ष के कारकों का महत्त्व और भी स्पष्ट हो जाता है। 1990 में, भारत और बांग्लादेश दोनों में महिलाओं की भागीदारी दर लगभग एक जैसी, क्रमशः 30 और 25 फीसदी थी। लेकिन आज, बांग्लादेश हमसे कहीं आगे निकल चुका है। इसका श्रेय उसके निर्यात-आधारित रेडीमेड परिधान उद्योग को जाता है। वर्ष 1983 में, रेडीमेड परिधान निर्यात बांग्लादेश के कुल निर्यात का केवल 4 फीसदी था, जो 2021 में बढ़कर 81फीसदी हो गया और 42 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

रेडीमेड परिधान क्षेत्र में 60 फीसदी से अधिक कर्मचारी महिलाएं (निर्यात संवर्धन ब्यूरो बांग्लादेश 2021) हैं। अगर रेडीमेड परिधान उद्योग में यह जबरदस्त उछाल नहीं देखी गई होती तो बांग्लादेश की महिला भागीदारी लगभग 38फीसदी होती न कि 44 फीसदी। इससे हमें साफ सबक मिलता है कि अगर बाकी चीजें समान रहें, तब रोजगार आधारित विकास का रास्ता महिला भागीदारी के लिए भी बेहतर है।

आखिरी सवाल यह है कि आखिर, भारत में श्रम की मांग कम क्यों है? इसके कई और अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षा और कौशल की खराब गुणवत्ता, और मुश्किल श्रम कानून। शिक्षा की गुणवत्ता को वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में पढ़ने और गणित के सवाल हल करने से जुड़ी सीख की जांच के नतीजों से आंका जा सकता है। तीसरी कक्षा के केवल 23 फीसदी छात्र पढ़ने में और 33 फीसदी गणित में पास हुए। पांचवीं कक्षा में, 44 फीसदी ने पढ़ने की और 30फीसदी ने गणित की परीक्षा पास की।

भारत में लगभग 15 फीसदी कंपनियां, श्रम कानूनों को एक बड़ी या बेहद गंभीर बाधा बताती हैं, जबकि बांग्लादेश में यह आंकड़ा महज 3.4 फीसदी और फिलीपींस में 6.4 फीसदी है। इन मांग-पक्ष की बाधाओं को दूर करना बहुत जरूरी होगा ताकि अधिक महिलाओं को कार्यबल में आने और बने रहने का मौका मिल सके, जिससे महिला एलएफपीआर बढ़ेगी। यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि शिक्षा की गुणवत्ता और श्रम कानूनों की बाधाओं को दूर कर, काम की मांग बढ़ाना काफी हद तक सरकार के हाथ में है। एक बार जब यह लागू हो जाएगा, तब यह उम्मीद है कि इससे एक सकारात्मक चक्र शुरू होगा, जो आपूर्ति और सामाजिक नियमों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे एलएफपीआर और बढ़ जाएगी।

(लेखकद्वय अर्थशास्त्री हैं और ये निजी विचार हैं।)

आपका पक्ष

भारत में डिजिटल लेनदेन की चुनौतियां

रूस ने डिजिटल लेनदेन के लिए अपने यहां विदेशी कंपनियों के एटीएम कार्ड या दूसरे साधनों पर निर्भरता रखी थी, उसका बुरा नतीजा वहां के नागरिकों को वित्तीय विदेशी कंपनियों द्वारा युद्ध के समय हाथ पीछे खींचने के रूप में चुकाना पड़ा था। लेकिन हमारे देश में मोदी सरकार ने रुपे कार्ड और भीम यूपीआई की शुरुआत कर देश को डिजिटल लेनदेन के लिए स्वदेशी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छा प्रयास किया है। हमारा देश गांवों का देश है और यहां अशिक्षित लोगों की संख्या भी कम नहीं है, इसलिए हमारे यहां डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलना आसान नहीं है। हमारा देश डिजिटल लेनदेन की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी आम लोगों को पेश आ रही हैं। इसमें मुख्यतः साइबर अपराध और ट्रांजेक्शन फेल होना आदि हैं। हालांकि सरकार, रिजर्व बैंक, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं इस पर नकेल कसने और आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए भरपूर प्रयास भी कर रहें हैं। मीडिया भी साइबर अपराध के प्रति लोगों को सतर्क करने के लिए विशेष लेख या कवरेज प्रस्तुत करता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो डिजिटल लेनदेन तो करने लगे हैं, लेकिन उन्हें इस बारे गूढ़ ज्ञान नहीं है, जिस कारण ऐसे लोग साइबर चोरों के शिकार होकर या फिर धोखाधड़ी के शिकार होकर अपने खून-पसीने की कमाई गंवा बैठते हैं। लोगों को चाहिए कि वे किसी भी झांसें में आकर अपने खून-पसीने की कमाई बरबाद न कर लें, साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

आज भारत के लोग डिजिटल लेनदेन की ओर अग्रसर हो चुके हैं मगर इसमें कुछ परेशानियों का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है

भारत भी व्यापार करार पर अख्तियार करे कड़ा रुख

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शुल्क का मुद्दा हल हो जाने तक भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार किया है। ट्रंप ने गुरुवार को अपने कार्यालय में कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता। यहां यह जानना भी जरूरी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह भारत पर 25 फीसदी जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही कुल शुल्क 50 फीसदी हो गया, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से डॉनल्ड ट्रंप को अपना खास दोस्त बताते आए हैं। मगर ट्रंप को दोस्ती को मोल पता नहीं है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को भी अब अमेरिका के साथ किसी भी तरह के व्यापार समझौते पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए, अब जरूरी हो गया है कि भारत भी अमेरिका के साथ व्यापार करार पर अपना रुख कड़ा कर ले ताकि वह हमें हल्के में न ले।

राजदीप सिंह, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को नया रूप देने के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये की परियोजना की आधारशिला रखी। पुनौरा धाम को माता सीता का जन्मस्थान माना जाता है। शाह ने सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य मौजूद रहे।

Machine Translated by Google

AWS को ठीक करें

मतदाता पंजीकरण समस्याओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यवस्थित समाधान की आवश्यकता

टी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर "आपराधिक धोखाधड़ी" के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत सुनिश्चित करने के लिए बेंगलुरु मध्य लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से ज़्यादा फ़र्ज़ी वोट बनाए गए। कथित चुनावी गड़बड़ियों की पाँच श्रेणियों को रेखांकित करने वाली उनकी विस्तृत प्रस्तुति की सावधानीपूर्वक जाँच की ज़रूरत है, न कि पूरी तरह से खारिज करने की। कांग्रेस नेता के दस्तावेज़ों से परेशान करने वाले पैटर्न सामने आए हैं: एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई बार पंजीकृत मतदाता, अलग-अलग राज्यों में एक जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर, और एक ही पते पर सूचीबद्ध मतदाताओं की अविश्वसनीय रूप से बड़ी संख्या। जबकि विभिन्न राज्यों में समान ईपीआईसी संख्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है - ईसीआई ने इस वर्ष की शुरुआत में इन विसंगतियों को संबोधित किया - उनका दावा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एक ही बूथ पर "एक ही व्यक्ति" द्वारा कई वोट दिखाने वाली बूथ पर्चियां मिलीं, यदि सत्यापित हो तो "एक व्यक्ति, एक वोट" सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन दर्शाता है। श्री गांधी ने दावा किया कि ये विसंगतियां महादेवपुरा तक सीमित नहीं थीं, बल्कि देश भर के सीमांत निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की मदद करने के लिए एक सोची-समझी कार्यप्रणाली का हिस्सा थीं। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पंजीकरण में भारी वृद्धि के बारे में इसी तरह के आरोप लगाए थे, यह दावा करते हुए कि इनसे भाजपा और उसके सहयोगियों की अप्रत्याशित जीत में योगदान मिला था, हालांकि महादेवपुरा में देखे गए गलत पंजीकरण के विस्तृत सबूत के बिना।

गांधी का विश्लेषण यह साबित करने में नाकाम रहा कि इन विसंगतियों ने सीधे तौर पर भाजपा की जीत में योगदान दिया। भाजपा ने 2023 में महादेवपुरा विधानसभा सीट लगभग 44,500 मतों के अंतर से जीती। 2024 में जीत का अंतर बढ़कर 1,14,000 से ज़्यादा हो गया, जबकि मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 52,600 थी और वास्तविक मतदाताओं की संख्या में केवल लगभग 20,000 की वृद्धि हुई। मतदाता सूची की त्रुटियों और चुनाव परिणामों के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य सहसंबंध से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। पंजीकरण त्रुटियों का दस्तावेजीकरण करने से लेकर भाजपा के साथ मिलीभगत करके चुनाव आयोग द्वारा जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के आरोप लगाने तक की छलांग अभी भी निराधार है।

ईसीआई ने 'शपथ के तहत' साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करके अनावश्यक रूप से रक्षात्मक रुख अपनाया है - एक आवश्यकता जो कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस स्थिति में लागू नहीं हो सकती है - और पंजीकरण के दौरान चिंताओं को उठाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा असफलता को चुनावी विसंगतियों को जिम्मेदार ठहराया। अधिक समस्याग्रस्त ईसीआई की कार्यप्रणाली है जिसमें संरचित, खोज योग्य पाठ प्रारूपों के बजाय भारी छवि पीडीएफ में मतदाता जानकारी जारी की जाती है, जो राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा सत्यापन प्रयासों में बाधा डालती है। मतदाता पंजीकरण के लिए ईसीआई का दृष्टिकोण स्व-घोषणाओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है और इसमें मजबूत सत्यापन तंत्र का अभाव है। महादेवपुरा विवाद सबसे विश्वसनीय विधि, डोर-टू-डोर सत्यापन के माध्यम से व्यापक मतदाता सूची सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। हालाँकि, जल्दबाजी में किए गए कार्यान्वयन और समस्याग्रस्त पहचान सत्यापन आवश्यकताओं के कारण वैध मतदाता सूची से नाम हटाने से जुड़ी नई समस्याएँ पैदा होने का खतरा है। आँकड़े पहले ही बिहार में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं के नाम हटाने की दर को अधिक दर्शाते हैं। यह देखते हुए कि अधिकांश प्रवासी पुरुष हैं, महिला मतदाताओं के नाम हटाने की दर में वृद्धि यह संकेत दे सकती है कि हाशिए पर पड़े मतदाता - विशेष रूप से वे जो निरक्षर हैं (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 2019-21 में बिहार में 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं की साक्षरता दर 55% थी) - को एसआईआर सूची के मसौदे की गणना प्रक्रिया से गलती से बाहर कर दिया गया है।

व्यापक चुनौती चुनावी प्रशासन के कई पहलुओं तक फैली हुई है: अभियान वित्त विनियमों और आदर्श आचार संहिता का ढीला कार्यान्वयन, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अनुपात के बजाय केवल छोटे नमूनों से वीवीपीएटी का मिलान, वीवीपीएटी में प्रतीक लोड करने के लिए अपर्याप्त तकनीकी सुरक्षा और ईवीएम की तकनीकी सुरक्षा को स्वतंत्र विशेषज्ञ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने की अनिच्छा।

मतदान केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज रखने में चुनाव आयोग का विरोध, मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े प्रकाशित करने में देरी, और आलोचना को हमले के रूप में देखने वाली संस्था में तब्दील होना, लोकतांत्रिक मानदंडों से एक चिंताजनक विचलन को दर्शाता है। वर्तमान चुनावी विवादों के मूल में संस्थागत विश्वास का क्षरण है।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता केवल तकनीकी सुदृढ़ता पर ही नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जनता के विश्वास पर भी निर्भर करती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय की उस सिफ़ारिश का पालन किया जाना चाहिए जिसमें चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की बात कही गई है, जिसे वर्तमान में सरकार दरकिनार कर रही है।

श्री गांधी के आरोप जानबूझकर की गई धोखाधड़ी को स्थापित करने में विफल रहे। लेकिन उनकी पार्टी के निष्कर्ष प्रणालीगत खामियों को उजागर करके एक मूल्यवान लोकतांत्रिक कार्य करते हैं। उचित प्रतिक्रिया के लिए व्यापक मतदाता सूची ऑडिट, डेटा साझाकरण में बेहतर पारदर्शिता, ईवीएम कमांड के व्यापक ऑडिट ट्रेल्स और चुनाव चिह्न लोडिंग के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित बेहतर तकनीकी सुरक्षा उपाय, चुनावी नियमों का सख्त प्रवर्तन और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श आवश्यक है। चुनाव आयोग को इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ जाँच-पड़ताल से और मज़बूत होती हैं। विकल्प - चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास का निरंतर क्षरण - लोकतांत्रिक शासन के लिए किसी भी विशिष्ट कदाचार के आरोप से कहीं अधिक जोखिम पैदा करता है।

टैरिफ के साथ, भारत की विकास दर पर सावधानीपूर्वक नजर रखने की जरूरत है

C. Rangarajan

मद्रास के अध्यक्ष हैं
अर्थशास्त्र स्कूल,
चेन्नई

एन.आर. भानुमूर्ति

मद्रास के निदेशक हैं
अर्थशास्त्र स्कूल,
चेन्नई

टी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 अगस्त से भारत के निर्यात पर 25% पारस्परिक शुल्क लगाया। 6 अगस्त को, अमेरिका ने 10% का दंडात्मक शुल्क लगाया।

भारत के निर्यात पर अतिरिक्त 25% की कटौती होगी क्योंकि भारत रूस से तेल आयात करता रहा है और यह 29 अगस्त से प्रभावी होगा। इन दोनों को मिलाकर भारत का अमेरिका को निर्यात कमज़ोर हो सकता है।

हम पहले 25% टैरिफ के प्रभाव की जांच करेंगे और बाद में दंडात्मक दरों के प्रभाव की जांच करेंगे।

भारत का अमेरिका के साथ व्यापारिक अधिशेष है — 2024-25 के लिए यह 41.18 अरब डॉलर था — जो समय के साथ बढ़ रहा है। इस व्यापार अधिशेष को कम करने के लिए, अमेरिका भारत के निर्यात और आयात दोनों पर ध्यान केंद्रित करता प्रतीत होता है। जबकि 25% पारस्परिक टैरिफ भारत के निर्यात में बाधा डाल सकता है, यह जुर्माना निर्यात पर काम कर सकता है और साथ ही रूस से कच्चे तेल के आयात पर एक गैर-टैरी बाधा के रूप में काम कर सकता है, इस प्रकार, भारत को अमेरिका या अन्य जगहों से अधिक कीमत पर कच्चा तेल आयात करने के लिए मजबूर कर सकता है। जबकि अमेरिका के उपाय दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर को कम कर सकते हैं, भारत के विकास और बाहरी खाते पर इसके प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। इस तरह की एकतरफा कार्रवाई मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों के विपरीत है

पारस्परिक टैरिफ का प्रभाव पारस्परिक टैरिफ का तत्काल प्रभाव व्यापार संतुलन पर होगा। यह मानते हुए कि अमेरिका से आयात पर कोई प्रभाव नहीं है (रूस से अमेरिका में तेल आयात के सीमित विविधीकरण को छोड़कर), टैरिफ भारत के अमेरिका के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है लेकिन किस हद तक? यह मानते हुए कि टैरिफ के संबंध में आयात लोच (-) 1 है, जो कि उच्चतर है, भारत का अमेरिका में निर्यात 25% तक कम हो सकता है - यह एक तेज गिरावट है। हालांकि, व्यापार संतुलन पर इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि कुल निर्यात में भारत के अमेरिका के निर्यात का कितना हिस्सा है। चूंकि 2025-26 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए अमेरिकी निर्यात में इस अपेक्षित गिरावट के निहितार्थ 2024-25 के लिए पूर्व-निर्धारित किए गए हैं।

यहाँ तक कि चरम स्थिति में भी, जहाँ लोच (-)1 मानी जाती है, कुल व्यापार घाटा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.56% बढ़कर 7.84% हो जाता है। परिणामस्वरूप, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% से लगभग 0.6% घटकर 5.9% हो जाती है। अधिक चिंता की बात इसका प्रभाव है।

चालू खाता घाटा (CAD) पर। अमेरिका के पारस्परिक शुल्कों के कारण, CAD 0.6% से बढ़कर 1.15% होने का अनुमान है। हालाँकि ये अनुमान 2024-25 के लिए हैं, लेकिन अगर शुल्क वर्ष की शुरुआत से ही प्रभावी होते, तो 2025-26 में प्रभाव की सीमा 2024-25 के इन अनुमानों से बहुत अलग नहीं होती।

हालाँकि, चालू वर्ष (2025-26) में चार महीने बीत चुके हैं, जीडीपी विकास दर में गिरावट 0.4% हो सकती है, और तदनुसार सीएडी भी कम हो सकता है।

कुछ चेतावनियाँ

हालाँकि, ये अनुमान कुछ चेतावनियों के अधीन हैं। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख देशों के साथ बातचीत चल रही है और बाह्य खाते पर उनके प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है। इनका चालू खाते के घाटे पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है।

हम टैरिफ के प्रभावों पर भी विचार नहीं कर रहे हैं भारतीय निर्यात के प्रतिस्पर्धी अन्य देशों पर लगाए गए करों में वृद्धि से भारत के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, हम हाल ही में अमेरिकी व्यापार उपायों और व्यापार संतुलन पर इसके प्रभाव के कारण विनिमय दर में होने वाले किसी भी संभावित बदलाव पर विचार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में, पारस्परिक शुल्क लगाए जाने के बाद से रुपया-अमेरिकी डॉलर का मूल्य तेज़ी से कम हुआ है और ₹87.5 के आसपास मँडरा रहा है। नए व्यापार समझौतों के साथ-साथ रुपये में गिरावट से चालू खाते के घाटे को थोड़ा कम करने में मदद मिल सकती है और साथ ही भारत की जीडीपी वृद्धि पर अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है।

लेकिन 2025-26 और आने वाले वर्षों के लिए, इन दोनों कारकों पर विचार करने के बाद भी, जीडीपी वृद्धि दर 6.5% के आधार मामले वृद्धि पूर्वानुमान से लगभग 0.5% कम रह सकती है; चालू खाता घाटा भी लगभग इसी सीमा तक बढ़ सकता है। इसके अलावा, जुर्माने की धमकी के बाद, कच्चे तेल के आयात में रूस से हटकर अमेरिका की ओर किसी भी बड़े बदलाव का चालू खाता घाटा के साथ-साथ विनिमय दर और घरेलू मुद्रास्फीति पर और अधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, विश्व तेल कीमतों में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता चालू खाता घाटा और उसके

इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

भारत डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के नकारात्मक जोखिमों को कैसे कम कर सकता है? एक विकल्प यह है कि भारत के पास अभी भी अमेरिका के साथ बातचीत की गुंजाइश है क्योंकि व्यापार समझौता अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है, साथ ही कृषि और संबद्ध क्षेत्रों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे विवादास्पद मुद्दों पर झुकना नहीं चाहिए।

दूसरा तरीका यह है, जैसा कि कई लोगों ने सुझाव दिया है, निर्यात बाजार में विविधता लाना संभव नहीं है। लेकिन अल्पावधि में यह कठिन होगा। एक संभावित तरीका यह है कि हम अपने आयातों पर लगाए जाने वाले अपने स्वयं के शुल्कों पर गौर करें। हमारे अनुभवजन्य परिणाम यह दर्शाते हैं कि भारत के निर्यात आयात शुल्कों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। आयात शुल्कों के संबंध में अनुमानित लोच एक (ऋणात्मक) से अधिक है। समय के साथ हमारे निर्यात में आयात सामग्री में वृद्धि के साथ, निर्यात वृद्धि पर शुल्कों का नकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ गया है। सरकार मौजूदा शुल्क दरों पर विचार कर सकती है और उन दरों को कम कर सकती है जिनका निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दंडात्मक शुल्क का प्रभाव: दंडात्मक शुल्क, जो कि 25% है, का प्रभाव पारस्परिक शुल्कों जैसा ही होगा। हालाँकि, कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें इस शुल्क से छूट दी गई है। यहाँ प्रभाव कुछ कम होगा। कुल मिलाकर, भारत की विकास दर पर इसका कुल प्रभाव काफी गंभीर हो सकता है, जो चालू वर्ष की 6.5% की आधार विकास दर से 0.6 प्रतिशत अंकों से अधिक की कमी है।

दंडात्मक कर से बचने के लिए, भारत को इस निर्णय की असमानता को पूरी दुनिया के ध्यान में लाना होगा। यह अत्यधिक भेदभावपूर्ण है। ऐसे कई अन्य देश हैं जो रूस से भारत से कहीं अधिक आयात करते हैं। बातचीत के लिए अभी जो तीन सप्ताह का समय उपलब्ध है, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

दंडात्मक शुल्क के साथ पारस्परिक शुल्क, राष्ट्रों को एक विशिष्ट नीति का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु शुल्कों के प्रयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। भारत को विश्व व्यापार की एक अलग प्रणाली पर वापस लौटने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हालाँकि भारत की विकास दर पर शुल्कों के तत्काल प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की व्यापार व्यवस्था को जारी रखना अमेरिका और भारत सहित सभी देशों के हित में नहीं होगा।

कुल मिलाकर, पारस्परिक कर और दंडात्मक लेवी का कुल प्रभाव

भारत की विकास दर बदल सकती है
गंभीर
होने के लिए

औद्योगिक दुर्घटनाएँ, उदासीनता की मानवीय कीमत

श्रीकांत माधव वैद्य

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं।

ए भारत के तेल और ऊर्जा क्षेत्र में 37 साल बिताने के बाद, इस लेखक ने देश भर के कारखानों, कारखानों और रासायनिक संयंत्रों के अंदरूनी हिस्सों में। इस लेखक ने औद्योगिक दुर्घटनाओं के दुखद परिणामों को करीब से देखा है—दूर की घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि कच्ची मानवीय त्रासदियों के रूप में। ये नियति के कर्म नहीं हैं। ये उन निर्णयों का परिणाम हैं—जो व्यक्तियों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का परिणाम हैं जो उनकी परवाह नहीं करते।

हमने इसे हाल ही में फिर से देखा है - विस्फोटों के रूप में तेलंगाना के सिगाची इंडस्ट्रीज में और तमिलनाडु में एक रीक्रैकर यूनिट में हुई दुर्घटना। ये कोई असामान्य घटनाएँ नहीं हैं। ये एक गहरे, निरंतर राष्ट्रीय संकट के लक्षण हैं।

हर बार एक ब्रह्मांड बिखर जाता है। श्रम मंत्रालय द्वारा संकलित सरकारी आंकड़ों और सूचना के अधिकार पर आधारित कई रिपोर्टों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में भारत के कारखानों, निर्माण स्थलों और खदानों में कम से कम 6,500 मज़दूरों ने अपनी जान गंवाई है। इसका मतलब है कि 21वीं सदी में, बढ़ती अर्थव्यवस्था में, शांतिकाल में हर दिन लगभग तीन मौतें हो रही हैं।

अकेले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, पिछले एक दशक में बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में 200 मौतें हुई हैं। लेकिन वास्तविक संख्या—खासकर अपंजीकृत या अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों में—कहीं ज़्यादा हो सकती है और शायद ही कभी खबरों में आती है। इनमें से हर मामला सिर्फ़ एक आँकड़ा नहीं है। यह एक कमाने वाले के चले जाने, एक बच्चे के अनाथ हो जाने और एक परिवार के सदमे और गरीबी में डूब जाने की कहानी है। इस लेखक ने यह सब देखा है—एक मौत के बाद एक रिन्यूएरी कैंटीन में खाली सीट, प्लांट के गेट के बाहर टहलते परिवार, उस खबर का इंतज़ार करते हुए जो उन्हें पता है कि उन्हें तोड़ देगी।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में 2020 के बाद सिर्फ़ 30 महीनों की अवधि में 130 से ज़्यादा बड़ी रासायनिक दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 218 मौतें हुईं और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इनमें से ज़्यादातर घटनाएँ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) में हुईं, जो अक्सर नियामकीय निगरानी में काम करते हैं।

इन मौतों को और भी अधिक गंभीर क्यों बनाया गया है?

भारत को अपने उद्योगों को चालू रखने के लिए अपने जीवन और अंगों को जोखिम में डालने वाले प्रत्येक श्रमिक को यह आश्वासन देना चाहिए कि औद्योगिक सुरक्षा उनका अधिकार है।

अक्षम्य यह है कि उनके कारण कितने प्राथमिक और परिहार्य हैं: कोई पुन: अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं - कारखाने अग्निशमन विभाग से बुनियादी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना भी चल रहे हैं; कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं - अलार्म, सेंसर, बुझाने वाले यंत्र गायब या खराब हैं; कोई परमिट-टू-वर्क सिस्टम नहीं - उच्च जोखिम वाले काम लापरवाही से किए जाते हैं, बिना किसी औपचारिक खतरे की पहचान या नौकरी सुरक्षा विश्लेषण के; कोई प्रशिक्षण नहीं - विशेष रूप से प्रवासी और अनुबंध श्रमिकों के लिए जो अक्सर अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और साइनेज या सुरक्षा प्रोटोकॉल से अनजान होते हैं; कोई निकास नहीं - या भंडारण सामग्री के नीचे बंद, अवरुद्ध या छिपे हुए निकास; कोई जवाबदेही नहीं - ऑडिट, जब आयोजित किया जाता है, अक्सर बॉक्स पर टिक करने का अभ्यास होता है।

सुरक्षा चूक के लिए दोषसिद्धि दुर्लभ है, तथा दंड भी नगण्य है।

मुख्य मूल्य नहीं: बड़ी कंपनियों में भी, परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान अक्सर बुनियादी सुरक्षा संस्कृति पर हावी हो जाता है। वैश्विक स्तर पर, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने सुरक्षा को औद्योगिक डिज़ाइन और कार्यस्थल संस्कृति में गहराई से समाहित कर लिया है। इसके विपरीत, भारत अभी भी सुरक्षा को एक मुख्य मूल्य के बजाय अनुपालन में एक बाधा मानता है।

जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर सबकी नज़र है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे राज्यों की स्थिति बेहतर है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का भी अपना रिकॉर्ड खराब है।

वास्तव में, मीडिया और राज्य के रिकॉर्ड के अनुसार, गुजरात में केवल एक वर्ष (2021) में 60 से अधिक प्रमुख औद्योगिक रिज़र्व और गैस रिसाव हुए।

कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (DGFASLI) के अनुसार, भारत में पंजीकृत कारखानों में हर दो दिन में एक गंभीर औद्योगिक दुर्घटना दर्ज की जाती है। अपंजीकृत इकाइयाँ क्या हैं? कोई भी ठीक से नहीं जानता।

यह पैटर्न अब इस हद तक परिचित हो गया है कि थकान: त्रासदी, आक्रोश, मुआवज़ा, समिति और फिर चुप्पी। मूल कारण अभी भी बरकरार है। अगली दुर्घटना बस होने का इंतज़ार कर रही है।

इस चक्र को जीवित रखने वाली चीज है राष्ट्रीय

उदासीनता — जनता की चुप्पी, नियामकों की जड़ता, और कंपनियों का लागत-कटौती का आवेग, जो सुरक्षा को दायित्व नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त खर्च मानते हैं। श्रमिकों, खासकर ठेके पर काम करने वालों को, बेकार समझा जाता है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

इसमें एक बहुत ही परेशान करने वाला वर्गीय पूर्वाग्रह भी है। क्या किसी ऊँची इमारत में स्थित कॉर्पोरेट मुख्यालय या किसी सॉफ्टवेयर पार्क में भी इसी तरह की सुरक्षा चूक पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? कड़वी सच्चाई यह है कि इन लोगों की ज़िंदगी को कम आंका जाता है क्योंकि ये लोग कौन हैं - प्रवासी मज़दूर, ठेका मज़दूर और आर्थिक रूप से बेज़ुबान।

'ईश्वरीय कृत्य' एक मुहावरा है जो हम अक्सर सुनते हैं, वह है "ईश्वरीय कृत्य"। यह बाइबिल जैसा लगता है, खुद को दोष से दूर रखने का एक तरीका। लेकिन ये आपदाएँ ईश्वरीय दंड नहीं हैं। ये मानव निर्मित हैं। नेशनल ज्योग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री ने इसी विचार की पड़ताल की थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे दुनिया भर में औद्योगिक दुर्घटनाएँ संयोग से नहीं, बल्कि लापरवाही और विफल प्रणालियों के कारण होती हैं।

दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों में अब कॉर्पोरेट हत्या कानून लागू हैं, जिनके तहत सुरक्षा संबंधी गंभीर चूक के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आपराधिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाता है। भारत को इस पर बातचीत शुरू करनी होगी।

यह केवल नियामक सुधार या बेहतर लेखा-परीक्षण का आह्वान नहीं है। यह सामूहिक विवेक का आह्वान है।
नागरिकों के रूप में, उद्योग जगत के नेताओं के रूप में, मीडिया के रूप में, नीति निर्माताओं के रूप में हमें यह कहना होगा कि, "हमें परवाह है"।

हमें न केवल कंपनियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए बल्कि हमें अपने श्रम सुरक्षा बोर्डों को भी मज़बूत करना होगा, जोखिम रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाना होगा और व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। और हमारे उद्योगों को चलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले हर कर्मचारी के लिए, हमें इस सच्चाई को सामने रखना होगा: औद्योगिक सुरक्षा कोई उपकार नहीं, बल्कि एक अधिकार है।

सवाल यह नहीं है कि क्या हमारे पास इन त्रासदियों को रोकने के साधन हैं। हमारे पास हैं। सवाल बस इतना है: क्या हम कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से चिंतित हैं?
या फिर हम चुप्पी साधकर और हार मानकर उस अनकहे अभियोग को सच साबित करते रहेंगे? किसे परवाह है?

द टटर्सटूदएडिटर

'चुनाव चोरी' का सबूत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता चोरी के आरोपों को "वोट चोरी के सबूत के रूप में परमाणु बम " के रूप में पेश करना चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर गंभीर सवाल उठाता है।

गांधीजी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी की टीम ने मतदाता आंकड़ों का विश्लेषण करके गंभीर अनियमितताओं का पता लगाने में छह महीने लगा दिए, जो इतना गंभीर है कि इसे न तो भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) और न ही ऐसी अनियमितताओं की कथित लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी, खारिज कर सकती है। चुनाव आयोग की संस्थागत ईमानदारी और उसकी क्षमता दांव पर है। श्री गांधी ने पूरा और सत्यापन योग्य आंकड़ा पेश किया है।

सार्वजनिक डोमेन में। चुनाव आयोग को इन आरोपों की पारदर्शी तरीके से जाँच करनी चाहिए। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उनके आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण पाए गए तो श्री गांधी और उनकी पार्टी को भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

एसके चौधरी, बेंगलुरु

इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी के सबूतों के आधार पर किए गए खुलासे पर सवाल उठाने के लिए। यह विचार करना ज़रूरी है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक टीम ने महीनों तक कागज़ों के ढेर से प्रविष्टियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने का एक असंभव सा लगने वाला काम पूरा किया। अगर इसी तरह का काम कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाए, तो और भी रहस्य उजागर हो सकते हैं।

आम आदमी को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि चुनाव आयोग श्री गांधी के चुनाव आयोग से झगड़े में तकनीकी पहलुओं की तलाश कर रहा है। वे तो बस मतदाता सूची में हेराफेरी के उनके हर 'खुले और साफ़' मामले का स्पष्ट जवाब चाहते हैं।

Kamal Laddha,
Bengaluru

निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का मतलब सिर्फ़ मतदान प्रतिशत की गणना करने का गौरव हासिल करना नहीं है। इसका मतलब एक सच्ची मतदाता सूची भी है। चुनाव आयोग को यह साबित करना होगा कि वह साफ़-सुथरा है।

एम. जेवियर,
वल्लियोर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु

अगर कांग्रेस नेता के आरोपों में कोई दम या प्रमाणिकता है, तो यह लोकतंत्र पर गहरा आघात है। कांग्रेस द्वारा दिए गए सबूत

नेता का मामला पहले से ही सार्वजनिक है और चुनाव आयोग सीधे तौर पर विस्तृत जाँच शुरू कर सकता है। अगर जाँच में आरोप झूठे साबित होते हैं, तो कानून को उनके खिलाफ अपना काम करने दें। अन्यथा, चुनाव आयोग की सर्वोच्चता, पवित्रता और ईमानदारी पर संदेह करने का पूरा औचित्य होगा।

V. Johan Dhanakumar,
चेन्नई

"वोट चोरी" के आरोप ने चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस फिर से छेड़ दी है। भाजपा इसे "चुनिंदा आक्रोश" बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कभी सवाल नहीं उठाया, जहाँ उसे जीत मिली। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, मतदाता सूची में जल्दबाजी में संशोधन के खिलाफ चेतावनी देते हुए, इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किसी भी तरह का पक्षपात या

मताधिकार से वंचित करना—खासकर गरीबों का—एक "भयावह विकास" होगा। मेरा मानना है कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होने के नाते, चुनाव आयोग चुनावी हार के बाद विपक्षी दलों के लिए एक आसान निशाना बन जाता है—ठीक वैसे ही जैसे विपक्ष में रहते हुए भाजपा भी ऐसा ही करती। कांग्रेस, जो लंबे समय से सत्ता में रहने की आदी रही है, सत्ता से बाहर होने के लिए खुद को ढालने को तैयार नहीं दिखती।

हालाँकि, भाजपा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को तटस्थ तीसरे सदस्य के रूप में स्वीकार न करके गलती की है, जिससे संस्थागत विश्वास मज़बूत होता। एक मज़बूत लोकतंत्र दोनों की माँग करता है: विश्वसनीय चुनाव और संयम

संवैधानिक को कमजोर करना

बिना किसी ठोस सबूत के शवों को बरामद किया गया।

गोपालस्वामी जे., चेन्नई

यह दुःखद है कि श्री. गांधी अपनी गिरती छवि को बचाने के लिए भारत के चुनाव आयोग जैसी प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था के खिलाफ अनुचित और अपमानजनक आरोप लगाकर इतना नीचे गिर गए हैं। सार्वजनिक रूप से छिछले बयान देने की अपनी आदत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद भी उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया है।

श्री गांधी को हमारे लोकतंत्र पर इस तरह गैरजिम्मेदाराना तरीके से हमला करने से बचना चाहिए।

Ravi Mathur,
Noida, Uttar Pradesh

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 9 अगस्त 2025

दूर हो आशंका

इलेक्टोरल रोल में धांधली के आरोप

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच का विवाद दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है। दुर्भाग्य से दोनों पक्ष आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। ध्यान रहे, यहां दांव पर चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता है। इसलिए किसी भी आशंका को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।

कोई विवाद न रहे

EC पर सवाल । कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियां लंबे वक्त से चुनाव आयोग पर हमलावर रही हैं। EVM को लेकर काफी बहस हो चुकी है और इस पर हंगामा भी हुआ है। लेकिन, देश के सामने अभी जो सीन चल रहा है, वह अभूतपूर्व है। राहुल गांधी के आरोप सीधे-सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईमानदारी और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल हैं।

एकजुट विपक्ष । राहुल ने इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्टोरल रोल को लेकर धांधली का आरोप लगाया था। इस बार उन्हें दूसरे विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। राहुल का आरोप है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हुए हालिया विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक, चुनावों के ऐन पहले बड़े पैमाने पर नए नाम जोड़े और काटे गए, जिसका फायदा कथित तौर पर BJP को मिला। राहुल के इन आरोपों को BJP बेबुनियाद बताती आई है। वह कहती है कि राहुल की यह चुनावी हार की खीझ है।

स्पष्ट जवाब चाहिए । वहीं, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा मांगा है। साथ ही, कर्नाटक समेत तीन राज्यों के चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के नाम देने को कहा है, जो उनके हिसाब से गलत ढंग से काटे या जोड़े गए। इस मामले में चुनाव आयोग को बिंदुवार और स्पष्ट ढंग से अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

गंभीर संकट । राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, और विपक्ष में होने के नाते उनका काम है कमियां उजागर करना व सरकार से जवाब मांगना। चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। इन दोनों की ही बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में। इस क्रम में इनकी एक-दूसरे से असहमति, शिकायत मान्य है। लेकिन, अभी का घटनाक्रम असहमति से बहुत आगे निकल चुका है। जिस तरह से दोनों के बीच सार्वजनिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, वह ठीक नहीं है। इस पर जल्द विराम लगना चाहिए।

अंतर्दृष्टि

दुख नहीं बांटते हम और भीतर से टूटते जाते हैं

सुंदर चंद ठाकुर

हम सब जी रहे हैं। हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रहे हैं, मीटिंग्स में भाग ले रहे हैं, घर चला रहे हैं, पर क्या भीतर से सच में ठीक हैं? बहुत कुछ है, जो हम भीतर छुपा कर रखते हैं, ऐसा जो हमने कभी किसी से कहा ही नहीं। शायद इस डर से कि लोग समझेंगे नहीं। या इस संकोच से कि अगर हम बोलेंगे, तो लोग हमें कमजोर समझ लेंगे। या शायद इसलिए कि अब हमें खुद को भी वह दुख याद नहीं। बचपन से हमें सिखाया गया कि रोना अच्छा नहीं। 'लड़के रोते नहीं', 'मजबूत लोग शिकायत नहीं करते', 'सब ठीक हो जाएगा' - ये वाक्य इतने बार सुने कि अब अपने ही दर्द को महसूस करना हमें गलत लगने लगा है। और जब महसूस ही नहीं करते, तो बांटना भी नहीं आता। लेकिन यह दुख, जो हम बोल नहीं पाते, वह समाप्त नहीं होता।

हम दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कराते हैं, पर भीतर कोई हिस्सा रो रहा होता है। और यह रोना तब सबसे खतरनाक होता है, जब हम खुद से भी छिपाने लगते हैं। हम कामयाबी की कहानियां सुनाते हैं, पर दिल की हार किसी को नहीं बताते। लोग कहते हैं - 'कितना सफल है', पर कोई नहीं जानता कि वह व्यक्ति रात को नींद की दवा लेकर सोता है। और यह सब इसलिए, क्योंकि हम अपना दुख नहीं बांटते। ऐसे में हमें खुद अपने लिए वह साथी बनना होगा। खुद को वह स्थान देना होगा, जहां हम खुद से ही बोल सकें। दिन में कुछ समय निकालकर खुद से पूछें - 'मैं कैसा महसूस कर रहा हूं?', 'क्या कोई बात है, जो मुझे परेशान कर रही है?' और अगर उत्तर में दुख मिले - तो उसे दबाएं नहीं। उसे डायरी में लिखें, आंखों में भर लें या आईने में देखकर कहें - 'मैं जानता हूं, मैं थका हुआ हूं, पर मैं तुम्हारे साथ हूं।'

जब हम अपना दुख पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसका असर बदल जाता है। वह बोझ नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। और जब हम किसी को अपना दर्द बांटते हैं - शब्दों में या मौन में, तो हम भीतर से थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। दुख बांटने का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों पर निर्भर हैं। इसका अर्थ है कि हम इंसान हैं और इंसान का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह महसूस करता है। अगर हम अपने आसपास किसी को चुप देखें, तो बस इतना कहें - 'मैं हूं, अगर तुम बोलना चाहो तो'। कई बार एक वाक्य, एक उपस्थिति, एक हाथ, एक सन्नाटा - किसी टूटते हुए मन को थाम सकता है। हमारा दुख तब तक बढ़ता है, जब तक वह अकेला रहता है। और जैसे ही वह साझा होता है, वह दवा बनने लगता है। शब्द बांटिए, मौन बांटिए, आंसू बांटिए, क्योंकि जब हम बांटते हैं, तो हम जुड़ते हैं और जब हम जुड़ते हैं हम ठीक होने लगते हैं।

ऑफ़ दि ट्रैक

धरती का मुड़ना!

दिलीप लाल

म्यांमार में इस साल आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के दौरान एक सीसीटीवी कैमरे ने ऐसा दृश्य रिकॉर्ड किया, जिसने चौंका दिया। आमतौर पर भूकंप में जमीन पर सीधी दरार बनती है, लेकिन इस बार धरती न केवल टूटी, बल्कि मुड़ी भी, जो वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद दुर्लभ है। यह कैमरा सगाइंग फॉल्ट से मात्र 20 मीटर दूर लगा था। सगाइंग फॉल्ट भारतीय और सुंडा प्लेट के बीच स्थित एक प्रमुख भूगर्भीय दरार है। यह म्यांमार के मध्य भाग में उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली है और सगाइंग, मांडले व नेप्यीडॉ से होकर गुजरती है। शुरुआत में विडियो में तेज झटके और जमीन खिसकने के दृश्य थे, लेकिन जापान के Kyoto University के भूभौतिक विज्ञानी Kearse और Yoshihiro Kaneko ने गौर किया कि जमीन पर एक घुमावदार दरार बन रही थी। आमतौर पर भूकंप में फॉल्ट के दोनों ओर की चट्टानें खिसककर सतह पर खरोंच जैसी रेखाएं बनाती हैं, जिन्हें slickenlines कहा जाता है। इस फुटेज में पश्चिमी हिस्सा उत्तर की ओर सीधी रेखा में नहीं, बल्कि हल्के मोड़ के साथ खिसक रहा था। शुरुआती क्षणों में यह खिसकन अधिक मुड़ी हुई थी, जो धीमी होने पर सीधी हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि सतह पर तनाव घटने के कारण फॉल्ट की दिशा बदलती है, फिर वह स्थिर हो जाती है।

चुनावी तारीख़ आने से पहले अलायंस मज़बूत करने पर ध्यान

बिहार में चल रहा चुनावी शतरंज

प्रियरंजन भारती

चुनावी समीकरण
- चिराग पासवान की LJP इस बार NDA का हिस्सा
- VIP पाला बदल कर महागठबंधन में
- पार्टी से निकल तेज प्रताप भी ठोक रहे हैं ताल

बिहार में फिलहाल भले चुनाव आयोग के अभियान SIR को लेकर तलवारें तनी दिख रही हों, चुनावी लड़ाई की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कई नए समीकरण बने हैं और दिन-ब-दिन बन रहे हैं। इसलिए नतीजों का अनुमान लगाना आसान नहीं है। खास बात यह कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है।

नीतीश के नाम पर । BJP-JDU गठबंधन इस बार भी नीतीश के नाम पर मैदान में है। उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के साथ अलायंस इस बार भी सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश में है। राज्य और केंद्र सरकार ने अपने दावों के जरिये विकसित बिहार की झलक पेश की है और इसी आधार पर जनता के बीच हैं। बिहार में चुनाव से पहले उद्घाटनों और शिलान्यास कार्यक्रमों की होड़ लगी है।

युवा नेतृत्व पर जोर । तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन नीतीश कुमार की कथित 'खटारा सरकार' को हटाकर नए स्वरूप की युवा नेतृत्व वाली सरकार देने का वादा कर रही है।

तेज प्रताप की चुनौती । प्रशांत किशोर ने दोनों ही गठबंधनों से अलग नए विकल्प का सपना जनता को दिखाया है। वह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नए मॉडल की सरकार बनाने का वादा कर रहे हैं। इस बीच, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद विरासत वोट बैंक पर दावा कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि वह तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी से अलग हुए गुट VVIP समेत पांच दलों के साथ गठबंधन किया है। तेज प्रताप मुस्लिम-यादव समीकरण में सेंध लगाने में कामयाब हुए तो तेजस्वी के लिए मुश्किल हो सकती है।

सीमांचल में ओवैसी । असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सीमांचल और मिथिलांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पहले ही अपनी धमक दिखा चुकी है। इस दफा उसने BJP को हराने की नीयत से महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की है। दिक्कत इस मामले में यह दिख रही है कि उसकी 40 सीटों की मांग वाली शर्त शायद ही तेजस्वी यादव को मंजूर होगी।

बड़े दावे, बड़ी मांग । पिछली बार NDA का हिस्सा बनकर BJP के हिस्से की 11 सीटों पर चुनाव में उतरी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने चार सीटें जीती थीं। बाद में BJP ने उसके पूरे विधायक दल को ही अपने में समाहित कर लिया। इस बार सहनी, तेजस्वी के साथ हैं। विधानसभा में साठ सीटें और सरकार बनने पर उपमुख्यमंत्री पद की शर्त इनकी मांग है। कांग्रेस का अलग दबाव है कि उसे उतनी ही सीटें चाहिए जितनी पर वह पिछली बार चुनाव लड़ी थी। तब उसे 70 सीटें मिली थीं, मगर पार्टी 19 पर ही जीत सकी थी। तेजस्वी यादव ने तब कहा था कि कांग्रेस इतनी सीटें न गंवाती तो गठबंधन को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाता।

विकल्पों की भरमार । कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया और चुनाव से पहले रणनीतिक रूप से RJD के समक्ष मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनाव बाद तय किए जाने का दबाव बनाया। बहरहाल, दोनों दलों में अब बढ़िया समझ विकसित होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे की रूपरेखा अभी तय नहीं हो सकी है। असल में टिकट कट जाने से नाराज नेता अक्सर विरोधी खेमे का रुख कर लेते हैं। इस दफा ऐसे नेताओं के पास विकल्प भी ज्यादा हैं। पीके की जनसुराज, तेज प्रताप का मोर्चा और AIMIM अभी से ऐसे संभावित उम्मीदवारों पर नजरें टिकाए हुए हैं। ऐसे में बड़ी पार्टियों और गठबंधनों का सतर्क होना लाजिमी है।

क्या चाहते हैं चिराग । पिछली बार लोकजनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान NDA से बाहर थे। JDU की सीटें कम करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इस बार उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि इस बार भी वह सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। वह विधानसभा चुनाव खुद भी लड़ना चाहते हैं।

आंतरिक रस्साकशी । इसे NDA के अंदर BJP की छुपी हुई चाल के रूप में देखा जा रहा है। समझा जाता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के वैकल्पिक उम्मीदवार के बतौर पेश करते हुए BJP महाराष्ट्र फॉर्म्युले की पुनरावृत्ति से बिहार में अपनी सरकार बनवाना चाहती है।

किसे होगा फायदा । कुल मिलाकर देखा जाए तो लड़ाई को बहुकोणीय बनाने वाली ताकतों की भूमिका इस बार काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि प्रशांत किशोर आखिरकार किसका पलड़ा भारी करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

तेल पर फिसले डॉन

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप रूस से व्यापारिक संबंध खत्म करने के लिए भारत पर दबाव बना रहे हैं। उनका जोर है कि कोई भी देश रूस से तेल न खरीदे। लेकिन, यह नीति US को कम, चीन को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है।

5 पॉइंट

1 बैन में मुश्किलें
भारत की ज्यादातर रिफाइनरी रूस के बाहर से क्रूड ऑयल खरीदती हैं यानी उनकी सीधी डील रूस के साथ नही है। ऐसे में US या EU के प्रतिबंधों को लागू करने में दिक्कत हो सकती है।

2 ग्लोबल फ्लो
ऑयल रिफाइनिंग में भारत की ग्लोबल हिस्सेदारी 5% है। रूस से भारत जो क्रूड आयात कर रहा, उसका एक हिस्सा रिफाइन करके पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों से इस फ्लो पर असर पड़ेगा।

3 भरपाई कैसे होगी
रूस से भारत हर दिन लगभग 20 लाख बैरल क्रूड खरीद रहा है। अगर इस पर रोक लगती है, तो भरपाई कैसे होगी? विकल्प के तौर पर खाड़ी देशों का नाम लिया जा रहा, लेकिन उन पर पहले से ही दबाव है।

4 कीमतें बढ़ेंगी
क्रूड ऑयल प्रॉडक्शन में रूस की हिस्सेदारी 11% है। वह अपना तेल भारत और चीन के जरिये दुनिया में पहुंचा रहा है। यह सप्लाई रुकी तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। ईरान पर US बैन के दौरान ऐसा हो चुका है।

5 मुनाफे में चीन
रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। भारत के हटने पर रूस से चीन ज्यादा तेल खरीद सकता है। ऐसा होने पर रिफाइंड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी।

प्रस्तुतिः शैलेंद्र पांडेय

25 रुपये के गिटार ने यूं बदली मेरी ज़िंदगी

*पंडित विश्व मोहन भट्ट ऐसे संगीतज्ञ हैं, जिन्होंने मोहन वीणा वादन से दुनिया भर में नाम कमाया है। उनकी इस विशेषता से भी लोग वाकिफ हैं कि वह जिस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, उस मोहन वीणा का आविष्कार उन्होंने स्वयं किया। हाल ही में वह 75 वर्ष के हो गए। उनकी लंबी संगीत यात्रा पर उनसे बात की **प्रदीप सरदाना** ने। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंशः*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

पंडित विश्व मोहन भट्ट

■ आज आप जब पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा को देखते हैं, तो आपको क्या अनुभूति होती है?

इस दौरान कई बदलाव हुए। हम भी समय के साथ बदलते रहे। सबसे अच्छा बदलाव मुझे तकनीक का लगा। जैसे पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था। हम जब संगीत सीख रहे थे तो संगीत सुनने के लिए सिर्फ आकाशवाणी पर निर्भर थे। म्यूजिक डाउनलोडिंग नहीं थी। आज दुनियाभर का संगीत घर बैठे सुना जा सकता है, उसे संजोया जा सकता है। हालांकि नई तकनीक में अब AI भी जुड़ गया है। लेकिन मुझे आशंका है कि इसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग ज्यादा होगा। आधुनिक तकनीक ने संगीत की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है।

■ आपको लगातार कई बड़े पुरस्कार मिले। पद्मश्री, पद्मभूषण, संगीत नाटक अकादमी, यहां तक विश्व संगीत का शिखर पुरस्कार ग्रैमी भी...

मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। इसके लिए मैं अपने श्रोताओं, शुभचिंतकों और प्रशंसकों का आभारी हूं। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं कभी उपलब्धियों के पीछे भागता नहीं हूं। किसी पुरस्कार को लेकर कोई योजना नहीं बनाता। अपना पूरा ध्यान अपने संगीत पर केंद्रित रखता हूं। उसके बाद जो भी झोली में आए, वह अच्छा है।

■ ग्रैमी अवॉर्ड के उन दिनों को याद कर आज कैसा लगता है?

1994 में संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना निश्चय ही सुखद रहा। लेकिन जब ग्रैमी अवॉर्ड दिलाने वालों के यहां हमारे एल्बम 'ए मीटिंग बाई द रिवर' की रेकॉर्डिंग हो रही थी, तब मैंने कभी यह महत्वाकांक्षा या योजना नहीं बनाई थी कि इसे ऐसे बजाओ या ऐसे करो, तो ग्रैमी मिलेगा। हम तो पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी और अनुशासन से काम कर रहे थे। मैंने देखा है, ईमानदारी के काम की एक अलग खुशबू होती है और वह सभी को महसूस होती है।

■ आपके मन में मोहन वीणा का आविष्कार करने का विचार कब और कैसे आया?

मैंने पंडित बृजभूषण काबरा जी को गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते देखा तो मैं काफी प्रभावित हुआ। किसी पश्चिमी वाद्य यंत्र पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने का पहला श्रेय उनको है। उन्हें देख मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा करूंगा, लेकिन गिटार में कुछ न कुछ बदलाव करके। 1967 में हमारे पिताजी मनमोहन भट्ट जी से संगीत सीखने के लिए जर्मनी से एक लड़की आई हुई थी, जिसके पास गिटार था। जब वह जर्मनी वापस जाने लगी तो उससे वह गिटार हमने 25 रुपये में खरीद लिया। वह मेरा पहला गिटार था। मैंने उसमें तरब के 20 तार और तुंबा लगाया और मोहन वीणा नाम दिया। इसमें गायकी अंग और तंत्रकारी अंग दोनों का सुंदर समावेश है। हालांकि मुझे इस बात का कोई अभिमान नहीं है कि मैं मोहन वीणा का जनक हूं। लेकिन संतुष्टि मिलती है और मैं संगीत की दुनिया में इसे अपना विनम्र योगदान मानता हूं।

■ आपके प्रिय राग कौन से हैं?

मेरा सर्वप्रिय राग तो यमन है। फिर शाम कल्याण राग भी मुझे काफी पसंद है। साथ ही हंस ध्वनि भी। यूं सुबह के समय राग भैरव और रात्रि काल में राग बागेश्वरी हृदय के तारों तक को झंझोर देते हैं।

■ आपके बारे में कहा जाता रहा है कि आपने कई देशों की नागरिकता ठुकरा दी और भारत में ही रहना पसंद किया...

मैं अपने देश, अपनी मिट्टी, अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं। मैंने बरसों पहले ही यह संकल्प लिया कि मैं अंत तक अपना शहर जयपुर छोड़कर नहीं जाऊंगा। जयपुर में हमारी पुश्तैनी हवेली रही है। आपको बता दूं यह हवेली हमारे पूर्वजों को 300 साल पहले जयपुर के महाराजा ने तब दी थी, जब जयपुर बन रहा था। तब से अब तक हमारी 7 पीढ़ियां यहीं रहती चली आ रही हैं।

> **"पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था। हम जब संगीत सीख रहे थे तो संगीत सुनने के लिए सिर्फ आकाशवाणी पर निर्भर थे। म्यूजिक डाउनलोडिंग नहीं थी। आज दुनियाभर के संगीत को घर बैठे सुना जा सकता है, संजोया जा सकता है। नई तकनीक में अब AI भी जुड़ गया है। लेकिन मुझे आशंका है कि इसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग ज्यादा होगा**

■ आपके गुरु आपके पिताजी रहे। अब आप अपने बेटों सलिल भट्ट और सौरभ भट्ट के गुरु हैं। शिष्य के रूप में आपको अपना कौन सा पुत्र ज्यादा प्रिय है?

मुझे दोनों प्रिय हैं। तुलना इसलिए नहीं कर सकता कि दोनों संगीत में होने के बावजूद अलग-अलग क्षेत्र में हैं। सलिल तो मोहन वीणा ही बजाते हैं। सौरभ विभिन्न प्रॉजेक्ट्स के लिए संगीत देते हैं। सौरभ के पुत्र अथर्व और विहान भी मोहन वीणा बजाते हैं। सलिल का पुत्र सात्विक भी मोहन वीणा बजाता है।

■ विदेशों में सबसे अच्छे श्रोता कहां के लगे?

मैं अभी तक 80 देशों की यात्रा कर चुका हूं। श्रोता सभी जगह ही अच्छे हैं। फिर भी फ्रांस और ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने वाले श्रोता कमाल के हैं। मैं अभी स्विट्जरलैंड से लौटा हूं तो वहां भी श्रोता हमारे संगीत से अभिभूत थे। जहां मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में 190 देशों के प्रतिनिधियों के सम्मुख अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं जहां भी जाता हूं वहां अपनी ग्रैमी विजेता धुन तो बजाता ही हूं, साथ ही अपने राजस्थान का 'केसरिया बालम पधारो म्हारे देश' की प्रस्तुति भी देता हूं।

www.nbt.in

रोज़-रोज़ कोई घर नहीं आता

खुद अपनी आंख से

सरस्वती रमेश

मैं दसवीं में थी। रक्षाबंधन पर घर में मेहमानों का तांता लगा था। पापा की तीन सगी बहनों के अलावा मौसी, मामा, चाचा की बेटियां आई थीं। जैसे इतना काफी न हो, मां की मुंहबोली बुआ की पोतियां भी मेरे भाइयों को राखी बांधने आई थीं। सबके साथ छोटे-छोटे बच्चे भी थे, जिन्हें हम चवन्नी-अठन्नी कहते थे। मां सबकी खातिरदारी कर रही थीं। इतनी बड़ी पलटन को देखकर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मां को लगातार काम करता देखकर मुझे गुस्सा आया। मैं कुछ बड़बड़ाने लगी। मां ने मुझे झिड़क दिया, 'घर आए महमानों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। कोई रोज-रोज थोड़े ही आता है।'

बुआ के बच्चे इतने उत्पाती थे कि घर में कोई चीज जगह पर न रही। जैसे बच्चे न हों बम हों, जो आते ही फट पड़े। चारों ओर घर बिखर गया। ऐसा हर राखी पर होता। शाम तक घर में इतना कोलाहल मचा रहा जैसे बारात आई हो। बड़े से घर का कोई कोना सुकून भरा न मिला कि मैं अपनी पढ़ाई कर लूं। शाम को कुछ बहनें अपना नेग लेकर अपने असली भाइयों के घर धावा बोलने निकल गईं। मगर पापा के सारे भाई आसपास ही रहते थे। तीनों बुआ उनको राखी बांध हमारे घर लौट आईं। रात यहीं रुकीं। अगले दिन सुबह बड़ी और छोटी बुआ भी अपने नेग ले चली गईं। मगर मझली न गईं। वह जब भी आतीं, अपने चार बच्चों के साथ दस-पंद्रह दिन जरूर रुकतीं। बुआ और बच्चे पूरी बारात पर भारी थे। कारण, वे दिन भर खाते थे। मां दोनों जून ढाई-ढाई किलो आटे की रोटियां बनातीं। सारा दिन अकेली रसोई पकातीं, फिर आंगन में नल के नीचे बरतन, कपड़े धोती रहतीं। बुआ के नाक बहाते बच्चे मुझे जरा भी न सुहाते। मैं बस यही सोचती कि ये कब जाएंगी?

जिस दिन बुआ जा रही थीं, मैं बहुत खुश हुई। मगर जाते हुए बुआ मां से लिपटकर रोने लगीं। मां उन्हें देर तक जाने क्या समझाती रहीं। फिर बुआ चली गईं। मैंने मां से पूछा, बुआ क्यों रो रही थीं? 'दुखियारी हैं', मां ने कहा। असल में फूफा गुजरात में बढ़ई थे। दो-ढाई साल में कुछ दिन के लिए आते। कभी पैसे नहीं भेजते थे। आकर भी हजार-पांच सौ ही देते। बुआ के घर खाने की हमेशा तंगी रहती। बुआ एक-एक पैसे की मोहताज रहतीं। हमारे घर आकर उसे अच्छा खाना और मां का प्यार मिलता। मां उसे कपड़े और पैसे भी देती थीं। दादी कंजूस थीं, बुआ को कुछ न देती थीं। यह बात समझ आने के बाद बुआ के प्रति मेरी नापसंदगी खत्म हो गई। बुआ के बच्चों के प्रति अपने बर्ताव पर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं अगली बार बुआ के आने की प्रतीक्षा करने लगी कि इस बार उनसे अपनापे से मिलूंगी। मगर बुआ फिर कभी न आ पाईं। उस रक्षाबंधन घर जाते ही बुआ बीमार पड़ गईं और इलाज के अभाव में चल बसीं। अब भी रक्षाबंधन आते ही बुआ की याद चली आती है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

चलते-चलते...

ताजे फलों के फायदों से हम सभी वाकिफ हैं। Journal of Agriculture and Food Chemistry में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, ताजे अंगूरों में 1,600 से अधिक प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। ये यौगिक हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, आंखों और आंतों के लिए फायदेमंद हैं। साथ ही त्वचा को UV किरणों से भी बचाने में मदद करते हैं।

रीडर्स मेल

फिर भगदड़, जिम्मेदार कौन?

कुबेरेश्वर धाम के सीहोर में कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण 7 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। भगदड़ से होने वाली मौतों के लिए अब जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति भीड़ एकत्र करे, वह सीधे-सीधे जिम्मेदार माना जाना चाहिए। धार्मिक स्थल (या अन्य समारोह में) और कथा प्रवचनों में जो भी आयोजक हों, उन्हें ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को निगरानी करने की जरूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आयोजकों को अपने निजी कार्यकर्ता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड पर्याप्त संख्या में रखने चाहिए, ताकि बदइंतजामी न हो पाए। तय सीमा से ज्यादा लोगों की भीड़ भी एकत्र नहीं होने देने के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। आजकल तो आयोजकों और बड़े-बड़े कथा-प्रवचन देने वालों में एक प्रकार की होड़ चल रही है कि कौन ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी चक्कर में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जा रही है। सरकार को अब नया कानून बनाना चाहिए कि आयोजन स्थल पर किसी भी हादसे के लिए कर्ताधर्ता, आयोजकों की तमाम जवाबदारी रहेगी।

हेमा हरि उपाध्याय 'अक्षत', ईमेल से

ईडी की कार्यशैली पर चिंता

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि ईडी 'बदमाश' की तरह काम नहीं कर सकती और उसे कानून के दायरे में रहकर जांच करनी चाहिए। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पीएमएलए के तहत एजेंसी को मिली शक्तियों की समीक्षा करते हुए दोषसिद्धि की बेहद कम दर पर सवाल उठाए। जैसा कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में दर्ज 5,000 मामलों में दोषसिद्धि 10% से भी कम रही है, जो स्वतंत्रता के अधिकार पर खतरा दर्शाती है।

अमृतलाल मारू 'रवि', ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

किसान हित सर्वोपरि

किसान मुद्दे भारत के लिए अति संवेदनशील हैं। भारत में अधिकतर लोगों का जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इसलिए भारत में किसान हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया और बाद में उसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। ट्रम्प भारत पर दबाव बढ़ाकर अपनी सभी मनमानी शर्तें मनवाना चाहते हैं लेकिन भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार महान कृषि वैज्ञानिक एन.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प की धमकियों का दो टूक जवाब देते हुए कहा कि "भारत अपने किसानों, पशु पालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है और मैं उनके कल्याण के लिए किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार हूं।" यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील किसान हितों के मुद्दे पर ही अटकी हुई है। ट्रम्प दबाव बनाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू करने की तिथि भी 27 अगस्त रखी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भारत किसानों के मुद्दे पर अमेरिका से क्यों टकरा रहा है।

भारतीय किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए बाजारों तथा उनकी जमीन पर कार्पोरेट नियंत्रण के खिलाफ लम्बा आंदोलन किया था। अमेरिका भारत को अपने माल का डंपिंग यार्ड बना देना चाहता है। अमेरिका में एक क्विंटल गेहूं के उत्पादन की लागत 1700 रुपए है जबकि भारत सरकार द्वारा एक क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए है। भारतीय किसानों के पास औसतन एक हेक्टेयर से कम जमीन है। अगर गेहूं और धान के भारतीय बाजार को अमेरिकी कम्पनियों के लिए खोल दिया जाए तो भारतीय किसानों की हालत क्या होगी यह सब जानते हैं।

अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, फल और बादाम-पिस्ते जैसे मेवों को बिना किसी शुल्क के भारतीय मार्केट में एंट्री मिले लेकिन भारत ने अब तक सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और सेब जैसे कुछ उत्पादों के लिए ही बाजार खोलने पर सहमति दी है। जबकि मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी जैसे सेक्टर्स के लिए भारत सख्ती से मना कर रहा है। इसके पीछे असली वजह यह है कि अमेरिका के अधिकतर मक्का और सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) होते हैं, जबकि भारत में अभी तक जीएम फसलों के आयात की इजाजत नहीं है। भारत में जीएम फसलों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जाता है और खुद बीजेपी से जुड़े कई संगठन जीएम फसलों के विरोध में हैं। जीएम फसलों के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी भारत-अमेरिका ट्रेड डील में एक बड़ा टकराव का मुद्दा बने हुए हैं। भारत में डेयरी केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि करोड़ों छोटे और भूमिहीन किसानों की आय का साधन है।

भारतीय किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए बाजारों तथा उनकी जमीन पर कार्पोरेट नियंत्रण के खिलाफ लम्बा आंदोलन किया था। अमेरिका भारत को अपने माल का डंपिंग यार्ड बना देना चाहता है। अमेरिका में एक क्विंटल गेहूं के उत्पादन की लागत 1700 रुपए है जबकि भारत सरकार द्वारा एक क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए है। भारतीय किसानों के पास औसतन एक हेक्टेयर से कम जमीन है। अगर गेहूं और धान के भारतीय बाजार को अमेरिकी कम्पनियों के लिए खोल दिया जाए तो भारतीय किसानों की हालत क्या होगी यह सब जानते हैं। अमेरिका भारत के साथ अपने 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए गेहूं, कपास, मक्का, सोया, अमेरिकी मक्खन और दूध उत्पाद के लिए भारत का बाजार खोलने के लिए दबाव डाल रहा है। भारत इन उत्पादों के लिए पहले ही आत्मनिर्भर है। दूसरा संवेदनशील पहलू यह भी है कि अमेरिकी पशुपालन में जानवरों को भी मांस खिलाते हैं। वे अधिक दूध के लिए गायों को भी मांसाहार परोसते हैं। भारत की एक बड़ी आबादी शाकाहारी है। अमेरिका के डेयरी उत्पाद उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से मेल नहीं खाते। भारतीय किसान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और उनकी आत्महत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है।

सबसे बड़ा सवाल लाखों भारत के छोटे किसानों की आजीविका का है। कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में 16 प्रतिशत योगदान देता है। कोरोना महामारी के काल में अगर किसी सैक्टर ने भारत को बचाया है तो वह कृषि क्षेत्र ही रहा। महामारी के दिनों में भी कोई भारतीय भूखा नहीं सोया। ऐसे में किसान हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। हमें विश्व बाजार में भारतीय कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, कृषि अनुसंधानों एवं खाद्य परसंस्करण पर ध्यान देना होगा। भारत को ऐसी मोर्चाबंदी करनी होगी जिससे कई देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार बढ़े और हम अमेरिका की चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य पैदा कर सकें।

रेशम के धागे में...

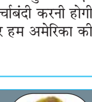

गीता पाढा

"इस रेशम के धागे में सिमटा अथाह प्यार है,
चंदन के उस तिलक को लगाकर
बहन कर रही भाई से दुलार है,
दुनिया के सभी भाई बहनों में हमेशा बना रहे ऐतबार है,
इस रक्षाबंधन पर भाई तुमसे यही विनम्र गुहार है,
संसार में किसी भी बहन, बेटी के साथ
न करों तुम कभी ग़लत व्यवहार है,
हर आंच से पहले बनो उनकी ढाल,
यही मेरा राखी का उपहार है...।"

'मन की बात' कार्यक्रम से अब तक 34.13 करोड़ रुपये की आय हुई: सरकार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से, इसकी शुरुआत से अब तक कुल 34.13 करोड़ रुपये की आय हुई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को राज्यसभा को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम आकाशवाणी मौजूदा संसाधनों के माध्यम से बिना अतिरिक्त खर्च के तैयार करता है। उन्होंने बताया कि 'मन की बात" कार्यक्रम पारंपरिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से श्रोताओं तक पहुंचता है और इसके जरिए अब तक 34.13 करोड़ रुपये की आय हुई है। 'मन की बात" का पहली बार प्रसारण तीन अक्टूबर 2014 को हुआ था।

मतदाता सूची, चुनाव और चुनाव आयोग

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक

स्वतन्त्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग के सामने आकर खड़े हो गये हैं । यह पूरा कार्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। श्री गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं अत: चुनाव आयोग के बारे में कहे गये उनके शब्दों या आरोपों को सामान्य रूप में नहीं लिया जा सकता। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाये हैं वे साधारण नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनका सीधा सम्बन्ध चुनावों की पवित्रता व शुचिता के साथ है। श्री गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पूरे देश में मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ है। अभी तक भारत में जो मांग होती रही है वह चुनाव प्रणाली को सुधारने की होती रही है। इसमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कभी निशाने पर नहीं रही। मगर राहुल गांधी ने सीधे ही आयोग की विश्वसनीयता को सन्देह के घेरे में खड़ा कर दिया है।

सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या मतदाता सूची के स्तर पर ही अशुद्धि को घोल कर पूरी चुनाव प्रणाली को अपवित्र करने का कोई काम चुनाव आयोग द्वारा किया गया है? इसमें एक बात समझने की है कि चुनाव आयोग पूरी तरह एक स्वतन्त्र और स्वायत्तशासी या खुद मुख्तार संस्था है जो सरकार का अंग नहीं है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और कौन सी विपक्ष में बैठी हुई है। चुनाव आयोग सीधे संविधान से शक्ति लेकर अपने काम को अंजाम देता है। आजकल संसद का सावन सत्र (मानसून) चालू है और इसके दोनों सदनों में विपक्ष की तरफ से यह मांग हो रही है कि चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में बहस कराई जाये जिसे सत्तापक्ष यह कह कर नकार रहा है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतन्त्र व निष्पक्ष संस्था के बारे में बहस नहीं कराई जा सकती क्योंकि उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में अपील चल रही है। मगर ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब लोकसभा या राज्यसभा में न्यायालय में लम्बित मामलों पर भी बहस घुमा-फिरा कर हुई है। संसद का सत्र केवल 21 अगस्त तक है और अभी तक संसद में केवल आपरेशन सिन्दूर पर ही लम्बी बहस हुई है। कुछ विधेयक भी सरकार ने विपक्ष के शोर- शराबे के बीच पारित करा लिए हैं। अत: समझा जा सकता है कि विपक्ष इस मसले को सीधे जनता के बीच ले जाने की फिराक में हैं। यदि यह स्थिति आती है और चुनाव आयोग के मुद्दे को विपक्ष संसद से निकाल कर सड़क तक ले जाता है तो सत्ताधारी पार्टी को रक्षात्मक होना पड़ेगा जबकि मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सत्ता पक्ष के लिए भी आगे जाकर मुसीबत का सबब बन सकता है। अत: बहुत साफ है कि सत्ताधारी भाजपा चुनाव आयोग की वकील नहीं बन सकती है। इस मामले में चुनाव आयोग को अपनी पैरवी खुद ही करनी पड़ेगी और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के सन्देह को दूर करना होगा क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं जिनका सम्बन्ध सीधे चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली से जाकर जुड़ता है।

मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1974 में देश मं स्व. जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन चला था तो चुनाव प्रणाली में सुधार का भी एक प्रमुख मुद्दा था। इस आन्दोलन में जनसंघ (भाजपा) भी शामिल थी। उस समय चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे थे। जेपी मांग कर रहे थे कि चुनावों पर बढ़ते धन के प्रभाव को कम किया जाये । इसके लिए उहोंने एक चुनाव सुधार कमेटी भी बनाई थी जिसके प्रमुख बम्बई उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री वी.एम. तारकुंडे थे। इस समिति ने सरकारी खर्च से चुनाव कराये जाने की वकालत तक की थी। मगर इसके बाद देश में 1975 जून में इमरजेंसी लग गई और 1977 में जब चुनाव हुए तो गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई सरकार का गठन हुआ । यह सरकार जनता पार्टी की थी जो सभी प्रमुख दक्षिणपंथी व मध्यमार्गी दलों का विलय करके बनी थी। इस सरकार ने चुनाव सुधारों के लिए एक पृथक आयोग रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस.एल. शकधर के नेतृत्व में बनाया। मगर 1980 में पुन: चुनावों के बाद सरकार बदल गई और श्रीमती इन्दिरा गांधी पुन: सत्ता पर बैठीं। लेकिन अब 2025 चल रहा है और चुनाव सुधारों का मामला न होकर चुनावी घांधली का विषय मुख्य रूप से सामने आया है जिसका कर्ताधर्ता खुद चुनाव आयोग को बताया जा रहा है। विपक्ष इस मसले से सीधे आम जनता को जोड़ना चाहता है। यदि आम जनता इससे जुड़ जाती है तो यह एक जनान्दोलन का स्वरूप ले सकता है क्योंकि आम जनता अपने एक वोट के बारे में बहुत संवेदनशील रहती है।

भारतीय संविधान में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को एक वोट का संवैधानिक अधिकार यह है। इस एक वोट की कीमत बराबर होती है। अर्थात सड़क बनाने वाले मजदूर के एक वोट की भी वही कीमत होती है टाटा या बिड़ला के वोट की होती है। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस वोट को ही चुनाव आयोग ने प्रदूषित कर दिया है और लाखों की संख्या में फर्जी मतदाता खड़े कर दिये हैं जिसका लाभ सत्ताधारी दल को मिलता है। यह आरोप चुनाव आयोग पर है। अत: चुनाव आयोग को इन आरोपों की जांच के लिए आगे कदम उठाना होगा और अपनी विश्वसनीयता व प्रतिष्ठा को बचाना होगा। भारत के चुनाव आयोग की पूरे विश्व के लोकतान्त्रिक देशों में बहुत ऊंची ख्याति है । न जाने कितने देशों ने भारत की चुनाव प्रणाली का अध्यन कर उससे कुछ सीखा है। भारत में चुनाव आयोग को लोकतन्त्र की गंगा का गोमुख माना जाता है। अत: राहुल गांधी जो भी और जितने भी आरोप मतदाता सूची को लेकर लगा रहे हैं उनकी जांच स्वयं चुनाव आयोग को ही करनी होगी । इस काम में सरकार उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को यह सोचना होगा कि उनके आरोप पुख्ता सबूतों पर ही आधारित हों। उनका लक्ष्य राजनीतिक विजय प्राप्त करना न हो बल्कि चुनाव प्रणाली को शुद्ध करना हो क्योंकि चुनाव सुधारों के लिए तो अब विपक्ष भी खुद उत्सुक नहीं बचा है। विपक्ष कह रहा है कि मतदाता सूची के मुद्दे पर वह संसद से लेकर सड़क तक जाम करने की स्थिति में है। चुनाव आयोग विपक्ष को मतदाता सूचियां भी उपलब्ध करा रहा है जबकि राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि उन्हें डिजिटल सूचियां दी जायें। इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि मुख्य आरोप यह है कि एक ही मतदाता कई राज्यों में मतदाता बना हुआ है एक पते पर दर्जनों मतदाताओं के नाम पंजीकृत हैं। मगर राहुल गांधी को भी यह सोचना होगा कि वह इस मामले में किसी प्रकार की शंका में महाराष्ट्र की तरह न रहें ।

महाराष्ट्र में पांच महीने के दौरान बढ़े मतदाताओं की संख्या उन्होंने लोकसभा में 70 लाख बताई जो बाद में घट कर 40 लाख के करीब रह गई । उन्हें यह तो याद रखना होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक व्यवस्था भारत के लोकतन्त्र के लिए बनाई उसमें चुनाव आयोग को इसी लोकतन्त्र का भीष्म पितामह बनाया क्योंकि खुद सरकार से बाहर रह कर आयोग देश में राजनीतिक प्रशासन प्रणाली को देने का काम करता है। ऐसा वह अपने संवैधानिक दायित्व के तहत करता है। वह निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव कराता है और प्रत्येक भारतीय को विश्वास दिलाता है कि उसके एक वोट के माध्यम से ही मुल्क में सरकारों का गठन होगा। वह लोकतन्त्र में आम आदमी की भागीदारी को सुनिश्चित करने का महायन्त्र होता है।

मगर यह भी हकीकत है कि बिहार में तीन महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और यहां चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण सूची तैयार की है। इसमें 65 लाख फर्जी मतदाता हटाये गये हैं तो भी विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। क्या चुनाव आयोग के इस कार्य को कानून सम्मत नहीं माना जाना चाहिए.। यह कैसे संभव है कि चुनाव आयोग एक राज्य में मतदाता बढ़ाये और दूसरे में घटाये तो भी उसे कटघरे में खड़ा किया जाये। भाजपा के इस तर्क में वजन क्यों न माना जाये कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों की सफाई करने के लिए ही पुनरीक्षण करा रहा है जबकि विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है तो मामला इतना सीधा नहीं है।

रूस-भारत-चीन की 'त्रिमूर्ति' निकालेगी ट्रम्प की दादागिरी

अर्जुन चोपड़ा

जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के पूरी दुनिया को टैरिफ बढ़ाने के ऐलान किए जाने और इसे लागू करने के बाद अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं उसका जवाब देना जरूरी है। ट्रम्प का टैरिफ बम भारत पर जिस तरह ब्लास्ट हुआ है, भारत ने उसे करारा जवाब भी दिया है। भारत की अगर रूस से बरसों पुरानी दोस्ती है और वह उससे तेल खरीदता है तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है लेकिन अमेरिका को भारत-रूस दोस्ती पसंद नहीं। उसे भारत का रूस से तेल खरीदना भी नहीं जंचता। तभी तो वह भारत पर टैरिफ बढ़ाने की नई-नई धमकी दे रहा है। दुनिया ट्रम्प की धमकियों का जवाब ढूंढ रही है। तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम के बीच कहा भी जा रहा है कि अगर रूस-इंडिया और चीन (आरआईसी) अगर एक हो जाएं तो सचमुच वाशिंगटन हिल जाएगा। यह ऊपरी तौर पर मजबूत विकल्प दिखाई दे रहा है जो दुनिया में अपना परचम फहरा सकता है लेकिन चीन को लेकर जमीनी दिक्कतें और जटिलताएं ज्यादा हैं। परन्तु यह भी कहा जा रहा है कि भारत और चीन एशिया की वो महाशक्तियां हैं तथा इनका मिलना आज के वैश्विक टकराव के बीच समय की मांग है। यह भी सच है कि भारत और चीन ने पिछले दो वर्षों में रिश्तों में जमी बर्फ को आपसी सहयोग से पिघलने का काम किया है।

भारत और चीनी पर्यटकों को वीजा दिए जाने की पहल, गलवान घाटी में तनाव कम करने के लिए सेनाओं की तैनाती में कटौती के अच्छे परिणाम दिखते हैं। अब दोनों देश सीमा तनाव खत्म कर चुके हैं और उस सम्भावना की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है रूस-इंडिया-चीन गठजोड़। प्रधानमंत्री मोदी एक दूरदर्शी जननायक हैं तथा उनका 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के लिए जाने का ऐलान विश्व के नक्शे पर एक बड़ा मील पत्थर साबित हो सकता है। इस आरआईसी की सम्भावनाओं का जन्मदाता ट्रम्प को ही माना जाना चाहिए, जिसने भारत पर टैरिफ 25 प्रतिशत बढ़ाया तथा फिर अपनी

धमकी पर अमल करते हुए पिछले हफ्ते ही 25 प्रतिशत का और इजाफा करते हुए इसे 50 फीसदी कर दिया। यद्यपि इस दिशा में गतिविधियां और घटनाक्रम शुरू हो चुका है।

रूस भारत-चीन तनाव कम करने और पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने के लिए आरआईसी त्रिगुट को दोबारा खड़ा करने पर जोर दे रहा है। वहीं भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार कर रहा है।

सच यह है कि हाल के वर्षों में वैश्विक भू-राजनीति में तेजी से बदलाव आया है। इस बदलती दुनिया में रूस, भारत और चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय मंच को दोबारा खड़ा करने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में इस मंच को फिर से सक्रिय करने की इच्छा जताई है। लावरोव ने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव में "काफी" कमी आई है और त्रिपक्षीय समूह 'आरआईसी' का रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। मॉस्को में उन्होंने कहा था कि आरआईसी प्रारूप में संयुक्त कार्य की बहाली बहुध्रुवीय ढांचे के निर्माण समेत यूरेशियाई प्रक्रियाओं की दिशा में पहला कदम हो सकता है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

अगर हम तीन दशक पुराने इतिहास में जाएं तो पाते हैं कि रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय मंच की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हुई थी, जब रूस के तत्कालीन विदेश मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने इसे अमेरिका-केंद्रित एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था के खिलाफ एक वैकल्पिक रणनीतिक गठजोड़ के रूप में प्रस्तावित किया था। इस मंच का उद्देश्य तीनों देशों के साझा हितों को बढ़ावा देना और वैश्विक मंच पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। 2000 के दशक में यह मंच ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों के साथ पूरक रूप से काम करता रहा लेकिन यह भी सच है कि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद RIC मंच लगभग निष्क्रिय हो गया। भारत-चीन सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास ने इस त्रिगुट को कमजोर कर दिया। इस बीच, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन के बीच निकटता बढ़ती चली गई।

रूस का मानना है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को शांत करने की दिशा में प्रगति हुई है, और अब आरआईसी मंच को फिर से सक्रिय करने का सही समय है। रूस का मानना है कि आरआईसी का पुनर्जन्म पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा और तीनों देशों को एक स्वतंत्र, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में काम करने का अवसर देगा।

भारत, जो रूस का दशकों पुराना साझेदार है, वह इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संतुलन की भूमिका निभा सकता है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका रूस के लिए आकर्षक है। देखा जाए तो भारत ने वैश्विक भू-राजनीति में अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखी है।

यह सच है कि रूस, भारत और चीन तीनों ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने आन दि रिकार्ड कहा कि, "मुझे वाकई उम्मीद है कि हम 'रूस-भारत-चीन' त्रिपक्षीय समूह के काम को फिर से शुरू कर पाएंगे।

भारत और चीन के बीच संबंधों में हाल के महीनों में कुछ सुधार के संकेत दिखे हैं। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते ने चार साल से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने में मदद की। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में हुई मुलाकात और विदेश मंत्रियों की बार-बार की बैठकों ने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। तथा अब एससीओ में पीएम मोदी बहुत कुछ कर सकते हैं।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी मार्च 2025 में कहा था कि दोनों देशों के बीच सहयोग ही एकमात्र सही विकल्प है। यह रुख उस समय सामने आया जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने वैश्विक भू-राजनीति में अनिश्चितता पैदा की थी। आज की तारीख में ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति भारत और चीन दोनों के लिए आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर रही है तथा इस कारण दोनों देश एक-दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में सोच रहे हैं। देखा जाए तो भारत और चीन के बीच अविश्वास की खाई अभी भी गहरी है। ऑपरेशन सिंदूर (2025) के दौरान पाकिस्तान द्वारा चीनी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने से तनाव को और बढ़ा दिया।

सच तो यह है कि आरआईसी का गठन भारत के प्रति रूस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रूस की इस पहल का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और चीन अपने द्विपक्षीय मुद्दों, खासकर सीमा विवाद, को कितनी प्रभावी ढंग से सुलझा पाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में आरआईसी का गठन दुनिया के लिए और हमारे खुद के लिए अमेरिका को एक करारा जवाब होगा।

क्या राहुल गांधी को आमंत्रित करेगा आरएसएस?

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

राजनीतिक गलियारों में 26 अगस्त से दिल्ली में शुरू हो रहे अपने शताब्दी समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आरएसएस द्वारा आमंत्रित किए जाने की अटकलें तेज़ हैं। ज़ाहिर है, आरएसएस के भीतर एक वर्ग यह संभावना जता रहा है कि राहुल को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इस चर्चा ने राजनीतिक प्रतिष्ठान, खासकर भाजपा, को दो बातों का इंतज़ार और नज़र रखने के लिए प्रेरित किया है। पहला, क्या यह बहुचर्चित निमंत्रण वास्तव में आएगा। दूसरा, अगर निमंत्रण आता है, तो क्या राहुल इसमें शामिल होंगे। शताब्दी समारोह राजधानी में तीन दिनों तक चलेगा और फिर देश भर के अन्य राज्यों में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में, इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दो दिवसीय व्याख्यान शामिल हैं, जो संगठन के इतिहास और भारत के लिए उसके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे। तीसरे दिन प्रमुख व्यक्तियों द्वारा चर्चाओं की एक श्रृंखला होगी।

आरएसएस अपने 100वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का इरादा रखता है। अतिथि सूची में प्रमुख बुद्धिजीवियों, शीर्ष राजनीतिक हस्तियों, भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों, वरिष्ठ संपादकों और प्रसिद्ध अभिनेताओं के नाम शामिल हैं। बेशक, कई धार्मिक नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। इस समारोह में कई कारणों से गहरी दिलचस्पी है, एक तो यह जानने की उत्सुकता कि भागवत आरएसएस के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं। भाजपा के लोग इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। वे भाजपा-आरएसएस के रिश्ते की दिशा का अंदाज़ा लगाने के लिए उनके हाव-भाव पर बहुत बारीकी से नज़र रखेंगे। एक और दिलचस्प बात स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी हैं। वह आरएसएस पर बेहद तीखी भाषा में हमला कर रहे हैं और हिंदू धर्म के बारे में अपने विचार को आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत रख रहे हैं। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, राजनीतिक हलके बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि समारोह के दौरान क्या होता है। अगस्त में काफ़ी उत्साह देखने को मिलेगा।

दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में क्यों हो रही घटनाएं

हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण इसे नई दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका कहा जाता है, लेकिन देश के राजनयिक क्षेत्र चाणक्यपुरी में पिछले कुछ महीनों में दो अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी हैं।

पहली घटना इज़राइल विरोधी पोस्टरों का रहस्यमय ढंग से सामने आना था, जिनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को "वांटेड" व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था। सबसे हालिया घटना चेन स्नैचिंग की थी, जिसमें तमिलनाडु की कांग्रेस सांसद सुधा कृष्णन पर हमला किया और उनके गले से सोने की चेन खींच ली। दोनों ही मामलों में, बदमाशों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि वे दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों, जो इस संवेदनशील क्षेत्र में चौबीसों घंटे गश्त करते हैं, की कथित निगरानी में कैसे उत्पात मचाने में कामयाब रहे। चाणक्यपुरी इलाके में हर गली-नुक्कड़ पर सीसीटीवी लगे हैं। इसीलिए बदमाशों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन दोनों ही घटनाएं दिनदहाड़े हुईं और फिर भी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। चेन स्नैचर के साथ हाथापाई में कांग्रेस सांसद घायल भी हो गईं और चीखने-चिल्लाने लगीं। जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के प्रभारी हैं, से शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर कार्रवाई हुई।

क्या थरूर की राह पर चलेंगे कल्याण बनर्जी?

अब जबकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया गया है, उनके सहयोगी सोच रहे हैं कि क्या वे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तरह ही कदम उठाएंगे, जो पिछले एक साल से भाजपा के साथ सांठगांठ कर रहे हैं और अपनी पार्टी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। थरूर इसलिए निराश हैं क्योंकि वे अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होना चाहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी उनकी बात नहीं मान रही है।

इससे उनके और मीडिया सेल प्रमुख जयराम रमेश के बीच 'एक्स' पर तीखी बहस हुई है। बनर्जी भी भाजपा के करीब जा रहे हैं, जिससे टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज़ हैं। ज़ाहिर है, वे भी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनसे कल्याण बनर्जी की बनती नहीं, को बढ़ावा दिए जाने से अपनी पार्टी में निराश हैं।

अभी तक कल्याण बनर्जी ने थरूर की तरह ट्वीट करना शुरू नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हाल ही में राजधानी में एक रात्रिभोज का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने बंगाल मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। ज़ाहिर है, उन्होंने पूरी शाम अपने दिल की बात रखी।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

CMYK

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

टैरिफ से तनाव

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की तलवार ऐसी खिंची है कि पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। वैश्विक घटनाक्रम बहुत तेज चल रहा है और उसका कुल निचोड़ दो बयानों में देखा जा सकता है। जहां एक ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि अब भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत नहीं होगी, तो वहीं दूसरी ओर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। इसका तीसरा निचोड़ या पहलू यह है कि कुछ अमेरिकी कंपनियों ने अपनी सरकार के अनुरूप कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लग रहा है कि अमेरिकापरस्त कुछ कंपनियां अपने राष्ट्रपति को खुश करने के लिए भारत में अपना काम समेटेंगी। हालांकि, उनकी कोशिश होगी कि उनका व्यापार और मुनाफा बना रहे। कोई शक नहीं कि अमेरिकी टैरिफ की आधिकारिक शुरुआत भले ही 27 अगस्त से हो, पर उसे लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों में जटिलता और तनाव का आलम बना रहेगा।

टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर तत्काल असर तो कम होगा, पर उसकी गूंज बहुत ज्यादा होगी। शोर मचाकर, विवाद खड़े करके या भारत के किसी दुश्मन की पीठ थपथपाकर भारत सरकार के भयादोहन की यह गैर-वाजिब अमेरिकी कवायद निंदनीय है। विशेष रूप से रूस से तेल लेने को बहाना बनाकर भारत पर जो 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है, वह किसी अन्याय से कम नहीं है। ट्रंप ने वार्ता की शुरुआत में भारत को रिझाने के लिए ख्वाब दिखाया था कि भारत-अमेरिका व्यापार 191 अरब डॉलर से बढ़कर 500 अरब डॉलर हो जाएगा। वास्तव में, जिस नीति पर वह काम कर रहे हैं, उससे केवल अमेरिकी व्यवसाय का ही विस्तार होना है। स्वयं अमेरिकी विशेषज्ञ व नेता भी यही मान रहे हैं कि ट्रंप की ऐसी नीति से अमेरिका को घाटे की आशंका है। एक चिंता यह भी है कि अमेरिका एक सहयोगी के रूप में भारत को खुद से दूर कर देगा।

शोर मचाकर, विवाद खड़े करके या हमारे किसी दुश्मन देश की पीठ थपथपाकर भारत सरकार के भयादोहन की यह गैर-वाजिब अमेरिकी कवायद निंदनीय है।

वास्तव में, यही इतिहास है, अमेरिका ने अपनी अनेक एकतरफा स्वार्थी नीतियों से सदा भारत को अपने से दूर ही किया है। भारत की स्वतंत्र आवाज अमेरिका के कानों में पंडित नेहरू की बंद अर्थव्यवस्था के दौर में भी चुभती थी और नरेंद्र मोदी की खुली अर्थव्यवस्था के युग में भी यही हाल है। मित्रता के दावे व संबंध सुधार की तमाम पिछली कोशिशें नाकाम होकर ट्रंप की मनमानी में सिमट गई हैं।

अब सवाल है, आगे रास्ता किधर जाएगा? बीजिंग और मास्को में जो नई सरगर्मी दिख रही है, वह अमेरिका के लिए भी साफ इशारा है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसकी नीतियां अमेरिका तय करने लगे और यही बात चीन भी कह रहा है। रूसी तेल खरीदने में चीन आज भारत से आगे है, लेकिन इसके लिए जुर्माना भारत पर लगा है। ट्रंप की नीतियों का यह कुतर्क दुनिया देख रही है। चीनी अखबार *ग्लोबल टाइम्स* के हवाले से समझें, तो 'ड्रैगन' और 'हाथी' के साथ नाचने से दुनिया में नया अध्याय लिखे जाने की संभावना है। किसी अर्थव्यवस्था में अगर किसी देश की वजह से कहीं शून्य पैदा होता है, तो उसे कोई दूसरा देश भरता है। भारत भी अपने यहां पैदा शून्य को आसानी से भर लेगा, पर अफसोस की बात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो रही है कि सबसे पुराने लोकतंत्र ने अपने स्वार्थ के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अन्याय करके दुनिया को हंसने का मौका दिया। यह बात अमेरिका में ज्यादातर नेता समझ रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप न जाने कब समझेंगे?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 09 अगस्त, 1950

दिल्ली समझौते की कसौटी

दिल्ली-समझौते अर्थात नेहरू-लियाकत समझौते को भारतीय संसद में अब तक की घटनाओं की रोशनी में एक बार फिर कसौटी पर परखा गया। समझौते के संबंध में शुरू से ही देश में दो दृष्टिकोण पाये जाते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं और जिनके किसी एक बिन्दु पर मिलने की कोई संभावना नहीं है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के संबंध में पहले से एक धारणा बना ली है। वह यह कि पाकिस्तान के शासक पाकिस्तान को थियोक्रेटिक अर्थात मजहबी राज्य बनाना चाहते हैं और उसमें इस्लाम के अनुयायियों के अलावा अन्य धर्मावलम्बियों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उनकी यह धारणा इस आधार पर पुष्ट हुई कि पश्चिमी पाकिस्तान से हिन्दू और सिख अल्पसंख्यकों को सर्वथा चले आना पड़ा। कुछ समय बाद जब पूर्वी पाकिस्तान में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं कि वहां से हिन्दू अल्पसंख्यकों का बड़ी तादाद में भारत आना शुरू हुआ तो यह ख्याल बनना स्वाभाविक था कि पाकिस्तान को निखालिस मजहबी राज्य बनाने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। पाकिस्तान की नेक नीयती पर से लोगों का विश्वास हिल गया और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके जैसे विचार के लोग यह मान बैठे कि पाकिस्तान के साथ किया गया कोई समझौता सफल नहीं हो सकता। इसलिए वे इस विचार के ही विरुद्ध हो गये कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई समझौता किया जाये। और जब नेहरू-लियाकत समझौता हुआ तो इन लोगों ने शुरू दिन से ही वह घोषणा करना प्रारंभ कर दिया कि वह विफल होगा। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, तैसे-तैसे इसी पूर्व मान्यता को जोश के साथ दुहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नेहरू-लियाकत समझौता विफल हो चुका है और बंगाल में अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए अन्य उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए।

इस संबंध में देखना यह है कि क्या सचमुच दिल्ली-समझौता विफल हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर केवल भावावेश में अथवा पूर्व मान्यताओं के आधार पर दिया जायेगा तो हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पायेंगे। हमको सारी परिस्थिति पर संतुलित दृष्टि से और तटस्थ वृत्ति से विचार करना होगा।

जहां एक ओर, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरी मुखरता से मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। विपक्ष चुनाव आयोग को गलत ठहरा रहा है, तो सत्ता पक्ष एक तरह से उसके बचाव में उतर आया है। सुधार या शिकायत दूर होने की उम्मीद में बैठी जनता पक्ष और विपक्ष की तल्ख दलीलों को ध्यान से सुन रही है...

आमने-सामने

चुनावी तंत्र की खामियों पर हमारे सवाल वाजिब

यहां स्कैन करें

पवन खेड़ा | चेयरमैन, मीडिया ऐंड पब्लिसिटी, कांग्रेस

- हमने चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल की मिलीभगत को बेनकाब कर दिया।
- आदित्य श्रीवास्तव का नाम और वोट तीन राज्यों की सूचियों में मिला।
- सुबूत पेश करने के बाद अब जिम्मेदारी आयोग की है, वह सच सामने लाए।

इस सप्ताह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग और केंद्र में सत्तारूढ़ दल की मिलीभगत को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार सुबूतों के साथ बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम का मतदाता सूची से 5 अलग-अलग तरीकों का विश्लेषण रखते हुए बताया कि कैसे सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की चोरी हुई। जरा सोचिए, जब एक विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो पूरे देश में हुए चुनावों में घोटाले का स्तर क्या रहा होगा! यह मामला केवल एक सीट का नहीं है, बल्कि यह पूरे चुनावी तंत्र की साख पर सवाल उठाता है।

कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखकर मतदाता सूचियों की पारदर्शी जांच, डिजिटल रोल और सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। मगर हर बार आयोग ने इन सवालों से बचने का रास्ता चुना। उल्टा, नियम बदलकर सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच सीमित कर दी और डिजिटल मतदाता सूची देने से साफ इनकार कर दिया। जिस जांच का दायित्व और कर्तव्य चुनाव आयोग का था, उसे आखिरकार कांग्रेस को खुद अपने संसाधनों और मेहनत से करना पड़ा। कांग्रेस ने लाखों प्रविष्टियों को एक-एक करके मैनुअल तरीके से जांचा, जबकि चुनाव आयोग के लिए यह काम डिजिटल डाटाबेस से बड़ी आसानी से पूरा करना संभव था, बशर्ते चुनाव आयोग ऐसा चाहता।

इस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे लोकतंत्र के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर पाए गए। जैसे, गुरकीरत सिंह डांग का नाम चार अलग-अलग बूथों पर दर्ज था। महिपाल सिंह के दो वोट महादेवपुरा में और एक वोट वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दर्ज पाए गए। आदित्य श्रीवास्तव का नाम और वोट तीन राज्यों; कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सूचियों में मिला। यह कोई साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित तरीके से किया गया चुनावी अपराध है, जिसमें एक ही व्यक्ति को कई जगह वोट डालने का अवसर मिला।

मतदाता सूचियों में लगभग 40,000 वोटरों के पते या तो पूरी तरह फर्जी थे, या '0' और '#' जैसे चिह्नों में लिखे गए थे। जब पते ही मौजूद नहीं हैं, तो साफ है कि ये नाम अवैध वोटिंग के लिए जोड़े गए थे। यही नहीं, एक ही पते पर दर्ज असंभव संख्या में मतदाताओं के मामले मिले, कहीं 80 लोग एक छोटे से मकान में पंजीकृत थे, तो कहीं 68 लोग एक शराबघर '153 बियर क्लब' में मतदाता के रूप में दर्ज थे। चुनावी प्रक्रिया के साथ इतना बड़ा मजाक चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

फर्जी वोटिंग को आसान बनाने के लिए मतदाता सूचियों में हजारों फोटो इतने छोटे या धुंधले रखे गए थे कि पहचानना असंभव था। जब बूथ पर पहचान सत्यापित ही नहीं हो सकती, तो कोई भी इन नामों से वोट डाल सकता है। सबसे खतरनाक खुलासा फॉर्म-6 के दुरुपयोग का सामने आया, जो नए और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए बनाया गया था। महादेवपुरा में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल फर्जी पंजीकरण और डबल वोटिंग के लिए किया गया। इसमें एक चौंकाने वाला उदाहरण है शकुन रानी, एक 70 वर्षीय महिला का नाम केवल दो महीने के अंतराल में दो बार पंजीकृत किया गया। दोनों बार फोटो और नाम में मामूली बदलाव किया गया और दोनों बार उन्होंने वोट भी डाले। यही वह कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया, ताकि इन घटनाओं के दृश्य प्रमाण कभी सामने न आ सकें।

यह केवल महादेवपुरा की कहानी नहीं है। राहुल गांधी ने उदाहरण के साथ चेताया कि कैसे कुछ हजार वोट पूरे चुनावी परिणाम को बदल सकते हैं। हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस बस आठ सीटों से हारी और इन आठों सीटों पर भी कुल वोट अंतर मात्र 22,779 वोटों का था, जबकि कुल मतदाता संख्या दो करोड़ थी। इसी तरह, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें 33,000 से कम वोटों के अंतर से जीती। यानी सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ 25 सीटें 'चुरानी' थीं, और यही कारण है कि चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूचियां देने से बच रहा है। यह बात जगजाहिर है कि अगर सिर्फ ये 25 सीटें भाजपा हार जाती, तो इस बार उसकी सरकार बनना तो दूर, सपना देखना भी मुमकिन नहीं था।

इन सभी तथ्यों के बावजूद भाजपा व चुनाव आयोग, दोनों ही चुप हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है, सुबूत पेश करने के बाद अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वह सच्चाई सामने लाए, न कि उनकी, जिन्होंने न केवल ठोस आंकड़े दिए, बल्कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा चुनाव आयोग की वेबसाइट से इसकी पुष्टि भी करवाई। कांग्रेस की मांग साफ है कि मशीन-रीडेबल मतदाता सूचियां और सभी पोलिंग स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता की न्यूनतम शर्त है, जिसे चुनाव आयोग तोड़ रहा है।

यह घोटाला केवल वोटों का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के भरोसे का है। जब जनता को यह भरोसा ही न रहे कि उसका डाला गया वोट सही तरीके से गिना जाएगा, तब पूरी चुनावी प्रक्रिया बेमानी हो जाती है। राहुल गांधी का यह खुलासा भारतीय राजनीति में एक तूफान बनकर आया है। तूफान की फितरत ही होती है कि वह यथास्थिति को बदल देता है। मौजूदा सरकार यदि यह सोचती है कि वह सांविधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके और चुनावी प्रक्रिया में हेर-फेर करके लोकतंत्र को हमेशा के लिए कमजोर कर देगी, तो उसे इस देश और कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। मनगढ़ंत मनोहर कहानियों से अंध भक्तों को बहलाना एक बात है, पर असल इतिहास से सही सबक लेना और उसके आधार पर शासन करना अलग। भारतीय लोकतंत्र की नींव में यह लड़ाई एक चुनाव की नहीं, बल्कि जनता के मत के मूल्य व संविधान की आत्मा की रक्षा की है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

चुनाव आयोग पर फर्जी आरोपों का सुतली बम

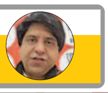

यहां स्कैन करें

शहजाद पूनावाला | राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

- आवाज और शोर खूब हुआ, निकला कुछ नहीं। दावे बड़े, दर्शन छोटे।
- आदित्य श्रीवास्तव का नाम कर्नाटक में मिला, यूपी और महाराष्ट्र में नहीं।
- राहुल गांधी के ज्यादातर दावे न्यायिक पटल पर टिक नहीं पाते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पावरपॉइंट प्रेसवार्ता का अगर सही मूल्यांकन किया जाए, तो यह एटम बम कम और सुतली बम ज्यादा थी। आवाज और शोर तो खूब हुआ, पर निकला कुछ नहीं। दावे बड़े, दर्शन छोटे। वैसे सुप्रीम कोर्ट की हाल की टिप्पणियों के बाद, जिसमें कोर्ट ने राहुल को सेना विरोधी बयानों के लिए जमकर फटकारा था, उनकी विश्वसनीयता वैसे भी न्यूनतम स्तर पर है। राफेल, पेगासस, वीर सावरकर, आरएसएस पर अपने दिए गए बयानों के चलते पहले भी कोर्ट से उनको फटकार मिल चुकी है, पर आधुनिक राजनीति के इन नेता की झूठ की दुकान में सामान खत्म होने का नाम ही नहीं लेता!

सेना पर अनर्गल बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस के बयान बहादुर ने चुनाव आयोग पर, जो एक सांविधानिक संस्था है, निशाना साधा है। 7 अगस्त, 2025 को राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दावा किया कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों में हेरफेर के लिए भाजपा के साथ सांठगांठ की। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,00,250 से अधिक फर्जी वोटों के सुबूत का हवाला दिया, जिसमें नकली मतदाता, फर्जी पते और अमान्य फोटो शामिल हैं। कांग्रेस नेता ने इसे आपराधिक धोखाधड़ी करार दिया है।

हैरानी की बात है, किन नेताओं ने राहुल जी को इस विषय पर ट्यूशन दी? क्या उन्होंने जाने-अनजाने में कांग्रेस नेता से फर्जी मतदाता की बात करवाकर एक प्रकार से बिहार में हो रहे गहन पुनरीक्षण को परोक्ष रूप से समर्थन ही दे दिया? यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची से गड़बड़, अयोग्य और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए ही बिहार में पूरी कवायद चल रही है। उसे लेकर राहुल जी के मित्र- परिवारवाद के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव मोर्चा खोले हुए हैं और यहां परिवारवाद के प्रथम प्रतिनिधि पुष्टि कर रहे हैं कि पुनरीक्षण जरूरी क्यों है। मुझे तो लगा कि कहीं राहुल जी तेजस्वी के दो वोटर कार्ड के विषय को ही न उठा लें, जिस रफ्तार से वह 'एटॉमिक' खुलासे कर रहे थे। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा कि एक नेताजी के दो वोटर कार्ड हैं और उन्होंने एक कार्ड पटना की प्रेस वार्ता में दिखाया था और अब चुनाव आयोग के तलब करने पर जवाब देते नहीं बन रहा है।

प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर का एपिक नंबर पेश करते हुए दावा किया कि यह शख्स कर्नाटक के अलावा लखनऊ में भी वोटर है। यही नहीं, उन्होंने उसे महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची में दर्ज दिखाया। कई न्यूज चैनल ने जब इसका फैक्ट चेक किया, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 'वोटर सर्च' पोर्टल के जरिये सत्यापन और जांच में जो नतीजे सामने आए, वे राहुल गांधी के दावे से मेल नहीं खाते हैं। कर्नाटक की वोटर लिस्ट में 'आदित्य श्रीवास्तव' नाम का एक व्यक्ति दर्ज है, लेकिन लखनऊ और महाराष्ट्र, दोनों स्थानों पर जब उसी नाम और एपिक नंबर से खोज की, तो 'नो रिजल्ट फाउंड' दिखाया। साफ है कि आदित्य श्रीवास्तव फिलहाल लखनऊ का वोटर नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, उसका नाम महाराष्ट्र के किसी मतदाता सूची में भी नहीं है।

कुल मिलाकर, आधे घंटे के भीतर ही राहुल जी का एटम बम फर्जी आरोपों का सुतली बम बन गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने तुरंत राहुल गांधी से उनके दावों को हलफनामे सहित जमा करने का अनुरोध किया, ताकि शिकायत पर न्याय संगत कार्रवाई कर सकें, लेकिन जैसे ही यह किया गया, राहुल गांधी पीछे हट गए और कहा कि उनका शब्द ही शपथ की तरह है। अपनी विश्वसनीयता के लिए राहुल गांधी को निर्वाचन नियमावली- 1960 के नियम के तहत मतदाता सूची में कथित अयोग्य मतदाताओं के नाम घोषणा/शपथ के साथ जमा करने चाहिए। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है और वह केवल सियासी नाटक कर रहे हैं। वह तथ्यों को धुंधला कर रहे हैं, लोगों के मन में चुनाव आयोग के प्रति संदेह पैदा कर रहे हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार सांविधानिक संस्था की छवि को धूमिल कर रहे हैं। यह केवल 'हिट ऐंड रन' था और कुछ नहीं!

वैसे राहुल गांधी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। उनके ज्यादातर दावे - पेगासस, राफेल, हिंडनबर्ग कोर्ट या न्यायिक पटल पर टिक नहीं पाते हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ से राहुल जी ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग आंकड़े दिए हैं। कभी कहा कि एक करोड़ नए वोटर जुड़े हैं, तो कभी 70 लाख, तो कभी 40 लाख। हरियाणा में भी चुनाव आयोग को जब हार के लिए दोष दिया, तो उन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि हार का कारण कांग्रेस खुद थी, न कि चुनाव आयोग। वैसे लोग जानते हैं, हर चुनाव में कांग्रेस ईवीएम को दोष देती रही है। अनेक बार यह बात सामने आ चुकी है कि ईवीएम से फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता, तो विपक्षी नेताओं ने ईवीएम छोड़कर अब नया शिगूफा शुरू किया है।

प्रेस वार्ता समाप्त होते-होते राहुल जी ने चुनाव आयोग को धमकी भी दे दी। कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब स्पष्ट है, यह ईसीआई नहीं, ईएमआई का मामला है- इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा। इंदिरा जी को लगता था 'इंदिरा इज इंडिया' और राहुल जी को लगता है कि उनका परिवारतंत्र -संविधान और लोकतंत्र से ऊपर है! जब चुनाव जीत जाते हैं, तो उनको चुनाव आयोग निष्पक्ष नजर आता है और जब हारने लगते हैं, तो चुनाव आयोग पर निशाना साध लेते हैं। यह संविधानिक संस्थाओं के प्रति चयनात्मक रवैया है।

यह बड़ी त्रासद विडंबना है कि देश को कभी नवीन चावला और एमएस गिल जैसे चुनाव आयुक्त देने वाली कांग्रेस अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बार-बार सवाल उठाती है?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

मनसा वाचा कर्मणा

श्रद्धा का सिक्का

सूफी संत शफीक ने एक बार अपने शिष्यों से बात करते हुए कहा, 'परमात्मा पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है। एक बार मैं सिर्फ एक पैसा साथ लेकर तीर्थयात्रा पर निकल गया। यात्रा लंबी थी, लेकिन सब कार्य सकुशल पूर्ण हुआ और मैं वापस लौट भी आया और वह पैसा मेरे पास ही रहा, बल्कि आज भी मेरे पास है।'

शफीक की बातें सुनकर चकित शिष्य एक-दूसरे से चर्चा करने लगे। उनकी आंखों में अपने गुरु के प्रति अगाध प्रेम और दिल में प्रशंसा के दीये जलने लगे। यह देखकर शफीक अचानक उदास हो गए और उनकी आंखें अनायास डबडबा उठीं। वह खामोश थे। लेकिन, तभी शिष्यों की भीड़ से एक नवयुवक उठा और उसने शफीक से कहा, 'माफी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आपने साथ में एक पैसा ले ही लिया था, तब आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपकी श्रद्धा पैसे पर नहीं, परमात्मा पर थी?'

शफीक का उदास चेहरा खिल उठा, आंसू खुशी के फूलों में बदल गए। उन्होंने उस शिष्य की ओर मुखातिब होते हुए कहा- 'मेरे प्यारे बच्चे! तुम ठीक कहते हो। जब परमात्मा पर भरोसा हो, तो एक पैसा भी असंगत है। और एक पैसे पर भरोसा है, तो प्रभु पर भरोसा नहीं है। मैंने यह कहानी तुम सबकी परीक्षा के लिए ही कही थी। मेरे पास जो पैसा था, वह श्रद्धा का ही सिक्का था। इसलिए वह कभी खर्च न हो सका।'

संदेह के साम्राज्य जीवन की यात्रा में खर्च हो जाते हैं और श्रद्धा का एक पैसा भी बच जाता है। श्रद्धा जिनके पास नहीं, वे सदा भिखारी हैं। और श्रद्धा जिनके पास है, उनके पास तो प्रभु का ही खजाना है- अनादि और अनंत।

ओशो

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

रक्षाबंधन केवल त्योहार नहीं, बल्कि कारीगरों और छोटे उद्यमियों के परिश्रम को सम्मान देने का संकल्प भी है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं, तब 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार करने की दिशा में अहम योगदान देते हैं।

अनुलोम-विलोम

पुस्तक-प्रेम

बदलते युग में किताबों का बढ़ता महत्व

हर वर्ष 9 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तक प्रेमी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों के लिए समर्पित है, जिन्हें पढ़ने से प्रेम है, जिनके लिए पुस्तकें सिर्फ ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और मानसिक यात्रा की दिशा होती हैं। लेकिन आज के समय में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में अभी भी 'पुस्तक प्रेमी' समाज रह गए हैं?

कुछ दशक पहले तक पुस्तकें ज्ञान, मनोरंजन और जीवन मूल्यों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थीं। घर में एक छोटी-सी लाइब्रेरी होना गर्व की बात होती थी। जो लोग पुस्तकें खरीद नहीं पाते थे, वे नगर पालिकाओं या संस्थागत पुस्तकालयों का सहारा लेते थे। वहां एक अकाउंट खुलता था, किताबें इश्यू होती थीं, और पढ़कर वापस कर दी जाती थीं। यह एक संस्कार था, ज्ञान साझा करने का संस्कार। मगर डिजिटल युग के आगमन के बाद यह परंपरा धीरे-धीरे सिमटती चली गई। आज स्मार्टफोन, टैबलेट और इंटरनेट ने न सिर्फ पुस्तकों की जगह ले ली है, बल्कि लोगों की एकाग्रता, धैर्य और अध्ययनशीलता को भी प्रभावित किया है। कई ऐतिहासिक और प्रमुख पुस्तकालयों पर ताले लग चुके हैं या अवैध कब्जे हो चुके हैं। युवाओं की एक पूरी पीढ़ी इन अनुभवों से अनभिज्ञ है। वे 'रील्स' में जीवन तलाशते हैं और 'मैसेज' में भावनाएं।

हालांकि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लेखन को लोकतांत्रिक रूप दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, पोस्ट कर सकता है, साझा कर सकता है। इससे अनेक नए लेखक और विचारक सामने आए हैं, जो समाज के जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डिजिटल लेखन पारंपरिक साहित्यिक लेखन की गहराई, संवेदना और शोध की बराबरी कर सकता है? इसके साथ ही अब लेखन की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी प्रवेश कर लिया है। यह लेखन को न केवल सरल बनाता है, बल्कि रचनात्मकता को एक नई दिशा भी देता है। पर जब सब कुछ 'तुरंत' मिलने लगता है, जैसे गूगल से आंकड़े, संदर्भ, उद्धरण, तो गंभीर और गहन चिंतन की आवश्यकता लोग कम महसूस करते हैं। यही कारण है कि आज के लेखन में सतहीपन मिलता है।

इस बदलते परिदृश्य में यह जरूरी हो गया है कि हम पुस्तक प्रेम को फिर से पुनर्जीवित करें। बच्चों को लाइब्रेरी का संस्कार दें, युवाओं को डिजिटल लेखन के साथ-साथ परंपरागत साहित्यिक रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पुस्तकों का संसार केवल जानकारी नहीं देता, वह दृष्टिकोण भी गढ़ता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

ज्ञान के लिए पुस्तकें अब जरूरी नहीं

ज्ञान किताबों से नहीं मिलता है। आखिर कबीरदास को क्यों कहना पड़ा, *पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।* इस दोहे का अर्थ है कि मोटे-मोटे ग्रंथों को पढ़ते हुए संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान नहीं हो सके। कबीरदास कहते हैं कि, यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही सही तरीके से पढ़ ले, तो वह प्यार का सही रूप पहचान लेता है और वही सच्चा ज्ञानी होता है। पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, लेकिन ज्ञान के लिए आपको चहुंओर देखना होगा। संसार में चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान पसरा है।

संसार में ज्ञान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफलता की कुंजी को प्राप्त कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए वे किताबों में ही डूबे रहते हैं। किताबों से ज्ञान तो अर्जित की जा सकती है, लेकिन यह काफी हद तक सीमित ज्ञान होगा। सफलता के लिए जरूरी है सूचनाओं को इकट्ठा करना। संसार में चहुंओर सूचनाओं का अंबार है। इसलिए पुस्तक से निकलकर संसार में अपने आस-पास भी देखिए और ज्ञान इकट्ठा कीजिए।

ऐसा देखा गया है कि ऊंची- ऊंची डिग्री धारण करने के बाद भी लोग व्यावहारिक जीवन में बहुत ही असफल होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि अपने इस किताबी ज्ञान को किस तरह से जीवन में उतारें और उपयोग करें। आचार्य विनोबा भावे ने ऐसी स्थिति को 'हनुमान कूद' की संज्ञा दी है। इसलिए जरूरी है कि किताबी ज्ञान के साथ ही मानवीय और व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल किया जाए। यह हमें पुस्तकों से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार से, आसपास के परिवेश और अनुभव से प्राप्त होता है।

कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर सूचनाओं को कैसे इकट्ठा किया जाए? हर किसी के लिए सफलता पाने का अलग-अलग मापदंड होता है। लोग अलग-अलग क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या आपका जो भी लक्ष्य है, उससे संबंधित लोगों से बातचीत कीजिए। अपने गुरुजनों, परिवार वालों, सफल व्यक्तियों और आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, सूचनाओं का सबसे अच्छा साधन है संवाद। संवाद के जरिये ही आप संसार की तमाम सूचनाओं को इकट्ठा कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए कबीरदास भी अपने दोहे के जरिये यह समझाते हैं कि किताबों में डूबे रहने से ज्ञान का अंकुर कभी नहीं फूट सकेगा। बल्कि प्रेम के अनुभव से ही व्यक्ति ज्ञान के शिखर को छू सकता है।

वेदांत कृष्ण, ब्लॉगर

संपादकीय जागरण

(12) शनिवार, 9 अगस्त, 2025 : श्रावण शुक्ल पूर्णिमा वि. 2082

विपत्ति में हार तभी होती है जब मनुष्य उससे डरता है

हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट

उच्चतर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के लिए यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश को आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोकती है और फिर जब वहां के 13 जज इसका प्रतिवाद करते हैं तो वह अपना फैसला वापस ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार के खिलाफ दिए गए अपने आदेश को वापस लेते हुए यह कहा कि उसका इरादा उन्हें शर्मिंदा करने का नहीं था, लेकिन फैसले के वक्त जैसी टिप्पणियां की गई थीं, वे तो उनकी योग्यता और निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाली थीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि ऐसा खराब और त्रुटिपूर्ण फैसला नहीं देखा? प्रश्न यह है कि अब वह कथित खराब फैसला खराब क्यों नहीं रहा? यह सामान्य बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर अपनी आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट के 13 न्यायाधीश अपने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखें। यह ठीक है कि इस पत्र का संज्ञान लिया गया और उसके बाद चर्चा एवं विवाद का विषय बना सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस हो गया, लेकिन क्या इसी के साथ मामले का पटाक्षेप हो गया? शायद नहीं। जो भी हो, इस सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करते हुए जो टिप्पणियां करते हैं, वे कई बार उनके फैसलों का हिस्सा क्यों नहीं बनतीं? कई बार किसी मामले की सुनवाई के दौरान की गईं तीखी टिप्पणियां कुछ और संदेश देती हैं और फैसला कुछ और कह रहा होता है। इससे भी बड़ी विडंबना यह कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गईं मौखिक टिप्पणियों को नजीर की तरह लिया जाता है। आखिर जो टिप्पणी फैसले का हिस्सा नहीं, उसे महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि ऐसी टिप्पणी होनी ही क्यों चाहिए? अच्छा यह होगा कि इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसी टिप्पणियां विवाद और अनावश्यक बहस का विषय बनती हैं। यह शुभ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिका की विसंगतियों को रेखांकित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कई विषयों पर दो टूक ढंग से अपनी बात कही है। उनसे यही अपेक्षित है कि वे विसंगतियों को रेखांकित करने तक ही सीमित न रहें, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए भी सक्रिय हों। उनकी सक्रियता के दायरे में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की विवादास्पद कोलेजियम व्यवस्था भी आनी चाहिए और महाभियोग की जटिल एवं लंबी प्रक्रिया भी। इसी जटिलता के कारण आज तक किसी जज के खिलाफ महाभियोग पारित नहीं हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही नहीं थे।

पोल खुली और बंद भी हुई

पोल खुलना मुहावरा है। अप्रकट भेद या रहस्य खुलने के मामले में इसका प्रयोग होता है। अगर दिमाग पर जोर दें तो हर साल वर्षा के समय इस शीर्षक से या इससे मिलते-जुलते शीर्षक से खबर छपती रही है-पहली वर्षा में ही नगर निगम की पोल खुली। जहां नगर निगम नहीं है, वहां यह शीर्षक नगरपालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत के नाम पर लगाया जाता था। यानी कोई भी निकाय हो, बरसात में उसकी पोल खुल ही जानी है। राजधानी में इस सप्ताह हुई वर्षा में एक बार फिर पटना नगर निगम और नगर विकास विभाग की पोल खुली। लेकिन, पिछले कई वर्षों के उलट इस बार तुरंत यह बंद भी हो गई। हर बार लंबे समय तक जल जमाव के लिए अगर नगर निगम और उससे संबद्ध इकाइयों की आलोचना होती रही है तो इस बार प्रशंसा भी होनी चाहिए। नागरिकों को बहुत कम समय में ही भारी संकट से उबार लिया। इसका मतलब है कि तंत्र सक्षम है। उसके पास साधन है। केवल तत्परता की कमी के कारण इससे पहले ऐसा नहीं हो पाता था। प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को भी जल जमाव के कारणों का पता चल गया है। जरूरत इस बात की है कि इस बार के जल जमाव और निकासी के अनुभवों का उपयोग इसके स्थायी समाधान के लिए किया जाए।

> जरूरत इस बात की है कि इस बार के जल जमाव और निकासी के अनुभवों का उपयोग इसके स्थायी समाधान के लिए हो

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या भारत को भी अमेरिका से आने वाली वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए?

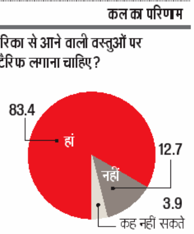

आज का सवाल

क्या राहुल गांधी द्वारा शपथपत्र देने से इन्कार करने पर चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

खतरनाक पड़ोसी है बांग्लादेश

प्रकाश सिंह

बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान से बढ़ती हुई नजदीकियां भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती बनने जा रही है

अवधेश राजपूत

आज से करीब एक वर्ष पहले पांच अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलटा गया। छात्र आंदोलन की आंधी में शेख हसीना भाग कर भारत की शरण में आ गईं और अमेरिका के प्रभाव से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जबरन सत्ता परिवर्तन में जमाते इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, हिजबुत तहरीर, हिफाजते इस्लाम जैसे इस्लामिक संगठनों का भी हाथ रहा। यूनुस सरकार ने जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर लगे प्रतिबंध हटा लिए और अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया। जेल में बंद हजारों जिहादियों को छोड़ दिया गया। कई शहरों में 'इस्लामिक स्टेट' के झंडे फहराने लगे। अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी के विरुद्ध सारे आरोप वापस ले लिए गए। रहमानी ने एक वायरल हुए वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवाहन किया कि वे मोदी के शासन से बंगाल को मुक्त कर अपनी स्वतंत्रता घोषित करें। एक कट्टरपंथी नेता सैयद मोहम्मद करीम ने बांग्लादेश में शरिया लागू करने की मांग करते हुए कहा कि देश में तालिबान जैसी हुकूमत होनी चाहिए।

जब 26 सितंबर, 2024 को मोहम्मद यूनुस संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे, तब उनके सम्मान में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव ने एक समारोह का आयोजन किया था। इसमें बिल क्लिंटन ने हिजबुत तहरीर के नेता महफूज आलम की बांग्लादेश में आंदोलन चलाने के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। हिजबूत एक कट्टर इस्लामी संगठन है, जो संसार भर में खलीफा का साम्राज्य चाहता है। यह संगठन इंग्लैंड, अमेरिका और कई अन्य देशों में प्रतिबंधित है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम वहां के अल्पसंख्यकों, विशेष तौर से हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। हत्या, अपहरण, दुष्कर्म के साथ मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएं आम हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच अल्पसंख्यकों के विरुद्ध 2,442 हिंसात्मक घटनाएं हुईं। यूनुस सरकार को अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके प्रमुख नेता बराक ओबामा, बिल एवं हिलेरी क्लिंटन आदि का पूरा समर्थन है। इस कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वाच जैसी संस्थाओं ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया और कोई रिपोर्ट नहीं छापी। जिन चंद पत्रकारों ने इन घटनाओं पर अपनी आवाज उठाई, वे गिरफ्तार कर लिए गए और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे चलाए गए। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस के अनुसार अभी तक 878 पत्रकारों को निशाना बनाया जा चुका है। बांग्लादेश में नया आतंक विरोधी कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। बांग्लादेश में सिक्योरिटी आर्डिनेंस भी पास किया गया है। इसका इस्तेमाल सरकार अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज को दबाने के लिए कर रही है।

चूंकि यूनुस को योग्य अर्थशास्त्री होने के नाते नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए लोगों को बहुत आशा थी कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश आर्थिक प्रगति करेगा, परंतु उसकी आर्थिक हालत खस्ता होती जा रही है। जो महंगाई सितंबर 2024 में 9.92 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 10.87 प्रतिशत हो गई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुश्किल से चार प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। विदेश से होने वाले निवेश गिरते जा रहे। कपड़ा उद्योग, जो देश की आर्थिकी का आधार था, संकट में चल रहा है। 69 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और 76,500 कर्मी बेकार हो गए हैं।

शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में बराबर सुधार होता रहा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के भारत विरोधी संगठनों के सदस्यों को पहले बांग्लादेश में शरण मिल जाती थी और वे असम, नगालैंड, मणिपुर आदि में हिंसात्मक कार्रवाई करते थे। यह सब शेख हसीना ने बंद कर दिया, परंतु अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार का भारत से फासला धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यूनुस सरकार का कट्टरपंथियों से गठजोड़ है। कुछ समय पहले चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक बैठक भी हुई, जिसका उद्देश्य भारत को अलग-थलग करना था। मोहम्मद यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक जाल फैलाने का न्योता दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सातों उत्तर-पूर्वी राज्यों की समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है। ऐसे में चीन को बांग्लादेश में अच्छा बाजार मिलेगा।

चुनाव को लेकर बांग्लादेश में आंतरिक मतभेद हो गए हैं। चूंकि मोहम्मद यूनुस को सत्ता का आनंद मिल रहा है, इसलिए वह अप्रैल 2026 के पहले चुनाव नहीं करना चाहते। आर्मी प्रमुख जनरल वकार ने कहा है कि चुनाव दिसंबर 2025 तक हो जाने चाहिए। इसके बाद भी अनिश्चितता बनी हुई है। वहां चुनाव के बाद जो सरकार बने भारत को उसका रवैया देखना पड़ेगा। यदि बांग्लादेश की नई सरकार भारत विरोधी रहती है तो हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारत में कम से कम दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हमें यह कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश इन्हें या तो वापस ले या इन्हें बसाने के लिए हमें आवश्यक भूमि हस्तांतरित करे। यह भूमि हम रंगपुर डिवीजन में मांगें और यदि बांग्लादेश नहीं दे तो उसे जबरदस्ती हासिल करने के लिए कदम उठाए जाएं। अगर हम इसमें सफल हो गए तो सिलीगुड़ी गलियारा में 'चिकन नेक' की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड मांग सकते हैं और चीन ताइवान पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर सकता है तो हम बांग्लादेश से कुछ जमीन उन्हीं के नागरिकों को बसाने के लिए मांग सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक है। आज वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला है। इससे अल्पसंख्यक भयभीत जिंदगी बिता रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजदीकियां भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती बनने जा रही हैं। भारत को चीन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश से भी सावधान रहना होगा।

(लेखक सीमा सुरक्षा बल एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे हैं)
response@jagran.com

बदलाव की तेज लहर लाई एआइ

जसप्रीत बिंद्रा

भारत के पास एआइ अपनाकर आउटसोर्सिंग अर्थव्यवस्था से ज्ञान महाशक्ति बनने का मौका है

गोवा में एआइ मिशन-2027 में भागीदारी करते युवा • प्रेट्र

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआइ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह हमारे जीने, काम करने, सीखने और सोचने के तरीके को तेजी से बदल रही है। हमारे स्मार्टफोन में वायस असिस्टेंट से लेकर कंपनियों के निर्णयों तक, एआइ हर जगह मौजूद है। जैसे-जैसे भारत एआइ-संचालित अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, यह जरूरी हो गया है कि हम मशीनी कौशल यानी एआइ को समझें। आज एआइ की शक्ति कृषि से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर वित्त तक हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है। भारत में किसान अब एआइ आधारित सेंसर और ड्रोन के जरिए फसल की निगरानी और सिंचाई का प्रबंधन कर रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ा है और संसाधनों की बर्बादी घटी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआइ अब कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों की पहचान पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक तरीके से कर पा रही है। भारतीय स्टार्टअप दूरदराज इलाकों में एआइ की मदद से एक्स-रे और एमआरआइ की व्याख्या कर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा रहे हैं। फाइनेंस, रिटेल, परिवहन, मैन्यूफैक्चरिंग-हर क्षेत्र में एआइ आधारित बदलाव की लहर चल रही है। नैसकाम के अनुसार यदि एआइ को रणनीतिक रूप से अपनाया गया तो वह 2025 तक भारत की जीडीपी में 500 अरब डालर का योगदान दे सकती है।

एआइ को लेकर आम धारणा है कि यह नौकरियां छीन लेगी, पर सच्चाई यह है कि यह नई नौकरियां भी पैदा कर रही है। हालांकि जल्द ही दोहराए जाने वाले और नियमित काम एआइ से स्वतः ही हो जाएंगे, लेकिन इसके चलते कई नए पेशे भी उभरे हैं-जैसे एआइ ट्रेनर, मशीन लर्निंग डेवलपर, डाटा एनोटेटर, एआइ एथिसिस्ट, प्राम्प्ट इंजीनियर आदि। भारत की युवा, तकनीकी रूप से दक्ष जनसंख्या इसे अपनाने के लिए उपयुक्त स्थिति में है। सरकार द्वारा शुरू किया गया 'इंडिया एआइ' प्रोग्राम और शिक्षा एवं उद्योग के साथ साझेदारी देश की एआइ क्षमता निर्माण में मदद कर रही है। देशभर में डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआइ एथिक्स से संबंधित कोर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर एआइ केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन हमें इसे केवल आशावाद का चश्मा पहन कर ही नहीं देखना चाहिए। एआइ तमाम मौजूदा नौकरियों को खत्म करेगी-विशेष रूप से बीपीओ, कस्टमर सर्विस, बेसिक कोडिंग और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में। मैकिंजे के अनुसार वर्ष 2030 तक दुनिया भर में 80 करोड़ नौकरियां स्वचालित हो सकती हैं। भारत में जहां बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक और कम-कौशल वाली नौकरियों में हैं, उनके लिए यह गंभीर संकट बन सकता है। एआइ युग में जिन कौशलों की जरूरत है, वे अब भी बहुत सीमित लोगों के पास हैं। अगर तुरंत डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक एआइ प्रशिक्षण में निवेश नहीं किया गया, तो भारत पीछे छूट सकता है। सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को मिलकर शिक्षा प्रणाली को फिर से परिभाषित करना होगा। भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखना, पुराना भूलना और नए सिरे से सीखना जानते हैं।

एआइ सिस्टम डाटा पर आधारित होते हैं और दुर्भाग्य से डाटा में समाज के मौजूदा भेदभाव और पूर्वाग्रह भी शामिल होते हैं। चेहरा पहचानने वाले सिस्टम अक्सर कुछ नस्लीय समूहों को गलत तरीके से पहचानते हैं। ऋण मंजूरी या नौकरी चयन में भेदभाव करने वाले एल्गोरिदम अब कल्पना नहीं, हकीकत हैं। भारत जैसे देश में जहां जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानताएं पहले से मौजूद हैं, वहां एआइ उचित रूप से नियंत्रित नहीं हुआ, तो वह इन्हें और बढ़ा सकता है। हवाई अड्डों और सार्वजनिक आयोजनों में चेहरे की पहचान तकनीक अपनाने से आमजन की निगरानी का खतरा बढ़ गया है। अगर एआइ का दुरुपयोग हुआ, तो यह नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है।

अमेरिका और चीन अरबों डालर एआइ अनुसंधान में झोंक रहे हैं। भारत को अपना अलग रास्ता चुनना होगा, जो नैतिक, समावेशी, सस्ता हो तथा जमीनी समस्याओं का हल करे। भारतीय स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के पास 'एआइ फार भारत' बनाने का अवसर है, जो कम संसाधन वाले क्षेत्रों में काम कर सकें, भारतीय भाषाओं को समझें और हमारी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें। ओपन-सोर्स माडल, अनुवाद टूल्स, कृषि या टेलीमेडिसिन में एआइ भारत की ताकत बन सकती है। इसके लिए लगातार निवेश, स्पष्ट नीति और वैश्विक सहयोग की जरूरत होगी। भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम बनाया है और एआइ पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन हमें एक समग्र और सुसंगत एआइ नियामक ढांचा चाहिए। इसमें पारदर्शिता, मानव निगरानी, जवाबदेही और समुचित अपील प्रणाली शामिल होनी चाहिए। नियम इतने सख्त भी न हों कि नवाचार रुक जाए। हमें एक ऐसा संतुलन बनाना होगा, जो भारत को एआइ में अग्रणी बनाए और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। भारत के पास एआइ अपनाकर आउटसोर्सिंग अर्थव्यवस्था से ज्ञान महाशक्ति बनने का मौका है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं तो डिजिटल लोकतंत्र, समावेशी विकास और सतत भविष्य की दिशा में एआइ भारत का साथी बन सकती है। भविष्य एआइ बनाम मानव का नहीं, बल्कि एआइ के साथ मानव का होगा।

(लेखक एआइ एंड बियांड के सह-संस्थापक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

समीक्षा और निंदा

समीक्षा और निंदा दो भिन्न अवधारणाएं हैं, जो अक्सर समाज में भ्रम उत्पन्न करती हैं। समीक्षा में सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, जबकि निंदा नकारात्मकता का प्रतीक है। जब हम किसी व्यक्ति के कार्यों की समीक्षा सकारात्मक और सुधारात्मक दृष्टि से करते हैं, तो वह व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रेरित होता है। संत-महापुरुष, माता-पिता, गुरुजन और सज्जन लोग हमेशा अपने प्रियजनों के विकास की दृष्टि से उनकी समीक्षा करते हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

समीक्षा एक दर्पण के समान है, जिसमें व्यक्ति को अपने संपूर्ण आचार-विचार की छवि दिखाई देती है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति को अपने गुणों को विकसित करने में मदद करता है। समीक्षा एक सैद्धांतिक आक्षेप है, जो व्यक्ति के चिंतन और क्रिया-कलाप में दोषों का निवारण करता है। इसके विपरीत निंदा व्यक्ति केंद्रित होती है और नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। यह व्यक्ति को राग-द्वेष से प्रभावित कर हतोत्साहित और अवसादित कर देती है। निंदक हमेशा विवाद और अलगाव को जन्म देते हैं। समीक्षा सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि निंदा व्यक्ति पर। समीक्षा में सुधार की भावना होती है, जबकि निंदा में प्रहार का भाव। समाज में निंदा के कारण विद्वेष की भावना का विषवमन होता है, जिससे पारस्परिक संबंधों में दरार आती है। इसलिए हमें निंदा के स्थान पर समीक्षा को अपनाना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति के दोषों को देखकर उसमें सुधार चाहते हैं, तो उसकी समीक्षा एकांत में उसके साथ करनी चाहिए। इससे उसमें विद्वेष या हीनता का भाव नहीं आएगा। इससे आपके प्रति उसमें सहानुभूति का भी संवर्धन होगा। समीक्षा का यह तरीका एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका को भी उजागर करता है। हमें चाहिए कि हम अपने आस-पास के लोगों की समीक्षा करें, ताकि वे अपने गुणों को पहचान सकें और उन्हें विकसित कर सकें।

आचार्य नारायण दास

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

गलती कर रहे हैं ट्रंप

'भारत की सामर्थ्य को समझे अमेरिका' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सृजनपाल सिंह ने अमेरिका के अहंकार के समक्ष कभी न झुकने वाले स्वाभिमानी भारत की सामर्थ्य को बखूबी विश्लेषित किया है। अमेरिका ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय भी पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखा और दुश्मन के 90 हजार से अधिक आत्मसमर्पित सैनिकों को युद्ध बंदी बनाकर पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। भारत के परमाणु कार्यक्रम को भी अमेरिका ने बाधित करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंकाया था। अबकी बार भी भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ की परवाह न करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को दो-टूक कहा है कि भारत दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, भारत की व्यापार नीति स्वतंत्र रहेगी। भारत से उलझ कर अमेरिका हर बार मात खाता रहा है और इस बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने अहंकार में वही गलती कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव में भारत अपने सदाबहार मित्र रूस से संबंध बिगाड़ने की गलती कभी नहीं करेगा। निकट भविष्य में भारत, चीन और रूस के आपसी रिश्ते अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़ (उप्र)

पार्टी की गिरती साख

संपादकीय आलेख 'यह कैसा एटम बम' में सदन नेता राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा 'एटम बम' की असफल प्रयोग पर प्रकाश डाला गया है। इसके पहले भी वे सदन में 'एटम बमों' का प्रक्षेपण कर चुके हैं, जो हमेशा फुस्स साबित हुआ है। राहुल के ऐसे वक्तव्यों से कांग्रेस पार्टी की साख ही गिरी है। राहुल गांधी ने अपने कार्यों-वक्तव्यों से सुप्रीम कोर्ट समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं को चौंकाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी ने ऐसे सबूत खोज निकाले हैं जिनसे चुनाव आयोग के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने आयोग के पास मौजूद सबूतों की तुलना ''परमाणु बम'' से भी की। उन्होंने आयोग के अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा था, हमने अपनी जांच कराई, इसमें छह माह लगे और जो मिला वह एक परमाणु बम है। जब यह फटेगा, तो चुनाव आयोग को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जवाब में चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आयोग रोजाना लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है।

युगल किशोर राही, छपरा

आंतरिक लोकतंत्र का अभाव

भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यहां पर पूर्ण लोकतंत्र है। सभी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। पूरी प्रक्रिया में सैकडों छोटे एवं बडे. राजनीतिक दल दम खम से हिस्सा लेते हैं। पर इन चुनावों में भाग लेने वाले अधिसंख्य राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। हर एक पर एक परिवार विशेष का कब्जा है। परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष का पद मिलने की संभावना ही नहीं है। सबसे पहले 140 वर्ष पुरानी कांग्रेस की बात करते हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, जबकि वह उस समय राजनीति में भी नहीं थे। गांधी परिवार का होने का लाभ मिला। इसी पारिवारिक निष्ठा के कारण 20 वर्ष से भी अधिक समय से कांग्रेस एक नेता पर आश्रित है। दूसरे प्रमुख दल भाजपा में भी लोकतंत्र की बहुत दुहाई बहुत दी जाती है। दल के अध्यक्ष पद पर किसी परिवार विशेष का अधिकार नहीं है पर पिछले 11 वर्षों में चयन का अधिकार अनौपचारिक रूप से मात्र एक व्यक्ति को प्राप्त है। यथार्थ है कि सपा मुलायम की, बसपा मायावती की, राजद लालू की, बीजू जनता दल नवीन पटनायक की, शिवसेना बाल ठाकरे की, तृणमूल ममता की, नेशनल कांफ्रेंस शेख अब्दुल्ला की, पीडीपी महबूबा मुफ्ती की एवं डीएमके स्टालिन की पारिवारिक पार्टी है।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

पोस्ट

तथाकथित 'एटम बम' का धमाका उलटा हो गया। आदित्य श्रीवास्तव सामने आए। वे लखनऊ के हैं। जब वहां थे, तो वोटर थे। फिर मुंबई आए, यहां वोटर हो गए। फिर शिफ्ट हो गए बेंगलुरु, वहां वोटर हो गए। इसमें चुनाव आयोग का षड्यंत्र क्या है? कांग्रेस को हवा में तीर छोड़ने का धंधा बंद करना चाहिए।

संजय निरुपम@sanjaynirupam

यदि एक संसदीय क्षेत्र में फर्जी वोटिंग के इतने आरोप हैं तो चुनाव आयोग को स्वयं जांच करनी चाहिए, क्योंकि मामला किसी व्यक्ति का नहीं है, जो व्यक्तिगत शपथपत्र की जरूरत हो। अगर सिस्टम में छेद है तो संस्था को स्वयं अपने अंदर झांकना चाहिए।

आरके विज@ipsvijrk

ट्रंप द्वारा भारत पर मनमाने टैरिफ लगाना अमेरिका का कोई नीतिगत मामला नहीं है। वह एक अहंकारी व्यक्ति हैं, जो भारत-पाकिस्तान में संघर्ष विराम के लिए प्रशंसा न मिलने पर गुस्से में हैं। अपनी निजी खुन्नस की आग में वे तीन दशकों में बने भारत-अमेरिकी रिश्ते को जलाने का प्रयास कर रहे हैं।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

जनपथ

धमकाएं या दाग दें वो टैरिफ की तोप,
सह लेंगे हम ट्रंप का नाजायज हर कोप।
नाजायज हर कोप और हरकत बचकानी,
है संकट में साथ आज हर हिंदुस्तानी।
ताऊ अपनी साख बोलकर रोज गिराएं,
जो-जो उनका दोस्त उसी को वे धमकाएं!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर वी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 119

****

चिंतन

संसद नहीं चलने देने से क्या हासिल हो पाएगा

संसद का मानसून सत्र लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। 21 जुलाई से सत्र शुरू हुआ है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने कई विधेयक पास कराने की तैयारी की है, लेकिन विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। आखिर जनता की गाढ़ी कमाई कब तक यूं ही जाया होती रहेगी? संसद सत्र के शुरू होने से पहले ही सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर, ट्रंप के दावे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, विपक्ष की मांग के अनुरूप दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब भी दिया गया, इसके बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ। वह अभी भी हंगामा ट्रैक पर है। आज आठ अगस्त को भी विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के सदस्य सरकारी कामकाज तो बाधित कर ही रहे हैं, आज उन्होंने गैर सरकारी कामकाज को भी अवरुद्ध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने दोहराया कि सरकार ने शुरू से कहा है कि नियमों के तहत वह हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा कि 'मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल चलने दें। यह महत्वपूर्ण समय होता है। नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता देख रही है कि नियोजित तरीके से सदन को कैसे बाधित किया जा रहा है।' राज्यसभा में भी यही स्थिति रहती है। सदन में चर्चा कम और हंगामा अधिक होता है। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हैं, आसन के नजदीक चले जाते हैं, नियम के विपरीत चर्चा की मांग करने लगते हैं, प्रश्नकाल नहीं चलने देते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जारी गतिरोध का जिक्र करते हुए शुक्रवार को बताया कि 'वर्तमान सत्र में लगातार हंगामे की वजह से सदन का अब तक 56 घंटे 49 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है।' उच्च सदन में आज भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस आसन द्वारा खारिज किए जाने के विरोध में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक शुरू होने के दस मिनट बाद ही दोपहर बारह बजे तक और बारह बजे शुरू होने पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर नियत कामकाज स्थगित कर चर्चा करने के लिए उन्हें नियम 267 के तहत 20 नोटिस मिले हैं। वर्तमान सत्र में रास सदस्यों के पास आज तक 195 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े 195 मुद्दे तथा विशेष उल्लेख के जरिये 195 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का अवसर था लेकिन अब तक केवल 13 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत सिर्फ पांच मुद्दे तथा विशेष उल्लेख के जरिये मात्र 17 मुद्दे ही उठाए गए हैं। यह पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले दो दशक से ऐसा ही हो रहा है। विपक्ष में जो भी दल रहे हों, संसद सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करते रहे हैं। संसद सत्र को अधिक उपयोगी बनाने की जरूरत है। अब जितने भी दिन सत्र बचे हैं, पक्ष व विपक्ष कोशिश करें कि सत्र चल सकें व जनोपयोगी मुद्दों पर चर्चा हो सके व विधेयक पास हो सकें।

विमर्श
आलोक शुक्ला

मतदाता सूचियों में पारदर्शिता जरूरी

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक पत्रकार वार्ता में देश की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महादेवपुरम विधान सभा क्षेत्र की वर्ष 2024 की मतदाता सूची का विश्लेषण करने पर 1,00,250 फर्जी नाम मिले। इस पर निर्वाचन आयोग की जो प्रतिक्रिया आई है, वह न तो उचित कही जा सकती है और न ही कानूनी रूप से सही है। अच्छा होता कि भारत निर्वाचन आयोग इस प्रकार का पत्र व्यवहार न करते हुए राहुल गांधी के विश्लेषण पर अपनी तथ्यपूर्ण प्रतिक्रिया देता और उनके विश्लेषण की त्रुटियों को उजागर करता। ऐसा न करने से आयोग की विश्वसनीयता ही कम होती दिख रही है।

सात जुलाई को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक पत्रकार वार्ता में देश की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महादेवपुरम विधान सभा क्षेत्र की वर्ष 2024 की मतदाता सूची का विश्लेषण करने पर 1,00,250 फर्जी नाम मिले। इनमें से 11,965 मतदाता डुप्लीकेट थे, 40,009 मतदाताओं के पते फर्जी थे, 10,452 के नाम बड़ी संख्या में किसी एक ही पते पर दिखाए गए थे। 4,132 मतदाताओं की फोटो पहचानना संभव नहीं था और 33,692 मतदाताओं के नाम फार्म 6 का दुरुपयोग करके मतदाता सूची में जोड़े गए थे। राहुल गांधी की इस पत्रकार वार्ता से राजनीतिक भूचाल आ गया है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर एक राष्ट्रीय बहस भी शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत शपथ के साथ घोषणा पत्र देने का आग्रह किया है।

राहुल गांधी का पहला आरोप तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में मदद करने के लिए महादेवपुरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों का पंजीकरण जानबूझकर किया गया है। दूसरा आरोप यह है कि इन फर्जी वोटरों ने भाजपा के पक्ष में वोट डाले और इस प्रकार निर्वाचन आयोग की मदद से भाजपा ने चुनाव को चुरा लिया। भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत, राजनीति से प्रेरित और देश के लिए अहितकर बताया है। राजनीतिक दल होने के कारण भाजपा से ऐसी ही राजनीतिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा भी थी। परन्तु निर्वाचन आयोग की जो प्रतिक्रिया आई है, वह न तो उचित कही जा सकती है और न ही कानूनी रूप से सही है। नियम 23(3)(बी) के अंतर्गत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान है, जिसके लिए 15 दिन की समय सीमा भी निर्धारित है। साफ है कि न तो इतने दिनों बाद अपील की जा सकती है और न ही राहुल गांधी अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई गई मतदाता सूची का विश्लेषण करते हुए जानबूझकर फर्जी नाम जोड़े जाने के आरोप लगाए हैं। अच्छा होता कि भारत निर्वाचन आयोग इस प्रकार का पत्र व्यवहार न करते हुए राहुल गांधी के विश्लेषण पर अपनी तथ्यपूर्ण प्रतिक्रिया देता और उनके विश्लेषण की त्रुटियों को उजागर करता। ऐसा न करने से निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता ही कम होती दिख रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के जिम्मेदार पद पर हैं इसलिए इस आलेख में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा को सही मानते हुए उसका तथ्यपूर्ण विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह आलेख इस बात का प्रयास करता है कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को पक्षपातपूर्ण न मानते हुए मतदाता सूची में राहुल गांधी दिखाई गई विसंगतियां के कारणों को समझा जाए।

मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम और फार्म 6 का दुरुपयोग, यह दोनों लगभग एक समान आरोप हैं, इसलिए इन पर एक साथ विचार करेंगे। दरअसल बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में डुप्लीकेट नामों की समस्या

लंबे समय से चली आ रही है। इन शहरों में लोग अक्सर किराये के मकानों में रहते हैं। मकान मालिक अधिकतर 11 महीनों के लिए किरायानामा करते हैं और उसके बाद किरायेदार पर मकान खाली करने का दबाव डालते हैं। मेट्रो शहरो में बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों से आते हैं और जल्दी-जल्दी जॉब बदलने के कारण अपना पता भी बदलते रहते हैं। यह लोग नए पते पर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा तो लेते हैं, परन्तु पुराने स्थापन से अपना नाम कटवाते नहीं हैं। जब इनके परिवार साथ में रहते हैं, तो बूढ़े मां-बाप का नाम भी मतदाता सूचियों में 2 स्थानों पर जुड़ जाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव के ठीक पहले मतदाताओं के नाम जोड़ने की मुहिम भी चलाता है जिसके कारण भी ऐसे डुप्लीकेट नामों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। हालांकि फार्म-6 में यह घोषणा की जाती है कि नाम जुड़वाने का आवेदन देने वाले व्यक्ति का नाम अन्य किसी स्थान की मतदाता सूची में नहीं है, परन्तु कोई भी इस घोषणा को गंभीरता से नहीं लेता है और लोगों के नाम अनेक स्थानों पर जुड़ते ही जाते हैं। फर्जी पते और एक ही मकान में बहुत अधिक नामों के होने का कारण दरअसल यह है कि निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के आदेश जारी किए हैं जिनका कोई स्थाई पता नहीं है। आयोग का यह फैसला ऐसे गरीब मजदूरों के पक्ष में है जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है और जो फुटपाथ पर भी जीवन काटने के लिए मजबूर हैं। मेट्रो शहरों में लगातार चल रहे निर्माण कार्यों के कारण ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होती है। इन गरीबों को अक्सर नगर निगम के अधिकारी और पास के गुंडे फुटपाथ पर उनके रहने के स्थान से भगाते रहते हैं। इस कारण वे अपने रहने का स्थान बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों के नामों को फर्जी पते वाला कहा गया है। पहचान राहुल गांधी का तीसरा आरोप है कि बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिनकी पहचान योग्य फोटो मतदाता सूची में नहीं है। दरअसल कुछ साल पहले तक मतदाता सूचियों में मतदाता की फोटो होती ही नहीं थी। आयोग ने जब फोटो जोड़ने का निर्णय लिया तो अधिकारियों ने फोटो एकत्रित करना प्रारंभ किया। बहुत सी फोटो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलीं। आयोग धीरे-धीरे अच्छी क्वालिटी की फोटो एकत्र करने का कार्य कर रहा है, पर यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आयोग के पास क्या विकल्प हैं - राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची के विश्लेषण का आसान स्पष्टीकरण आयोग दे सकता है। न जाने किस कारण से निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न करने की नीति अपनाई है। मेरा मानना तो यह है कि राहुल गांधी ने डुप्लीकेट नामों, फर्जी पते और खराब फोटो की जो सूचियां पत्रकार वार्ता में दिखाई थीं, वह सूचियां उनसे मांगकर निर्वाचन आयोग को उनमें शामिल प्रत्येक नाम की जांच अपने अधिकारियों से करा लेनी चाहिए और प्रत्येतक नाम के संबंध में उचित कारण देते हुए अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हर भारतीय की यह अपेक्षा है कि त्रुटिहीन निर्वाचक नामावली तैयार की जाए। आयोग शायद इसी उद्देश्य से पहले बिहार में और फिर सारे देश में सघन पुनरीक्षण का कार्य करना चाहता है। परन्तु आयोग को यह समझना होगा कि जब तक नई और उन्नत तकनीक का प्रयोग करके प्रक्रिया में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक सघन पुनरीक्षण का कोई लाभ नहीं होने वाला है। अच्छा होगा कि निर्वाचन आयोग सूचना प्रौद्योगिकी के जानकारों की एक राष्ट्रीय समिति बनाए जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी रखा जाये। यह समिति मतदाता सूचियों को शुद्ध रूप में बनाने और उनके रखरखाव के संबंध में जो सुझाव दे उन पर आयोग को खुले हृदय से विचार करना चाहिये और उसके बाद देशहित में फैसला लेना चाहिये।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

स्पेस स्टेशन
डॉ. रमेश ठाकुर

अंतरिक्ष से मिसाइल अटैक की योजना बना रहे देश!

भविष्य में लड़ाई लड़ने के तरीके बदलने वाले हैं। पावरफुल मुल्क बंदूक, तोप, तलवारों या अन्य हथियारों से नहीं, बल्कि मिसाइलों से अंतरिक्ष में बने 'स्पेस स्टेशनों' से युद्ध की योजना बना रहे हैं। सुखद ख़बर यहां ये है कि भारत भी इस योजना से पीछे नहीं है। अन्य देशों की 'मिसाइल अटैक' वाली मंशाओं की संभावनाओं के बीच भारत ने भी अंतरिक्ष में अपना पैर जमा दिया है। सिर्फ दशक भर बाद किसी पराए नहीं, स्वनिर्मित 'अतंराष्ट्रीय स्पेस सेंटर' में उतरा करेंगे हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों की कोशिशें अंतिम चरण में हैं। कुल मिलाकर अगर ये मिशन 10 सालों में मुकम्मल होता है, तो स्पेस में भी हम सफलता के झंडे गाड़ देंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा वर्ष-2035 तक अंतरिक्ष में खुद का 'इंटरनेशनल स्पेस सेंटर' बनाने का ऐलान किया जा चुका है। बीते दिनों बेशक शुभांशु शुक्ला नासा अधिकृत मिशन के जरिए स्पेस सेंटर में उतरे हों, पर भविष्य में जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में यात्रा करेगा, तो वह अपने स्पेस सेंटर में ही लैंड करेगा। ऐसी सफलता निश्चित रूप से बदलते हिंदुस्तान की अकल्पनीय, करिश्माई व अनोखी कही जाएगी। पावरफुल देश अंतरिक्ष क्षेत्र को क्यों तवज्जो देने में लगे हैं? क्यों वहां नित नई तकनीकी शक्तियों के विस्तार में जुटे हैं? क्या भविष्य में 'स्पेस स्टेशन' के जरिए मिसाइल अटैक करने की कोई योजनाएं तो नहीं बनाई जा रही हैं? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में कौंधने लगे हैं। सवाल उठने वाजिब इसलिए भी हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में ज्यादातर देश अपनी लड़ाइयां जमीन को छोड़कर हवाई मिसाइलों से लड़ने लगे हैं। ईरान, इजरायल, गाजा, फिलिस्तीन, यूक्रेन-रूस और अभी हाल में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव में हुए सीजफायर इसके उदाहरण हैं। शायद वो वक्त दूर नहीं, जब आगामी लड़ाइयों की आहटें हमें सीधे अंतरिक्ष से सुनाई दिया करेंगी। ये बातें बेशक चौंकाने वाली हों, पर ऐसा मुमकिन होता दिखाई पड़ने लगा है। अंतरिक्ष स्टेशनों से युद्ध स्तर पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोधों में कुछ मुल्क बीते कुछ दशकों से लगे हुए हैं। अभी तक अंतरिक्ष में मात्र दो ही स्पेस स्टेशन हैं।

पहला, 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' जिसे अमेरिका-रूस व अन्य देशों ने अपने साझा प्रयास से मिलकर तैयार किया है। वहीं, दूसरा स्पेस स्टेशन चीन का निजी है। हालांकि अब रूस, अमेरिका, भारत व एकाध और अन्य मुल्क अपने-अपने निजी 'स्पेस स्टेशन' बनाने के अंतिम चरणों में हैं। अगले 10 साल में भारत के अलावा रूस भी अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा। मकसद भले ही इन स्पेस स्टेशनों का प्रयोग वैज्ञानिक शोधों के लिए हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इन स्पेस स्टेशनों के जरिए कुछ देश सैटेलाइट्स मिसाइलों से लड़ाइयां लड़ने की जुगत भिड़ा रहे हों? उनके पहुंचने का माध्यम इस बार भले ही 'एक्सिओम मिशन-4' क्यों न रहा हो? लेकिन भविष्य में ये निर्भरता खत्म होने को है। अंतरिक्ष में निजी स्पेस स्टेशन सिर्फ चीन का है, लेकिन उस दिशा में भारत भी करीब पहुंच चुका है। वर्ष 2009 में अमेरिका ने रूस के साथ एक करार किया था, जिसमें उन्होंने अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव की प्रासंगिकता अब समझ में आती है। अपने निजी स्पेस स्टेशन के जरिए अमेरिका अंतरिक्ष से मिसाइल से लड़ने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष में भी अपना एकछत्र राज करना चाहता है। धरती से अंतरिक्ष की दूरी करीब 62 मील है, जिसे पूरा करने में 28 घंटे लगते हैं। इतनी दूरी वाली मारक क्षमता वाली मिसाइल अमेरिका तैयार कर रहा है। अंतरिक्ष में 24 घंटे में 16 दफे सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त होता है। 90-90 मिनट की दिन और रातें होती हैं।

अंतरिक्ष स्टेशन 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर लगभग 16 बार चक्कर लगाते हैं। इन सभी की पड़ताल अमेरिका कर चुका है। सैटेलाइट मिसाइलों का प्रयोग अतंरिक्ष से कैसे हो, इसके लिए नासा की रिसर्च बहुत पहले से जारी है। इसरो और नासा अंतरिक्ष में मानव जीवन, सांस, पानी होने की पड़तालों में भी जुटे हैं। पर, इसरो का अगला कदम सन-2035 में अंतरिक्ष में खुद का 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' स्थापित करने के अलावा वर्ष-2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना है। इसके लिए वह 'मिशन गगनयान' को लांच करने की घोषणा पहले ही कर चुका है। इस मिशन में लगे वैज्ञानिकों को विशेष स्पेस ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो अपने आगामी 'गगनयान मिशन' को अब तक के सबसे बड़े मिशन में गिन रहा है जिसकी तैयारियों में बीते कई वर्षों से देश के टॉप 400 अंतरिक्ष वैज्ञानिक लगे हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

'छिद्रान्वेषण', जो लोग दूसरों में ढूंढ़ते हैं दोष

संकलित
दर्शन

लोग प्रायः दूसरों में दोष ढूंढ़ने में लगे रहते हैं। इसी को छिद्रान्वेषण कहते हैं। ऐसा करने वाले लोग अपने बड़े-बड़े दोषों को देखते हुए भी नहीं देख पाते। फिर भी दूसरों में दोष निकालने से बाज नहीं आते। यह प्रवृत्ति न केवल स्वयं के लिए, अपितु समाज के लिए भी घातक है। इसी कारण समाज में ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का परिवेश बनता है। इसका सर्वाधिक विपरीत प्रभाव उन लोगों के मनोबल पर पड़ता है, जो ईमानदारी से समाज और देश की सेवा कर जीवन यापन करना चाहते हैं। छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति अमूमन उन्हीं लोगों में देखने को मिलती है जो स्वयं बुराइयों के भंडार होते हैं। इससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर क्षरण होता है और स्वयं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है, 'मनुष्य की यह प्रवृत्ति कभी अपने भीतर सद्गुणों का विकास नहीं होने देती।' परिणामस्वरूप मन, वाणी और कर्म तीनों कलुषित हो जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन छिद्रान्वेषी दुष्प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने कभी अपने दोष देखने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए उसके मन, वाणी और कर्म सभी कलुषित हो गए। एक बार गुरु द्रोण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को राज्य में साधु पुरुषों की गणना के लिए भेजा तो दुर्योधन को कोई साधु पुरुष मिला ही नहीं। यह दुर्योधन की छिद्रान्वेषी दुष्प्रवृत्ति का परिणाम था। इसके विपरीत युधिष्ठिर को कोई दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। वास्तव में दूसरे के दोष देखने का अधिकार उसी को है, जिसमें वह बुराई न हो।

ब्रह्माजी को दंड देने के लिए प्रकट हुए थे कालभैरव

संकलित
प्रेरणा

शिवजी के 19 अवतारों में से एक है कालभैरव। भैरव अवतार से जुड़ी कई अलग-अलग मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं में ब्रह्माजी को दंड देने के लिए शिवजी के क्रोध से कालभैरव प्रकट हुए थे। कालभैरव की उत्पत्ति से जुड़ी सृष्टि की शुरुआत के समय की बहुत प्रचलित कथा है। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी खुद को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति बन गई। उस समय शिवलिंग प्रकट हुआ और शिव जी ने इन दोनों का विवाद शांत किया। उसी समय वहां एक विशाल पुरुष की आकृति प्रकट हुई। ये आकृति शिवजी का ही एक रूप थी। शिव जी ने उससे कहा कि तुम काल के समान हो और भीषण हो। इसी वजह से तुम्हारा नाम कालभैरव होगा। पंचमुखी ब्रह्मा जी बार-बार खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए कालभैरव ने ब्रह्माजी का एक सिर काट दिया था। इस घटना के बाद से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए। शिव जी ने कालभैरव को काशी का नगरपाल बना दिया। कालभैरव की पत्नी भैरवी देवी पार्वती की अवतार हैं। कालभैरव की पूजा में शराब (मदिरा), तामसिक खाना खासतौर पर चढ़ाया जाता है। दरअसल, कालभैरव हमारी बुराइयों को खत्म करने वाले देवता हैं। इनकी पूजा करते समय भक्त नशे की चीजें चढ़ाकर अपनी बुराइयां छोड़ने का संकल्प लेता है। जो लोग इस संकल्प को निभाते हैं, उन्हें भैरव की विशेष कृपा मिलती है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

अंतर्मन

आज की पाती

लोगों में धन की भूख बढ़ी

आज भौतिकवादी और आधुनिक युग में कुछ लोगों को धन की इतनी भूख बढ़ रही है कि वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि, धन एक वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है, और इसके विपरीत है अधर्म का खजाना। लेकिन आज बहुत से लोग अमीर बनने के चक्कर में बेईमानी, हेराफेरी, अनैतिकता की राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि गलत तरीकों से कमाई धन-दौलत ज्यादा दिन सुख नहीं दे सकती। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अगर हम बेईमानी कि कमाई से अन्न खरीद कर खाएंगे या अपने परिवार को खिलाएंगे तो क्या वो अन्न हमारे या हमारे परिवार के लिए उचित भोजन होगा? शायद नहीं। पाप की कमाई से अगर बच्चों का पालन-पोषण किया जाए तो इससे बच्चे पथभ्रष्ट ही होंगे। - विवेक चौधरी, बेमेतरा

ट्रेंड

उज्ज्वला योजना

रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व मोदी जी ने देश की करोड़ों बहनों को सौगात देते हुए 12,000 करोड़ की लागत से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी है।
- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

हर घर तिरंगा अभियान

इस बार हर घर तिरंगा अभियान और भी है खास आपरेशन सिंदूर से विजय का अद्भुत है अहसास। "हर घर तिरंगा" अभियान के वालेंटियर बनिए। अपने आसपास देशभक्ति के इस राष्ट्र उत्सव का आनंदित वातावरण बनाइए। अपनी जान-पहचान के नागरिकों को इससे जोड़िए।
-गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति मंत्री

अर्थव्यवस्था की रीढ़

खेती-किसानी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के साथ-साथ हमारी अस्मिता, संस्कृति और परंपरा की पहचान है। खेतों की हरियाली किसानों की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। हम मेहनतकश किसानों को खुशहाल और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
-हेमन्त सोरेन, सीएम, झारखंड

भाजपाई भ्रष्टाचार

प्रयागराज के नाम पर 20 हजार करोड़ का स्मार्ट सिटी का जो फंड भाजपाई निगल गये, अगर 'महाकुंभ के उस महाकोष' का एक अंश भी सीवर और नाला सफाई में लग जाता तो प्रयागराज का थाना आज तालाब न बनता। ये भाजपाई भ्रष्टाचार है।
- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

भारत पर शुल्क लगाना 'राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा'

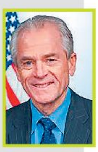

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाना ''राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा'' है, जो नयी दिल्ली के ''रूसी तेल की खरीद बंद करने से साफ इनकार'' से जुड़ा है। पिछले सप्ताह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो सात अगस्त से लागू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। व्हाइट हाउस में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवारो ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ''भारत पर लगाए गए शुल्क का तर्क पारस्परिक शुल्क से बिलकुल अलग है।'' उन्होंने कहा, ''यह पूरी तरह से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, जो भारत के रूसी तेल की खरीद बंद करने से साफ इनकार से जुड़ा हुआ है और हर अमेरिकी को इसका गणित समझना चाहिए, क्योंकि यह व्यापारिक स्थिति से संबंधित है।'' नवारो ने कहा, ''आप इस बात से समझिए कि भारत शुल्क का 'महाराजा' है, यह अमेरिकी उत्पादों पर दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है और इसके पास ऊंची गैर-शुल्क बाधाएं भी हैं, जिससे हम अपने उत्पाद वहां नहीं पहुंचा पाते।''

ऑफ बीट

कम सामग्री वाले खाद्य पदार्थ अधिक स्वास्थ्यवर्धक होते हैं?

खाद्य पदार्थों की सामग्री को उनके वजन के क्रम में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सूची में सबसे पहले वाली चीजें ही उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती हैं। सबसे आखिर वाली चीजें सबसे कम होती हैं। खाद्य लेबल में पोषण संबंधी जानकारी पैनल भी शामिल होता है, जो आपको प्रत्येक बार परोसे जाने पर प्रमुख पोषक तत्वों (ऊर्जा, प्रोटीन, कुल कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, कुल वसा, संतृप्त वसा और सोडियम) की मात्रा बताता है। यह पैनल आपको प्रति 100 ग्राम या मिलीलीटर में सामग्री भी बताता है, जिससे आप प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों को भी पैक किया जा सकता है। जिन उत्पादों की सामग्री सूची में केवल एक, दो या तीन वस्तुएं होती हैं, वे आमतौर पर अपने उस रूप के क़रीब होते हैं जैसा खाद्य पदार्थ खेत से सीधे लाए जाने पर होता है। इसलिए, भले ही ये पैकेजिंग में आते हों, इन्हें संपूर्ण खाद्य पदार्थ माना जा सकता है। ''संपूर्ण खाद्य पदार्थ'' वे हैं जिन पर शून्य से न्यूनतम प्रसंस्करण किया गया है, जैसे ताजे फल और सब्जियां, दालें, फलियां, साबुत अनाज जैसे जई या भूरा चावल, बीज, मेवे और अप्रसंस्कृत मांस और मछली। समग्र स्वास्थ्य को सहारा देने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई आहार संबंधी दिशानिर्देश संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने तथा अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को सीमित करने की सलाह देते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 9 अगस्त, 2025

दैनिक जागरण

विपत्ति में हार तभी होती है जब मनुष्य उससे डरता है

हाई कोर्ट–सुप्रीम कोर्ट

उच्चतर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के लिए यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश को आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोकती है और फिर जब वहां के 13 जज इसका प्रतिवाद करते हैं तो वह अपना फैसला वापस ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार के खिलाफ दिए गए अपने आदेश को वापस लेते हुए यह कहा कि उसका इरादा उन्हें शर्मिंदा करने का नहीं था, लेकिन फैसले के वक्त जैसी टिप्पणियां की गई थीं, वे तो उनकी योग्यता और निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाली थीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि ऐसा खराब और त्रुटिपूर्ण फैसला नहीं देखा? प्रश्न यह है कि अब वह कथित खराब फैसला खराब क्यों नहीं रहा? यह सामान्य बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर अपनी आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट के 13 न्यायाधीश अपने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखें। यह ठीक है कि इस पत्र का संज्ञान लिया गया और उसके बाद चर्चा एवं विवाद का विषय बना सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस हो गया, लेकिन क्या इसी के साथ मामले का पटाक्षेप हो गया? शायद नहीं। जो भी हो, इस सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करते हुए जो टिप्पणियां करते हैं, वे कई बार उनके फैसलों का हिस्सा क्यों नहीं बनतीं?

कई बार किसी मामले की सुनवाई के दौरान की गईं तीखी टिप्पणियां कुछ और संदेश देती हैं और फैसला कुछ और कह रहा होता है। इससे भी बड़ी विडंबना यह कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गईं मौखिक टिप्पणियों को नजीर की तरह लिया जाता है। आखिर जो टिप्पणी फैसले का हिस्सा नहीं, उसे महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि ऐसी टिप्पणी होनी ही क्यों चाहिए? अच्छा यह होगा कि इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसी टिप्पणियां विवाद और अनावश्यक बहस का विषय बनती हैं। यह शुभ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिका की विसंगतियों को रेखांकित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कई विषयों पर दो टूक ढंग से अपनी बात कही है। उनसे यही अपेक्षित है कि वे विसंगतियों को रेखांकित करने तक ही सीमित न रहें, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए भी सक्रिय हों। उनकी सक्रियता के दायरे में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की विवादास्पद कोलेजियम व्यवस्था भी आनी चाहिए और महाभियोग की जटिल एवं लंबी प्रक्रिया भी। इसी जटिलता के कारण आज तक किसी जज के खिलाफ महाभियोग पारित नहीं हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही नहीं थे।

कर व्यवस्था पर चोट

झारखंड में उजागर हुआ 800 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था और कर प्रणाली पर गहरा प्रहार भी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सरायकेला और अन्य कई शहरों में की गई छापेमारियों में यह सामने आया कि दर्जनों फर्जी कंपनियों के माध्यम से फर्जी इनवाइस तैयार कर करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवैध रूप से हासिल किया गया। यह कोई सामान्य कर चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध लूट है जिसमें वास्तविक माल या सेवा का कोई लेन-देन नहीं हुआ। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि तकनीक आधारित कर प्रणाली, चाहे वह जितनी भी आधुनिक क्यों नहीं हो, यदि निगरानी और जवाबदेही मजबूत नहीं हो, तो वह फर्जीवाड़े का शिकार हो सकती है। घोटाले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह झारखंड जैसे राज्य में हुआ है, जहां पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप आए दिन लगते रहे हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि ईमानदार करदाताओं और कारोबारियों के विश्वास को भी चोट पहुंचाती हैं। अब यह आवश्यक हो गया है कि राज्य और केंद्र सरकार इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं, दोषियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा दी जाए और साथ ही जीएसटी प्रशासनिक प्रणाली में निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

फर्जीवाड़ा रोकने के जीएसटी प्रशासनिक प्रणाली में निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है

खतरनाक पड़ोसी है बांग्लादेश

प्रकाश सिंह

बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान से बढ़ती हुई नजदीकियां भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती बनने जा रही है

अवधेश राजपूत

आज से करीब एक वर्ष पहले पांच अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलटा गया। छात्र आंदोलन की आंधी में शेख हसीना भाग कर भारत की शरण में आ गईं और अमेरिका के प्रभाव से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जबरन सत्ता परिवर्तन में जमाते इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, हिजबुत तहरीर, हिफाजते इस्लाम जैसे इस्लामिक संगठनों का भी हाथ रहा। यूनुस सरकार ने जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर लगे प्रतिबंध हटा लिए और अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया। जेल में बंद हजारों जिहादियों को छोड़ दिया गया। कई शहरों में 'इस्लामिक स्टेट' के झंडे फहराने लगे। अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी के विरुद्ध सारे आरोप वापस ले लिए गए। रहमानी ने एक वायरल हुए वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवाहन किया कि वे मोदी के शासन से बंगाल को मुक्त कर अपनी स्वतंत्रता घोषित करें। एक कट्टरपंथी नेता सैयद मोहम्मद करीम ने बांग्लादेश में शरिया लागू करने की मांग करते हुए कहा कि देश में तालिबान जैसी हुकूमत होनी चाहिए।

जब 26 सितंबर, 2024 को मोहम्मद यूनुस संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे, तब उनके सम्मान में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव ने एक समारोह का आयोजन किया था। इसमें बिल क्लिंटन ने हिजबुत तहरीर के नेता महफूज आलम की बांग्लादेश में आंदोलन चलाने के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। हिजबूत एक कट्टर इस्लामी संगठन है, जो संसार भर में खलीफा का साम्राज्य चाहता है। यह संगठन इंग्लैंड, अमेरिका और कई अन्य देशों में प्रतिबंधित है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम वहां के अल्पसंख्यकों, विशेष तौर से हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। हत्या, अपहरण, दुष्कर्म के साथ मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएं आम हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच अल्पसंख्यकों के विरुद्ध 2,442 हिंसात्मक घटनाएं हुईं। यूनुस सरकार को अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके प्रमुख नेता बराक ओबामा, बिल एवं हिलेरी क्लिंटन आदि का पूरा समर्थन है। इस कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वाच जैसी संस्थाओं ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया और कोई रिपोर्ट नहीं छापी। जिन चंद पत्रकारों ने इन घटनाओं पर अपनी आवाज उठाई, वे गिरफ्तार कर लिए गए और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे चलाए गए। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस के अनुसार अभी तक 878 पत्रकारों को निशाना बनाया जा चुका है। बांग्लादेश में नया आतंक विरोधी कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। बांग्लादेश में सिक्योरिटी आर्डिनेंस भी पास किया गया है। इसका इस्तेमाल सरकार अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज को दबाने के लिए कर रही है।

यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की आर्थिक हालत खस्ता होती जा रही है। जो महंगाई सितंबर 2024 में 9.92 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 10.87 प्रतिशत हो गई है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुश्किल से चार प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। विदेश से होने वाले निवेश गिर रहे। कपड़ा उद्योग, जो देश की आर्थिकी का आधार था, संकट में चल रहा है। 69 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और 76,500 कर्मी बेकार हो गए हैं।

शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में बराबर सुधार होता रहा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के भारत विरोधी संगठनों के सदस्यों को पहले बांग्लादेश में शरण मिल जाती थी और वे असम, नगालैंड, मणिपुर आदि में हिंसात्मक कार्रवाई करते थे। यह सब शेख हसीना ने बंद कर दिया, परंतु अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार का भारत से फासला धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यूनुस सरकार का कट्टरपंथियों से गठजोड़ है। कुछ समय पहले चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक बैठक भी हुई, जिसका उद्देश्य भारत को अलग-थलग करना था। मोहम्मद यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक जाल फैलाने का न्योता दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सातों उत्तर-पूर्वी राज्यों की समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है। ऐसे में चीन को बांग्लादेश में अच्छा बाजार मिलेगा।

चुनाव को लेकर बांग्लादेश में आंतरिक मतभेद हो गए हैं। चूंकि मोहम्मद यूनुस को सत्ता का आनंद मिल रहा है, इसलिए वह अप्रैल 2026 के पहले चुनाव नहीं करना चाहते। आर्मी प्रमुख जनरल वकार ने कहा है कि चुनाव दिसंबर 2025 तक हो जाने चाहिए। इसके बाद भी अनिश्चितता बनी हुई है। वहां चुनाव के बाद जो सरकार बने भारत को उसका रवैया देखना पड़ेगा। यदि बांग्लादेश की नई सरकार भारत विरोधी रहती है तो हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारत में कम से कम दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हमें यह कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश इन्हें या तो वापस ले या इन्हें बसाने के लिए हमें आवश्यक भूमि हस्तांतरित करे। यह भूमि हम रंगपुर डिवीजन में मांगें और यदि बांग्लादेश नहीं दे तो उसे जबरदस्ती हासिल करने के लिए कदम उठाए जाएं। अगर हम इसमें सफल हो गए तो सिलीगुड़ी गलियारा में 'चिकन नेक' की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड मांग सकते हैं और चीन ताइवान पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर सकता है तो हम बांग्लादेश से कुछ जमीन उन्हीं के नागरिकों को बसाने के लिए मांग सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक है। आज वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला है। इससे अल्पसंख्यक भयभीत जिंदगी बिता रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजदीकियां भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती बनने जा रही हैं। भारत को चीन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश से भी सावधान रहना होगा।

(लेखक सीमा सुरक्षा बल एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

बदलाव की तेज लहर लाई एआइ

जसप्रीत बिंद्रा

भारत के पास एआइ अपनाकर आउटसोर्सिंग अर्थव्यवस्था से ज्ञान महाशक्ति बनने का मौका है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआइ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह हमारे जीने, काम करने, सीखने और सोचने के तरीके को तेजी से बदल रही है। हमारे स्मार्टफोन में वायस असिस्टेंट से लेकर कंपनियों के निर्णयों तक, एआइ हर जगह मौजूद है। जैसे-जैसे भारत एआइ-संचालित अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, यह जरूरी हो गया है कि हम मशीनी कौशल यानी एआइ को समझें। आज एआइ की शक्ति कृषि से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर वित्त तक हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है। भारत में किसान अब एआइ आधारित सेंसर और ड्रोन के जरिए फसल की निगरानी और सिंचाई का प्रबंधन कर रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ा है और संसाधनों की बर्बादी घटी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआइ अब कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों की पहचान पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक तरीके से कर पा रही है। भारतीय स्टार्टअप दूरदराज इलाकों में एआइ की मदद से एक्स-रे और एमआरआइ की व्याख्या कर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा रहे हैं। फाइनेंस, रिटेल, परिवहन, मैन्यूफैक्चरिंग- हर क्षेत्र में एआइ आधारित बदलाव की लहर चल रही है। नैसकाम के अनुसार यदि एआइ को रणनीतिक रूप से अपनाया गया तो वह 2025 तक भारत की जीडीपी में 500 अरब डालर का योगदान दे सकती है।

एआइ को लेकर आम धारणा है कि यह नौकरियां छीन लेगी, पर सच्चाई यह है कि यह नई नौकरियां भी पैदा कर रही है। हालांकि जल्द ही दोहराए जाने वाले और नियमित काम एआइ से स्वतः ही हो जाएंगे, लेकिन इसके चलते कई नए पेशे भी उभरे हैं-जैसे एआइ ट्रेनर, मशीन लर्निंग डेवलपर, डाटा एनोटेटर, एआइ एथिसिस्ट, प्राम्प्ट इंजीनियर आदि। भारत की युवा, तकनीकी रूप से दक्ष जनसंख्या इसे अपनाने के लिए उपयुक्त स्थिति में है। सरकार द्वारा शुरू किया गया 'इंडिया एआइ' प्रोग्राम और शिक्षा एवं उद्योग के साथ साझेदारी देश की एआइ क्षमता निर्माण में मदद कर रही है। देशभर में डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआइ एथिक्स से संबंधित कोर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर एआइ केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन हमें इसे केवल आशावाद का चश्मा पहन कर ही नहीं देखना चाहिए। एआइ तमाम मौजूदा नौकरियों को खत्म करेगी-विशेष रूप से बीपीओ, कस्टमर सर्विस, बेसिक कोडिंग और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में। मैकिंजे के अनुसार वर्ष 2030 तक दुनिया भर में 80 करोड़ नौकरियां स्वचालित हो सकती हैं। भारत में जहां बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक और कम-कौशल वाली नौकरियों में हैं, उनके लिए यह गंभीर संकट बन सकता है। एआइ युग में जिन कौशलों की जरूरत है, वे अब भी बहुत सीमित लोगों के पास हैं। अगर तुरंत डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक एआइ प्रशिक्षण में निवेश नहीं किया गया, तो भारत पीछे छूट सकता है। सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को मिलकर शिक्षा प्रणाली को फिर से परिभाषित करना होगा। भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखना, पुराना भूलना और नए सिरे से सीखना जानते हैं।

गोवा में एआइ मिशन-2027 में भागीदारी करते युवा। प्रेट्र

एआइ सिस्टम डाटा पर आधारित होते हैं और दुर्भाग्य से डाटा में समाज के मौजूदा भेदभाव और पूर्वाग्रह भी शामिल होते हैं। चेहरा पहचानने वाले सिस्टम अक्सर कुछ नस्लीय समूहों को गलत तरीके से पहचानते हैं। ऋण मंजूरी या नौकरी चयन में भेदभाव करने वाले एल्गोरिदम अब कल्पना नहीं, हकीकत हैं। भारत जैसे देश में जहां जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानताएं पहले से मौजूद हैं, वहां एआइ उचित रूप से नियंत्रित नहीं हुआ, तो वह इन्हें और बढ़ा सकता है। हवाई अड्डों और सार्वजनिक आयोजनों में चेहरे की पहचान तकनीक अपनाने से आमजन की निगरानी का खतरा बढ़ गया है। अगर एआइ का दुरुपयोग हुआ, तो यह नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है।

अमेरिका और चीन अरबों डालर एआइ अनुसंधान में झोंक रहे हैं। भारत को अपना अलग रास्ता चुनना होगा, जो नैतिक, समावेशी, सस्ता हो तथा जमीनी समस्याओं का हल करे। भारतीय स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के पास 'एआइ फार भारत' बनाने का अवसर है, जो कम संसाधन वाले क्षेत्रों में काम कर सकें, भारतीय भाषाओं को समझें और हमारी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें। ओपन-सोर्स माडल, अनुवाद टूल्स, कृषि या टेलीमेडिसिन में एआइ भारत की ताकत बन सकती है। इसके लिए लगातार निवेश, स्पष्ट नीति और वैश्विक सहयोग की जरूरत होगी। भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा अधिनियम बनाया है और एआइ पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन हमें एक समग्र और सुसंगत एआइ नियामक ढांचा चाहिए। इसमें पारदर्शिता, मानव निगरानी, जवाबदेही और समुचित अपील प्रणाली शामिल होनी चाहिए। नियम इतने सख्त भी न हों कि नवाचार रुक जाए। हमें एक ऐसा संतुलन बनाना होगा, जो भारत को एआइ में अग्रणी बनाए और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। भारत के पास एआइ अपनाकर आउटसोर्सिंग अर्थव्यवस्था से ज्ञान महाशक्ति बनने का मौका है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं तो डिजिटल लोकतंत्र, समावेशी विकास और सतत भविष्य की दिशा में एआइ भारत का साथी बन सकती है। भविष्य एआइ बनाम मानव का नहीं, बल्कि एआइ के साथ मानव का होगा।

(लेखक एआइ एंड बियांड के सह-संस्थापक हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

ऊर्जा

समीक्षा और निंदा

समीक्षा और निंदा दो भिन्न अवधारणाएं हैं, जो अक्सर समाज में भ्रम उत्पन्न करती हैं। समीक्षा में सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, जबकि निंदा नकारात्मकता का प्रतीक है। जब हम किसी व्यक्ति के कार्यों की समीक्षा सकारात्मक और सुधारात्मक दृष्टि से करते हैं, तो वह अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रेरित होता है। माता-पिता, गुरुजन और सज्जन लोग हमेशा अपने प्रियजनों के विकास की दृष्टि से उनकी समीक्षा करते हैं।

समीक्षा एक दर्पण के समान है, जिसमें व्यक्ति को अपने संपूर्ण आचार-विचार की छवि दिखाई देती है। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति को अपने गुणों को विकसित करने में मदद करता है। समीक्षा एक सैद्धांतिक आक्षेप है, जो व्यक्ति के चिंतन और क्रिया-कलाप में दोषों का निवारण करता है। इसके विपरीत निंदा व्यक्ति केंद्रित होती है और नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। यह व्यक्ति को राग-द्वेष से प्रभावित कर हतोत्साहित और अवसादित कर देती है। निंदक हमेशा विवाद और अलगाव को जन्म देते हैं। समीक्षा सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि निंदा व्यक्ति पर। समीक्षा में सुधार की भावना होती है, जबकि निंदा में प्रहार का भाव। समाज में निंदा के कारण विद्वेष की भावना का विषवमन होता है, जिससे पारस्परिक संबंधों में दरार आती है। इसलिए हमें निंदा के स्थान पर समीक्षा को अपनाना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति के दोषों को देखकर उसमें सुधार चाहते हैं, तो उसकी समीक्षा एकांत में उसके साथ करनी चाहिए। इससे उसमें विद्वेष या हीनता का भाव नहीं आएगा। इससे आपके प्रति उसमें सहानुभूति का भी संवर्धन होगा। समीक्षा का यह तरीका एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका को भी उजागर करता है। हमें चाहिए कि हम अपने आस-पास के लोगों की समीक्षा करें, ताकि वे अपने गुणों को पहचान सकें और उन्हें विकसित कर सकें।

आचार्य नारायण दास

पारिवारिक संबंधों को सहेजता रक्षाबंधन

डा. मोनिका शर्मा

जीवन की यात्रा में भाई–बहन ही एक–दूसरे के साथ सबसे अधिक वर्ष साझा करते हैं

रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है। विवाह के बाद जब बहन ससुराल चली जाती है, तब यह डोर उसे मायके के आंगन से जोड़े रखती है। यह भाव न केवल बहन के बच्चों के जुड़ाव को पोसता है, बल्कि अभिभावकों को भी संबल प्रदान करता है। रक्षा सूत्र के रूप में बांधे गए इस मोह के धागे से भाई-बहन के बीच दूरियां नहीं आतीं। अपनी-अपनी जिंदगियां बसा लेने के बाद भी इस रिश्ते की स्नेहिलता और आत्मीयता को निभाने की समझ आज भी विद्यमान है। रक्षाबंधन के पर्व से जुड़े भावनात्मक पहलुओं में असीम स्नेह और कर्तव्यबोध समाहित है। बिखरते रिश्तों के इस दौर में संबंधों को संजीदगी से सहेजने और दृढ़ता से थामे रखने के सोच को बल मिलता है। यह रिश्ता बच्चों के लिए भौतिक और भावनात्मक सहारे का स्रोत होता है, जो उन्हें अकेलेपन और अवसाद से भी बचाता है।

आज की पीढ़ी पारिवारिक रिश्तों की उलझनों में व्यावहारिक और वैचारिक समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे में हमारे पारंपरिक पर्वों में आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी परेशानियों को समझने का एक सूत्र मिलता है। अध्ययन बताते हैं कि भाई-बहन के रिश्ते की मजबूती मानसिक दिशाहीनता और व्यावहारिक समस्याओं से बचाती है। परिवार में पोषण वाला यह जुड़ाव समस्या समाधान की भावना को भी बल देता है। ऐसे बच्चों में सामाजिक मोर्चे पर संघर्ष और अलगाव का स्तर कम देखने को मिलता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ मिसौरी के मानव विकास एवं परिवार विज्ञान विभाग की शोधकर्ता सारा किल्लोरेन के अनुसार, भाई-बहनों के साथ रिश्तों के माध्यम से लोग सीखते हैं कि दूसरों से कैसे व्यवहार किया जाए। भाई-बहन एक-दूसरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गहराई से प्रभावित करते हैं। उनमें सहयोग, नया सीखने की प्रक्रिया में संबल देने और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। भाई-बहन का रिश्ता बच्चों के व्यवहार, समायोजन और बेहतरी से जुड़े पहलुओं को अनोखे ढंग से आकार देने की क्षमता रखता है। एक अध्ययन में यह भी सामने आया है कि युवा अवस्था में भाई-बहन के रिश्तों की गुणवत्ता 65 वर्ष की उम्र में खुशहाल रहने के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक थी।

बच्चे स्कूल के बाद अपने भाई-बहनों के साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। यह समय माता-पिता और दोस्तों के साथ की तुलना में अधिक होता है। जीवन की यात्रा में भाई-बहन ही एक-दूसरे के साथ सबसे अधिक वर्ष साझा करते हैं। समझना कठिन नहीं है कि इस गहरे जुड़ाव की सामाजिक-पारिवारिक रिश्तों को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपरा और पारिवारिक धरातल से जुड़ा यह पहलू आज संबंधों को सहेजने वाला प्रगतिशील पक्ष प्रतीत होता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

गलती कर रहे हैं ट्रंप

'भारत की सामर्थ्य को समझे अमेरिका' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सृजनपाल सिंह ने अमेरिका के अहंकार के समक्ष कभी न झुकने वाले स्वाभिमानी भारत की सामर्थ्य को बखूबी विश्लेषित किया है। अमेरिका ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय भी पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखा और दुश्मन के 90 हजार से अधिक आत्मसमर्पित सैनिकों को युद्ध बंदी बनाकर पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। भारत के परमाणु कार्यक्रम को भी अमेरिका ने बाधित करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंकाया था। अबकी बार भी भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ की परवाह न करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को दो-टूक कहा है कि भारत दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, भारत की व्यापार नीति स्वतंत्र रहेगी। भारत से उलझ कर अमेरिका हर बार मात खाता रहा है और इस बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने अहंकार में वही गलती कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव में भारत अपने सदाबहार मित्र रूस से संबंध बिगाड़ने की गलती कभी नहीं करेगा। भारत, चीन और रूस के रिश्ते अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़ (उप्र)

प्रतिक्रिया

ड्रोन की बढ़ती भूमिका

आजकल विश्व में युद्ध की स्थिति में ड्रोन हमलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। हवाई और मिसाइल हमलों की तुलना में दुश्मन देशों पर ड्रोन हमले अधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी ड्रोन का व्यापक उपयोग हुआ, जहां पाकिस्तान ने चीन और तुर्किये से आयातित ड्रोन का इस्तेमाल किया, वहीं भारत ने अपने स्वदेशी निर्मित ड्रोन का सहारा लिया। हाल में, भारत ने एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के बजाय उसे निष्क्रिय कर बंदी बनाने में सक्षम है। यह 24 घंटे सीमा सुरक्षा, हवाई अड्डों और बिजली संयंत्रों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कार्यरत रहेगी। इसका मल्टीलेयर सिस्टम एक साथ कई स्थानों पर निगरानी करने और दोस्त एवं दुश्मन की पहचान करने में सक्षम है। पांच किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्य करने में सक्षम ड्रोन खतरे का पता लगाते ही तीन मिनट में दुश्मन के ड्रोन को धरती पर ले आता है। यह तकनीक भारत की स्वदेशी प्रणाली क्षमता को दर्शाती है।

मनमोहन राजावत ''राज'', नई सड़क, शाजापुर

राष्ट्र प्रथम

अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह विकासशील देशों पर दोहरी नीति अपनाकर उनकी अर्थव्यवस्था को कुचलने का प्रयास करे। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत का टैरिफ अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। आज का भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। भारत सरकार किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और डेरी उत्पादों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, जो कि ब्रिक्स का सदस्य है, ने कहा है कि वह ट्रंप से बातचीत नहीं करेगा और केवल मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग से बात करेगा। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो अमेरिका को चुनौती देती है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुतिन का भारत आने का कार्यक्रम और शी जिनपिंग का समर्थन, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था ढलान पर है, जबकि भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।